

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

9 मार्च, 2002

खण्ड-1, अंक 10

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, मार्च 19, 2002

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10)1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(10)15
स्थगन प्रस्ताव की सूचना/वाक आउटस	(10)23
वर्ष 2002-2003 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(10)36
वैयक्तिक स्पष्टीकरण	(10)45
श्री बंसीलाल एम.एल.ए. द्वारा	
वर्ष 2002-2003 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(10)46
वर्ष 2002-2003 के बजट की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(10)59
बैठक का समय बढ़ाना	(10)72
वर्ष 2002-2003 के बजट की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(10)73

बैठक का समय बढ़ाना	(10)76
वर्ष 2002-2003 के बजट की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान (पुनरारम्भ)	(10)76
विधान कार्य	(10)82
(i) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (अमेंडमेंट) बिल, 2002	
(ii) दि पंजाब पैसेजर्ज एंड गूड्स टैसे ान (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 2002	
बैठक का समय बढ़ाना	(10)85
विधान कार्य (पुनरारम्भ)	(10)86
(i) दि पंजाब पैसेजर्ज एंड गुड्ज टैक्से ान (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 2002	
(iii) दि ईस्ट पंजाब बार अवार्डज (हरियाणा अमेंडमेंट) बिल, 2002	

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार 19 मार्च, 2002

विधान सभा की बैठक विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बने हुई, अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान ने अध्यक्षता की।)

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैमबर्ज, अब प्र न होंगे।

Building of Civil Hospital, Ambala Cantt.

929. Sh.Anil Vij : Will the Minister of State for Health be pleased to state -

(a) Whether it is a fact that the building of Civil Hospital, Ambala Cantt. is in dilapidated condition; and

(b) if so, Whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new building for the said Hospital ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डॉ, एम, एल, रंगा):

(क) जी, नहीं।

(ख) प्र न ही उत्पन्न नहीं होता। लेकिन फिर भी दूसरी प्र न के जवाब में में माननीय सदस्य को कहना चाहूँगा कि अस्पताल के कुछ भाग का निर्माण कार्य विचाराधीन है।

श्री अनिल विल : अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही अच्छा दिन हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मंत्री जी ने अपने लिखित जवाब से हटकर एफरमेटिव जवाब दिया है। लिखित में तो जवाब न में आया था लेकिन मंत्री जी ने उससे हटकर एफरमेटिव जवाब दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह अस्पतरल 1959-60 में बना था और तब इसको खरैती अस्पताल के नाम से जाना जाता था। वहां डॉक्टर अच्छे होने के बावजूद बिल्डिंग की हालत हीर्ण-पीर्ण अवस्था में होने के कारण यह अस्पताल अपने खरैती अस्पताल की पोजीशन से ऊपर नहीं उठ रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता है। कि यह बिल्डिंग कब तक बन जाएगी और दूसरे इसके लिए क्या वहां पर किसी पैसे का प्रावधान किया गया है।

(डॉ, एम, एल, रंगा): अध्यक्ष महोदय, अम्बाला कन्टोनमेंट के अस्पताल को 1959 में कन्टोनमेंट बोर्ड के द्वारा बनाया गया था। हमारे हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने इसको 1973 में टेक ओवर किया था। इस अस्पताल का कुछ पार्ट जीर्ण-पीर्ण अवस्था में है। हमारे ब्लॉक में यूरोपियन कमिशन के तहत 20 लाख रूपया पी.पी.सैन्टर के लिए इयर मार्क किया गया है। हमारे सम्मानित सदस्य उसके मैम्बर है। जब वहां पर मीटिंग होगी तो ये वहां पर इस बारे में बात उठाये तो ज्यादा पैसा एलोकेट करवाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर स्वास्थ्य विभाग ने एकसरे ब्लॉक, एमरजेंसी ब्लॉक में पिछले दसवे मास में

मुरम्मत के लिए 54 हजार रूपये मंजूर करवाये है। वहां पर धोबी घाट के लिए सन् 2001 मे 74 हजार रूपये की मंजूरी दी गई है। इसके लिए टैन्डर हो चुके है और एक दो सप्ताह में इसका भी काम भुरु हो जाएगा। इसी के साथ वहां पर टी.बी. ब्लाक में ट्वायल्ट की रिपेयर की आव कता थी तो उसके लिए हमने एक लाख मंजूरी के लिए सरकार को लिख कर भेजा हुआ है। वह मंजूरी भी जल्दी आ जाएगी तो उसकी रिपेयर भी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमने पी.डब्ल्यू.डी. से पुछा कि उस हस्पताल के बारे में लोग कहते है। कि यह जीर्ण- र्ण अवस्था में है। तो इस बारे में आप अपनी रिपोर्ट हमे दो। उनकी रिपोर्ट हमारे पास आई तो उन्होने उस में लिखा है। कि एक तो वहां पर जो कार्यालय है। और दुसरा स्वास्थ्य का स्टोर है उसकी हालत जीर्ण- र्ण है। हमने उनको फिर से कहां है कि इनकी रिपेयर के बारे में फोरन एस्टीमेट भेजें। जब एस्टीमेट आ जाएगा तो हम उसको सरकार की मंजूरी के लिए भेज देंगे। इसके अलावा यूरोपियन कमी ान ने इस बात के लिए यह जिला छाटा है। यूरोपियन कमी ान से पी.पी सैन्टर के लिए 20 लाख रूपये आए हुए है और यह निर्माण कार्य के लिए है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्टाफ की बात है तो वहां पर 93 कर्मचारियों का स्टाफ स्वीकृत हैं और आज की डेट में वहां पर 92 कर्मचारियों का स्टाफ काम कर रहा है एक खाली पोस्ट है वह भी जल्दी भर दी जाएगी।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छा दिन है कि मंत्री जी ने एक और बिल्डिंग का निर्माण करने के बारे में बताया है। मुझे यह भी उम्मीद है कि जो बिल्डिंग जीर्ण-पूर्ण अवस्था में है उसको भी मंत्री जी जल्दी ठीक करवा देंगे क्योंकि उसके प्रोसैस आरम्भ कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जो निर्माण कार्य समय-समय पर अम्बाला कौन्ट के सिवल अस्पताल में हो रहे हैं वहाँ पर कहीं पर ब्लड बैंक बना दिया जाता है और कहीं पर कोई ऐमरजेन्सी वार्ड बना दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अम्बाला कौन्ट के बीच में यह अस्पताल है और बहुत ही सैन्ट्रल प्लेस पर लोकेटिड है उस अस्पताल की जो भूमि है वह बहुत ही सीमित है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आने वाले समय की जरूरत को मद्दे नजर रखते हुए, 20 या 30 सालों की जरूरतों को देखते हुए वहाँ के अस्पताल के लिए क्या कोई मास्टर प्लान बनाया गया है और क्या इस तरह के किसी मास्टर प्लान पर विचार करने का उनका इरादा है ? अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर आईन्दा से जो भी निर्माण हो चाहे वह किसी भी हैड से हो, वह उसी मास्टर प्लान के तहत होने चाहिए ताकि जो लैण्ड की मैनेजमेंट है वह वहाँ पर ठीक तरह से की जा सके। होता यह है कि अब भी वहाँ पर कहीं पर एक चीज बना दी जाती है, कहीं पर दूसरी चीज बना दी जाती है और कहीं पर तीसरी चीज बना दी जाती है और अगर कल को उस अस्पताल में कोई एक्सपेंशन करना पड़े तो उसका वहाँ पर कोई स्कोप नहीं रह जाएगा। इसी

तरह से अध्यक्ष महोदय, उस अस्पताल में तीन साल से अल्ट्रासाउंड की मीनिंग लगी हुई है लेकिन उसके लिए वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है इसलिए वह मीनिंग काम में नहीं आ रही है। मंत्री जी ने बताया है कि 93 पोस्ट उन्होंने वहां की भर दी है और अब केवल एक पोस्ट खाली है मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह वहीं पोस्ट खाली है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं ? अगर यह वही पोस्ट है तो मंत्री जी बताएं की इनको कब तक भर दिया जाएगा ? अगर वहां पर यह डॉक्टर की पोस्ट भर दी जाती है तो जो वहां पर अल्ट्रासाउंड मीनिंग लगी है उसका अम्बाला के मरीज फायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, अम्बाला जिले में जो यूरोपियन कमीशन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्य कर रहा है और सरकार ने वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की हालत सुधारने के लिए जो कदम उठाए हैं वह एक बहुत ही अच्छी बात है। अब हर जिले में लगभग 50 करोड़ खर्च किये जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि इस काम में डिले हो रहा है जबकि यह टाईम बाउन्ड प्रोग्राम था। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह प्रोग्राम कब तक पूरा हो जाएगा और कब तक अस्पतालों में बिल्डिंग का या दूसरे अन्य कामों को दूसरे कामों भुंरु कर दिया जाएगा?

डॉ. एम.एल. रंगा : अध्यक्ष महोदय,सम्मानित सदस्य ने तीन प्रश्न किये हैं। इनका पहला प्रश्न यह है कि क्या जरूरत से वृद्धि को देखते हुए अम्बाला के सिवल अस्पताल के लिए कोई मास्टर प्लान रखा गया है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, जब भी

सरकार इस तरह के मास्टर प्लान पर विचार करती है तो इन सभी मुद्दों पर ध्यान रखा जाता है। जब भी प्लान साईड की मीटिंग होगी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा और अम्बाला कैन्ट के अस्पताल के बारे में विचार किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने यह भी कहा कि अल्ट्रासाउंड की मशीन के लिए वहां पर डॉक्टर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि वहां पर 93 पोस्टस सैंकान हैं और इनमें से 92 पोस्टस पर लोग काम कर रहे हैं जबकि एक पोस्ट वहां अभी खाली है लेकिन इसका भी हमने समाधान निकाल रखा है। वहां पर यमुनानगर से एक डॉक्टर भेजा जाता है फिर भी सरकार वहां की एक पोस्ट को यथा शीघ्र भर देगी। तीसरा जो इनका प्रश्न यूरोपियन कमीशन के बारे में है। मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि मेरी तरह से इनको भी इस बारे में ज्ञान होना चाहिए क्योंकि ये भी उस यूरोपियन कमीशन सोसायटी के सम्मानित सदस्य हैं और हर मीटिंग में ये भी वहां पर विराजमान रहते हैं इसलिए जैसा ये चाहेगे उसी हिसाब से काम होंगे। इस सोसायटी में जिला परिषद् के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, नगर परिषद् के सदस्य और ब्लॉक समिती के चेयरमैन सब को सम्मिलित करके सबसे विचार करके काम किया जाता है। इसके अलावा भाहर के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनको भी इस सोसायटी में शामिल किया गया है जबभी इस सोसायटी की मीटिंग हो तो माननीय सदस्य उस मीटिंग के बारे में जानकारी ले और उसमें अपने विचार रखें। इनको ज्ञान

देने का और ज्ञान देने का अधिकार है इसलिए वहां पर जैसे कामों की जरूरत है ये वैसा ही काम करवाएं।

श्री सूरजमल : स्पीकर साहब, हमारे मुरथल गांव के अंदर एक बीस बेडज का अस्पताल चौधरी देवीला जी के वक्त में मंजूर हुआ था और हमारी पंचायत ने भी 70 हजार रुपये इसके लिए भर दिए थे। जब मुख्य मंत्री जी वहां गए थे तो इन्होंने भी इसके लिए इजाजत दे दी थी। पंचायत ने जमीन के बारे में रैजोल्यूशन बगैरा पास करके दे दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इसको 20 बेडज का अस्पताल बनाने का विचार है और अगर है तो यह कब तक इसके काम पूरा है जाएगा ?

डॉ. एम.एल.रंगा : स्पीकर सर, जैसे तो यह प्रश्न अम्बाला छावनी के अस्पताल के बारे में चल रहा था लेकिन मुरथल भी जी.टी. रोड पर है इसलिए मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूँगा कि पिछली बार विधान सभा में भी यह बात आयी थी हमने इसका ऐस्टीमेट बनवा लिया था, डिजाइन बगैरा बनाने का काम चल रहा है और मैं चाहूँगा कि जब चौधरी देवी लाल जी ने उसका फिनालान्यास किया हुआ है तो उसको हम यथा शीघ्र पूरा करवाने की कोशिश करेंगे।

श्री रमेश राणा : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि धरौण्डा जी.टी. रोड

पर स्थित है और वहां पर एक अस्पताल की जरूरत को समझते हुए 1991 में जब चौधरी भजन लाल जी की सरकार आई थी उस वक्त वहां पर चारदीवारी गई थी। तत्कालीन मंत्री कंबर राम परल सिंह चौधरी भजन लाल जी को नेकर वहां आए थे और वहां नींव पत्थर रखा गया था। वह नींव पत्थर 10-11 साल से वहां मौजूद है लेकिन आज तक वहां पर एक भी कमरे का निर्माण नहीं किया गया है। अभी पिछले दिनों आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घरौण्डामें 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम रखा था, उस कार्यक्रम में 30 बिस्तरों का अस्पताल वहां पर मंजूर किया था। मैं पूछना चाहूंगा कि कब तक इस का काम भुरू किया जाएगा और कब तक इस काम को पूरा करने की सरकार की योजना है ?

डॉ. एम.एल.रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 1995-1996 और 1997 या इससे पहले जो भी िनान्यास किए गए थे उस समय के 33 भवन हमारी सरदार ने पूरे करवाएं हैं। इसके अलावा 3 बड़े अस्पताल, 4 सी.एच.सी. और 9 पी.एच.सी. का निर्माण कार्य जारी है क्योंकि मुख्यमंत्री जी घरौण्डा में हां भर चुके थे और वहां पर 31 कनाल, 11 मरले भूमि 1995 में सरकार को दी हुई है। 1995, 1996, 1997 एवं 1998 के चार साल तक के समय में न नक्शे परस हुए न ऐस्टीमेट्स पास हुए। सन् 2000 में हमारी सरकार ने आते ही ऐस्टीमेट्स बनाकर डिजाइन बनवाए। जनसरी 2001में। करोड़ 15 लाख रुपये के ऐस्टीमेट्स आकर मंतूरी के लिए गए हुए हैं जब मंजूर होकर आ

जाएंगे जाक इनका निर्माण कार्य भुरु कर दिया जाएगा। फिलहाल वहां पर पी.एच.सी. काम कर रही है, पूरा स्टाफ है और काम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है।

श्री जसबीर मलौर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में चौड़मस्तपुर में काफी पुरानी सी.एच.सी. बनी हुई है और बरसात के दिनों में जब ज्यादा बरसात हो जाती है तो 2-2 फुट पानी वहां खड़ा हो जाता है और वहां पर फलड जैसी स्थिति हो जाती है। बरसात के सीजन में दो महीने तक यह सी.एच. लगभग बंद रहती है और जो डॉक्टर कालोनी में रहते हैं उनको भी पानी भरा होने की वजह से काफी दिक्कन होती है। क्या मंत्री जी डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पर मिट्टी डलवाने की कोई व्यवस्था करेंगे ताकि वहां पानी खड़ा न हो। वैसे मेरे हल्के में माजरी गांव में अभी मुख्य मंत्री जी व मंत्री जी 67 लाख रूपये की लागत से बनने वाली पी.एच.सी. का िालान्यास करके आए थे। मेरा अनुरोध है कि सी.एच.सी. चौड़मस्तपुर में मिट्टी डलवाने की कोई व्यवस्था करें।

डॉ एम.एल.रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि चौड़मस्तपुर प्राकामिक स्वास्थ्य केन्द्र में मैं स्वयं गया था वह वास्तव में काफी नीचे बनी हुई है और वहां बरसात के दिनों में पानी खड़ा हो जाता है। इस बारे में पंचायत से बात हुई थी और कहा था कि मिट्टी पंचायत डलवा दे

और उस पर जो फर्क वगैरह बनवाना होगा वह हम बनवा देंगे। पंचायत इस पर विचार कर रही हैं उसके बाद फर्क का काम हम विभाग के द्वारा करवा देंगे इसके अलावा वहां पर रिपेयर का भी कुछ काम था उसके लिए हमने सिविल सर्जन को कहा है कि प्रस्ताव भेज दें, पैसा हम मंजूर कर देंगे।

श्री रामबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गुड़गांव एक महानगर है और आए दिनों वहां आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं इसके लिए वहां जनरल होस्पिटल में कब तक आई.सी.यू और बर्न्ट वार्ड की व्यवस्था हो जाएगी।

डॉ. एम.एल. रंगा: अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का होर्ड प्रस्ताव अभी सरकार के पास नहीं आया है। मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूँगा कि वे अस बारे में लिखकर दे दें ताकि इस पर विचार किया जा सके और आगे आने वाले समय में इस बाने प्रयास किया जा सके।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि मैंने बिल्डिंग की मास्टर प्लान वाली बात कही थी मैंने बिल्डिंग बनाने की बात नहीं कही थी। मेरा क्वैश्चन यह था कि जो 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत अम्बाला सदर में तोपखाना बाजार में एक डिस्पेंसरी बनाने के बारे में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आवासन दिया

था और जो 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत घोशणाएं की जाती हैं वे पूरी की जाती हैं। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि वहां पर डिस्पेंसरी तो बनेगी। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे विभाग को आदे । देकर इस काम को एक्सपेडाइट करवायेंगे क्योंकि वहां कन्टोमेंट एरिया है इसलिए डिस्पेंसरी की बड़ी असव यकता है।

श्री अध्यक्ष : विज साहब आप बैठिये।

डॉ.एम.एल.रंगा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बिल्डिंग की मास्टर प्लान की बात की है वे मुझे बता दें ताकि उस पर विचार किया जा सके। दूसरा जैसा कि माननीय सदस्य ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम का जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो घोशणाएं की जाती हैं वे हमारे पास आती हैं उसके बाद उनके नॉर्म्ज को देखा जाता है और जो भी घोशणा नॉर्म्ज पूरे करती है उस पर जल्दी कार्यवाही भुरू हो जाती है। सम्मानित सदस्य उस घोशणा के बारे में हमें बता दें हम उसको दिखवा लेंगे और अगर नौर्म्ज पूरे करती होगी तो उस पर जल्दी कार्यवाही की जायेगी।

चौ. नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि कौनासी गांव की सी.एच.सी. की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है लेकिन अभी

तक वहां पर स्टाफ नहीं बैठता है कृपया मंत्री जी बतायें कि वहां पर स्टाफ कब से बैठना शुरू करेगा। अध्यक्ष महोदय, पल्स पोलियो अभियानके दौरान माननीय मंत्री जी बहादूरगढ़ गये थे तब भी मैंने इनको सिविल होस्पिटल बहादूरगढ़ की एक 50-60गज की लम्बी दीवार दिखाई थी जोकि बननी बाकी है उसको मंत्री जी कब तक बनवा देंगे ताकि होस्पिटल में पण्डित वगैरा न घुस सकें।

डॉ. एम.एल.रंगा : अध्यक्ष महोदय, सिविल होस्पिटल बहादूरगढ़ की दीवार बनाने के बारे में एस्टिमेट हमारे पास आ चुका है और इस बार मरम्मत के काम के लिए हमने स्वास्थ्य विभाग के बजट में साढ़े पांच करोड़ रूपयों का प्रावधान किया हुआ है उसकेतहत इस दीवार को बनवा दिया जायेगा। दूसरे जो सी.एच.सी.की बात माननीय सदस्य ने की है उसके बारे में ये मेरे से अलग से बात कर लें, उसको देखकर उस बारे में क्या किया जा सकता है इनको बता दिया जायेगा।

Construction of Roads

851. Shri Sher Singh : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads in Julana constituency :-

(1) Igrah to Vuradehr via Buana;

(2) Kharianty to Buana; and

(b) of so, the time by which the said roads are likely to be constructed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) (1) हां, श्रीमान जी।

(क) (11) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) इस सड़क के पूर्ण होने का समय नहीं बतसया जा सकता क्योंकि यह एक दोहरी लिंक है था वरीयता में नीचे है।

आई.जी. (रिटायर्ड) श्री भोर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि मेरे हल्केजुलाना में मण्डी है उस मण्डी को रोहतक रोड़ से एक सड़क आती है। वहां पर पहले कमेटी होती थी तब तो यह सड़क बनी हुई थी। अध्यक्ष महोदय, यह सड़क लगभग 500 गज की है। आज इस सड़क की खस्ता हालत है और जब वहां पर बारिश आती है तो लोगों को मण्डी में और बाजार में आने के लिए बड़ी दिक्कत पैदा आती है। क्या सरकार इस 500 गज की सड़क को बनवाने का कार्य करेगी। क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि 500 गज के टुकड़े के कारण लोगो को बाजार में आने के लिए तकलीफ हों। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इस सड़क को जल्दी बनाया जाये।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : स्पीकर सर, जिस प्रकार से माननीय सदस्य भोर सिंह जी ने केवल 500

गज की सड़क जी बात की है यह ज्याया लम्बी सड़क की बात नहीं है इसको हम लोगों की सूकवधा के लिए जल्दी बनवाने का कार्य करेंगे। इसी प्रकार स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने लिखित प्र न में जिस सड़क की बात इन्होंने कही है वह 9.88 किलोमीटर की है उस पर 14.48 लाख रूपये का कार्य को चुका है और उस पर 90लाख रूपये और चाहिए। इसी प्रकार एक और सड़क 4.65 किलोमीटी की है स्पीकर सर, यह ठीक है इन दोनों सड़कों को तो जब धन उपलब्ध होगा तभी बनाया जायेगा परन्तु 500 गज वाली सड़क को प्राथमिकता के आधार पर बनाया जायेगा। स्पीकर सर, इतना ही नहीं माननीय सदस्य अच्छे ओहदे पर रहे है मेरी इनसे बात भी हुई है और 3 नई सड़के मार्किटिंग बोर्ड इनके क्षेत्र में बना रहा है। भोरसिंह जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बैठे-बैटे हां भी भर रहे है कि विकास के कार्य वास्तव में हो रहे है। मैंजो ऐसे सीनियर मैम्बर को यह कहूंगा किव यह भी मानें कि आपके क्षेत्र में और भी बहुत काम पी.डब्ल्यू.डी. की तरफ से हुए हैं और इसी प्रकार से जहां सड़को को बनाने के काम किए गए हैं वहीं उनकी रिपेयर के भी बहुत काम किए गए है, उनको चौड़ा और मजबूत बनाने और उनके रख रखाव के भी काम किए गए हैं। इसी प्रकार से वर्ष 2001-2002 में इनके क्षेत्र में 2 करोड़ 4 लाख रूपये खर्च किए गए हैं। बरवाला जींद रोड पर भी काम किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास हरियाणा में हुए विकासों से सम्बन्धित किताब है इसके लिए आत मैं आदरणीय चौणरी ओम प्रका । चौटाला को बधाई दंना चाहूंगा, इनके साथ ही मैं कृशि मंत्री

जसविन्द्र सिंह सन्धू और मार्किटिंग बोर्ड के चेयरमैन श्री बलवन्त हसंह मायना को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने कि आज इतने विकास के काम करवाकर इस किताब को बनवाया है। ये किसी भी क्षेत्र के बारे में पूछेंगे तो मैं इनको इस बुक में से पढ़कर बताऊंगा। (तोर एवं व्यवधान) अगर ये हरियाणा के विकास की किताब को गौर से पढ़ेंगे तो इनको विकास के कार्य होते हुए दिखाई देंगे।

केप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, रिवाड़ी जिले में कोई सड़क नहीं बनाई गई है। (तोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : केप्टन साहब, जो पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं वहां विकास के ज्यादा कार्य होते हैं चाहे तो आप भजन लाल जी से पूछ लें। (तोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी. पी.एस. से कहना चाहूंगा कि मेरा सवाल पर्टीमुलर जुलाना विधानसभा क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं है बल्कि मैं चाहूंगा कि वे अन्य विधानसभा क्षेत्रों के बारे में भी 1999 से अपटू डेट जो नई सड़कें बनाई गई हैं या सड़कों की रिपेयर की गई है उनका पूरा ब्यौरा दें। विशेषकर आमदपुर विधानसभा क्षेत्र, रोहतक में किलोई, किसार में बरवाला और रिवाड़ी, कालका और यमुनानगर में कितनी नई सड़कें बनाई गई हैं और कितनी सड़कों की रिपेयर की गई है। (तोर एवं व्यवधान)

श्री राम परल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मेरे साथी कैप्टन अजय सिंह यादव, जय प्रकाश बरवरला और कृष्ण परल जी, जो इस समय बैठे नहीं हैं, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में छात्र रहे हैं, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, ये जानबूझकर मुझे टोकते हैं। मैं इनको बताना चाहूँगा कि सड़को की रिपेयर के बहुत ज्यादा काम किए गए हैं। रिवाड़ी में 10 करोड़ रुपये के सड़कोकी रिपेयर के काम किए गये हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव :*****

श्री अध्यक्ष :कैप्टन साहब जो रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाएफ बेवजह बोलने वाले का कोई रिकॉर्ड न किया जाए।(गोर एवं व्यवधान)

श्री राम परल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आदमपुर में 22 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है।(गोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, रिवाड़ी में 10 करोड़ रुपये की नागत से सड़को की रिपेयर की गई है।(गोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please sit down,जय प्रकाश जी प्लाज आप बैठ जायें। (गोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप जिस चेयर पर बैठें हैं यह बड़ी पाक चेयर है। आपको ऐसे नहीं करना

चाहिए किहम जो कुछ कहें वह रिकॉर्ड न किया जाये और सता पक्ष के भाई कुछ भी कहते रहें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर अपनी रिप्लाइ दे रहे हैं प्लीज आप बैठ जायें और रिप्लाइ ध्यान से सुनें।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, आदमपुर में 22.83 कि.मी. नई सड़के बनवाई गई हैं और बरवाला में 35 कि.मी. नई सड़के 2.65 करोड़ रुपये की लागत से बनवाई गई हैं।(गोर एवं व्यवधान)

चौ. जय प्रकाश : स्पीकर सर, *****

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी जो कुछ कह रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाये।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, बेरी में 12.70 कि.मी. नई सड़के बनाई गई हैं।(गोर एवं व्यवधान) किलोई में 43 कि.मी. नई सड़के बनाई गई हैं जिन पर 2.47 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। पलवल में 30 कि.मी. की सड़के 1.44 करोड़ रुपये की लागत से बनवाई हैं।(गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब प्लाज बाप बैठें। मंत्री जी रिप्लाइ दे रहे हैं उसके बाद आप अपनी बात कहना।

श्री रामपरल माजरा : स्पीकर सर, इसी तरह से तो गाम में 17 कि.मी. की सड़क के एक करोड़ रुपये की लागत से बनवाई गई हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माजरा साहब सारी लिस्ट पढ़कर क्यों सुना रहे हैं ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं लिस्ट नहीं पढ़ रहा बल्कि जो प्र न पूछा गया है उसी के बारे में बता रहा हूँ।(गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, प्लीज आप बैठें।

डॉ.बि.ान लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको मालूम है कि आज के दिन हरियाणा प्रदेश में हर गांव को किसी न किसी सड़क से नहीं जोड़ा गया है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 'सरकार आपके द्वार' के दूसरे फेस के तहत इस सड़क को बनाने की मंजूरी दी थी लेकिन अब सरकार ने एक भाव यह लगा दी है कि जहां पर रोड बनना है गांव वाले वहां मिट्टी डाल दें और उसको पक्का सरकार करवा देगी। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उस गांव में 100 के करीब घर हैं और सभी हरिजन मजदूर हैं। वे लोग मिट्टी डलवाने की हालत में नहीं हैं इस बारे में मैं सी.पी.सी. साहब से जानना चाहूंगा कि क्या उस गांव में मिट्टी डलवाने और उस पर सड़क बनाने का काम सरकार करवायेगी ?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, लोगों की जरूरत को देखते हुए 'सरकार आपके द्वार'के दूसरे फेस में यह प्रावधान किया गया था कि बैनीफियरिज अगर मिट्टी डाल देंगे तो उस सड़क को पक्का करने को सरकार प्राथमिकता देगी। मैं मेरे माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि स्व-रोजगार योतना के तहत ज्यों ही पैसा आयेंगा हम जहाँ भी इस तरह की सड़क नहीं होगी वहाँ मिट्टीभी पंचायती राज डिपार्टमेंट से डलवायेंगे और सड़क पक्की करवायेंगे ।

श्री रमे । कुमार खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी.पी.एस. साहब से जानना चाहूँगा कि पहले मार्किटिंग बोर्ड से बनवानी मंजूर की थी लेकिन मंख्य मंत्री जी ने जब दोबारा दरबार लगाया तो इस सड़क को बतायेंगे कि यह सड़क कब तक बना दी जायेगी ?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरे माननीय साथी अलग से नोटिस दे दें, इनको बता दिया जायेगा।

श्री धर्मबीर सिंह : स्पीकर सर, नाबार्ड, हुडको और कई तगहों से लोन लेकर के सड़को का काम चल रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि भिवानी से चण्डीगढ़ आते वक्त रास्ते में भिवान से जींद का रास्ता बहुत ही खराब हैं। यह 65 किलोमीटर का फांसला है और इस फांसले को सड़क खराब होने की वजह से अढ़ाई घण्टे से

पहले तय नहीं किया जा सकता। मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि भिवान से जींद तक जो सड़क आमी है असको कब तक, ठीक करवा किया जायेगा। इसी प्रकार से तो ताम से भिवानी तक की जो सड़क है वह भी बहुत ही खराब है। इस सड़क से गाड़ी द्वारा एक किलोमीटर का फांसला भी तय नहीं किया जा सकता। मैं बताना चाहूँगा कि इस सड़क की इतनी बुरी हालत है कि इस पर पैदल चलना भी मुश्किल है। इसी प्रकार से एक सड़क सुंगरपुर से देवराला है वह भी बहुत खराब है। स्पीकर साहब, मैं बापके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि इन सड़को कब क बना दिया जायेगा ?

श्री राम पाल माजरा : सर, भिवानी से जींद वाली जो सड़क भाई धर्मवीर जी बता रहे हैं, इसको हमने वर्ष 2002-03 के कार्यक्रम में लिया हुआ है। इस सड़क पर 1 करोड़ 90 लाख रुपये खर्च होंगे। मैं माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि इसको 2003 तक ठीक कर दिया जायेगा। यह इनकी बात ठीक है कि भिवानी से जींद तक तो आने में वाकई दिक्कत है लेकिन जींद से चण्डीगढ़ आने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो अनको सरकार का धन्यवाद करना चाहिए।(विधन)

श्री भगवान सहाय रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि मार्किटिंग बोर्ड और पी.डब्ल्यू.डी. अर्थात् दोनों द्वारा सड़के बनायीजा रही हैं इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है मैं सी.पी.एस. साहब की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पहले

जब चौधरी देवी लाल जी की सरकार 1987-91 के दौरान थी उस वक्त मेरे हल्के के अन्दर नांगल जाट से अन्धोप और बहिन से सेवली, सेवली जो मेरा अपना पैतृक गांव भी है, तक वहां पर उस वक्त कार्किटिंग बोर्ड द्वारा 2 सड़के बनाई गई थी। इन सड़कोको बने हुए आज 12 वर्ष हो चुके हैं। इन 12 वर्षों के दौरान इन दोनो सड़को की भी मरम्मत नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से सी.पी.एस.साहब से जानना चाहता हूँ कि क्या वे सड़को की मरम्मत करवायेंगे ?

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, जब प्रदे 1 की सता चौधरी बोम प्रका 1 चौटाला जी ने संभाली थी उस वक्त तक सड़को का ताना-बाना लगभग पूरी तरह से टूट चुका था। मैं अपने ऑनरेबल साथियों को जो यहां पर बैठे हुए हैं, मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मौजदा सरकार ने सता में आने के बाद नयी सड़के भी बनवाई हैं और पुरानी सड़को की रिपेयर आदि भी की गई है। इस बात को हमारे कई साथियों ने भी जिनमें भाई जगबीर सिंह जी, भाई भोर सिंह जी व धर्मपाल जी आदि ने भी माना है कि सड़को पर काम हुआ है कुछ लोगों ने तो सरकार की मुखालफत करने वास्ते केवल मुखालफत ही करनी है चाहू काम हुए हो या नहीं हुए हों केवल मुखालफत ही करनी है। स्पीकर साहब, हमारी सरकार ने सभी सड़को की रिपेयर का डिज्यूल बनाया हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि सारा सदन सरकार को बधाई दे कि सड़कों की रिपेयर के लिए हमारी स्पीड यू की यू

बनी रहें। अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भाई जसविन्द्र सिंह संधु जी बैठे हैं, इन्होंने कार्किटिंग बोर्ड के माध्यम से न जाने कितनी सड़कों को रिपेयर करवाया है और न जरने कितनी नयी बनायी गई है। (विधन) बाप लोग कह ही नहीं रहे कि सड़कों का काम हुआ है। (विधन) कैप्टन साहब भी मेरी तरफ घूर-घूर कर देख रहे हैं। जो सच्चाई है उसको आपको मानना चाहिए। (विधन) जब दूसरे साथी मान रहें हैं तो आपको भी मानने में क्या दिक्कत है। भगवान सहाय रावत जी ने पूछा है कि जो सड़क इनकी मार्किटिंग बोर्ड द्वारा बनायी गई थी उसको रिपेयर करवा जायेगा नहीं तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये दो सड़को की एक दो किलोमीटर की रिपेयर की बात कर रहे हैं, हम तो सारे हरियाणा की सड़को को रिपेयर कर रहे हैं तो फिर यह एक-दो किलोमीटर सड़क की तो बात ही क्या है।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी.पी.एस. साहब से जानना चाहता हूँ कि मेरे जिला सोनीपत में और सोनीपत भाहर में मार्किटिंग बोर्ड द्वारा कितनी सड़कें बनाई गई है।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इतनी लम्बी चौड़ी लिस्ट है इसमें से ढूँढने में समय तो लगता ही है अन्हें थोड़ा इत्मीनान और सब्र तो रखना चाहिए (विधन) स्पीकर सर, अगर ये कहेंगे तो मैं इनके यहां पर जो-2 काम हुए हैं उनके बारे में भी सारी बात खोल कर बता दूंगा (विधन) पिछली सरकार के टाइम

की जो सड़के टूटी हुई थी वे भी सारी इनको भूल गई हैं इनके वक्त कोई सड़क तो बनी ही नहीं थी और सारे हरियाणा को यह मार कर गए थे।(विधन)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब और जय प्रकाश जी, आप बीच में अस प्रकार से न बोलें, आप बैठे-बैठे बीच में बोल रहे हैं यह ठीक नहीं है। आप इस प्रकार से रनिंग कमेंट्री न करें।(विधन) मैं कल से आप लोगों के लिए पान का प्रबन्ध कर दूंगा(हँसी) मंत्री जी, दीवान साहब के सवाल का जवाब दें।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, बरोदा की 3 सड़के रिपेयर की गई हैं। इसी प्रकार से गोहाना की 6 सड़के, कैलाना की 14 सड़के, राई की 14 सड़के और रोहट की 5 सड़के रिपेयर की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मैं सोनीपत जिले की सड़को की रिपेयर की बात बता रहा था और जो सड़के मार्किटिंग बोर्ड बनाता है उनमें भाहन की सड़के नहीं आती हैं।

श्री देवराज दीवान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सी.पी.एस. महोदय से यह जानना चाहूँगा कि जो गांवों वाले लोग भाहरों में आएंगे वेकहां से आएंगे (विधन)

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, माननीय सदस्य जो सोनीपत की अन्य सड़कों के बारेमें बात कर रहे हैं बरोदा की 3 सड़के, गोहाना की 6 सड़के, हसनमुर की 2 सड़के, कैलानाकी 14 सड़के, महम की एक सड़क, राई की 14 सड़के और रोहट की 4

सड़कें सोनीपत की 9 किलोमीटर की सड़कें हैं जिन पर 74 लसख रूपयें की राशि खर्च की गई है।

Girls College, Hisar

875. Sh. Puran Singh Dabra : Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government Girls College at Hisar, if so, the time by which it is likely to be opened ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ. बहादुर सिंह) : हाँ, श्रीमान् जी। भवन का निर्माण होते ही महाविद्यालय में शिक्षण कार्य आरम्भ हो जायेगा।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि इस महाविद्यालय की बिल्डिंग कब तक बन जाएगी क्या इसके लिए कोई टाइम लिमिट रखी गई है कि इसमें क्लासें कब तक चालू कर दी जाएंगी ?

चौ.बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसार में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। राजकीय महाविद्यालय, हिसार में पढ़ने वाले छात्रों की मूल संख्या 2824 है जिसमें से 1201 लड़कियां हैं छात्रों की इतनी बड़ी संख्या

को ध्यान में रखते हुए हिसार में कन्या महा विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए 1996 में पंजाब शासन विभाग द्वारा 29 एकड़, 7 कनाल, 15 मरले भूमि शिक्षा विभाग को सीनान्तरित कर दी गई है। इस कन्या महाविद्यालय का िलान्यास भी किया जा चुका है। भवन निर्माण उपायुक्त, हिसार द्वारा इस बारे गठित कमेटी द्वारा किया जाना है। राजकीय कन्या महाविद्यालय, हिसार के भवन के 3 विंगज के लिए भवन योजना उप वास्नुकार हरियाणा द्वारा तैयार किए गए हैं क्योंकि भवन निर्माण के लिए सरकार की काफी ज्यादा धनराशि खर्च होगी इसलिए केवल एक कवंग के निर्माण विभाग द्वारा दो करोड़, 47लाख, 48 हजार रूपये का अनुमान दिया गया है। अध्यक्ष महोदय उपायुक्त हिसार ने यह भी सूचित किया है कि राजकीय कन्या महाविद्यालय, हिसार के एक विंग के लिए जनता द्वारा 52 लाख रूपये की राशि एकत्रित की गई है और निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए सरकार से 105 लाख रूपये की राशि निर्धारित करवाई जा रही है। भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही राजकीय कन्या महाविद्यालय में ििक्षण कार्य आरम्भ हो जाएगा।

श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह तानना चाहूँगा कि कया इन्होंने इसके लिए कोईसमय निश्चित किया है, इस बारे में मंत्री जी ने जवाब में नहीं बताया है।

चौ.बहादुर सिंह : समय तो यही निश्चित है कि बिल्डिंग जैसे ही पूरी हो जाएगी उसी दिन कन्या महाविद्यालय चालू हो जाएगा।

राव इन्द्रजीत सिंह : श्री पूर्ण सिंह डाबड़ा : स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने प्रश्न संख्या 875 के जवाब में हिसार के अंदर कॉलेज खोलों की मंजूरी जारी की है। इस बारे में इन्होंने कहा है कि जब बिल्डिंग बन जाएगी उस दिन से कॉलेज भूखंड हो जाएगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जहां पर बिल्डिंग अभी नहीं बनी है वहां पर तो ये कॉलेज भूखंड करने की मंजूरी जारी कर रहे हैं लेकिन कनीना के अंदर गांव वालों ने पने पैसे खर्च करके 18-20 कमरे बना दिए हैं तो क्या ये वहां पर कॉलेज भूखंड करने के लिए एन.ओ.सी.ग देने का कष्ट करेंगे ?

चौ.बहादुर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की और हमारी सभी की यही मंजूरी है कि लड़कियों की शिक्षा की तरफ खास ध्यान दिया जाए और हिसार के अंदर लड़कियों का कॉलेज खोलने की बात है। (गौर एवं व्यवधान)हिसार के अंदर 1200 लड़कियां हैं जोकि महाविद्यालय के अंदर पढ़ रही हैं उनका अलग कॉलेज खोलना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कनीना की बात है, तो वहां से हमारे परस कोई प्रस्ताव नहीं आया है। अगर वहां से कोई प्रस्ताव आएगा तो उस बारे में भी एग्जामिन करके विचार कर लिया जाएगा।

Construction of Roads

1003. Shri Daryao Singh Rajoura : Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the roads from Jhajjar to Gudyani and from Bus Stand, Kulana to Lohari in District Jhajjar ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्री मान् जी, झत्तर से गुडयानी तथा बस-अड्डा कुलाना से लोहारी पक्की सड़कें पहले ही निर्मित है।

श्री दरियाव सिंह राजौरा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जिन सड़कों का मैंने जिक्र किया है ये चौधरी देवी लालन जी के समय की बनी हुई है और उनके बाद चौधरी भजन लाल जी और चौधरी बंसी लाल जी की सरकार आई थी। उनके वक्त में उस सड़क पर रिपेयर का कोई काम नहीं करवाया गया था। आज वह सड़क खंडहर हो गई हैं। यह जो सड़कें बनाने के लिए केन्द्र की स्कीम आई है मया उसके तहत उस सड़क को रिपेयर करवा दिया जाएगा।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में ही उन सड़कों की रिपेयर नहीं करवाई गई थी और वह खंडहर बन चुकी है। इनको बताना चाहूँगा कि जिन सड़कों के बारे में इन्होंने कहा है केन्द्रीय सड़क कोर्स की स्कीम

के तहत दोनों सड़कों की मरम्मत करवाने का प्रस्ताव है और दोनों की रिपेयर करवा दी जाएगी।

श्री राजे । सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, इस सररोर के आने के बाद यह बात ठीक है हरियाणा में सड़कों के निर्माण और रखरखाव के कार्य को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए निश्चित रूप से यह सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन मैं दापके माध्यम से माजरा साहब का ओर सारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हिन्दुस्तान में हरियाणा प्रदेश ही एक ऐसा प्रथम प्रदेश है जहाँ पर हर भाहर आर हर गांव एक लम्बी चौड़ी सड़कों के जाल से जुड़ा हुआ है। मंत्री जी, आज सड़कों को बनाने के लिए जो लेटस्ट टेक्नोलोजी है क्या उस टेक्नोलोजी को सड़क के निर्माण करने में आडप्ट किया गया है। पिछली सरकारों के वक्त मेरी बल्लबगढ़ कांस्टीचुएंस में ही बना है। उसको बनाने के लिए जो मीनरी आती थी वह 20-20,25-25 पहियों वाले बहुत लम्बे चौड़े ट्रालों से आती थी। इसके अलावा मोहना जो यमुना का ब्रिज बनाया जा रहा है। वहाँ पर जो पुरानी सड़कें हैं उनकी चौड़ाई कम है और जो वहाँपर सड़क बनाने के लिए मैटीरियल डालते हैं वह कम डाला जाता है। मैं माजरा साहब से विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि क्या मेरे क्षेत्र की सभी सड़कोंकी आज जो लेटस्ट पोर्जी है वह मंगवाकर स्पेसली रिपेयर करवाएंगे। इसके अलावा हाई-वे पर जो मैटीरियल डाला जाता है उसकी लेयर पतली डलती हैं और जब वहाँ पर भारी वाहन आने

जाते हैं जो वह सड़क जल्दी टूट जाती है अब जैसे चंदावली से मुखायपुर मजेंड़ी जाएं तो वह जो भी वाहन वहां पर 5 किलोमीटर की स्पीड से भी नहीं चल पाता है। क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि अति गीघ्र वहां पर भी बढ़िया मैटीरियल का प्रयोग करके सड़क बनवाएंगे।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन्होंने कहा है कि क्या सड़कों को बनाते वक्त माडर्न टेक्नोलोजी आडप्ट की गई है। स्पीकर सर, यह ठीक है कि सड़क बनाने के लिए बैन्स्टी आफ वहीकल्ज देखी जाती है। नै नल हाई-वे, स्टेट हाई-वे और जो भी चूसी सड़कें होती हैं उनको अलग-अलग टेक्नोलोजी से बनाया जाता है। जहां पर ज्यादा व्हीकल्ज का आनाजाना है वहां पर सड़क अलग टेक्नोलोजी से बनाई जाती है। जहां पर नै नल हाई-वे है, स्टेट हाई-वे है, डिस्ट्रिक्ट हाई-वे हैं और चूसरी सड़कें हैं उन सब को अलग-अलग टेक्नोलोजी से बनाया जाता है और जिस प्रकार इन्होंने स्पैसिफिक तरीके से कहा है कि यं सड़कें बनायीं गयीं थीं लेकिन फिर से वे टूट गयीं। स्पीकर सर, इसके लिए हम नये सिरे से ऐग्जामिन करवा लेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहां-जहां पर ज्यादा व्हीकल्ज का आना जाना है वहां पर सड़कों को और मजबूत करें और हमने ऐसा किया भी है। बिसला जी इस बात के च मदीद गवाह भी हैं क्योंकि जितनी सड़कें इनके इलाके की रिपेयर की गयीं हैं एवं बनायीं गयीं हैं वह भायद एक रिकॉर्ड है। अगर मैं उनके बारे में

एक—एक करके बताऊँगा तो यह कहेंगे कि मैंने समय ले लिया, ठाइम खर्च कर दिया। यह ठीक नहीं रहेगा।(विधन)

श्री मती सरिता नारायण : स्पीकर सर, मेरे हल्के के अंदर कुछ सड़कें मार्किट कमेटी बना रही है लेकिन वह आज भी अधूरी पड़ी हुई है उन पर कहीं पर तो केवल रोड़ी ही पड़ी है और कहीं पर केवल मिट्टी पड़ी है। मैं इस बारे में कई बार गुहार लगा चुकी हूँ लेकिन फिर भी वे सारी सड़कें अधूरी है। मेरा इस बारे में एक क्वै चन भी था जो लगा नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि कलानौर से पिलानातक की जो सड़क टूटी हुई है वह कब तक बन जाएगी ? इसी प्रकार से कलानौर बस स्टैंड के पास वाली जो सड़क है वह बार—बार तारकोल से बनायी जाती हैलेकिन वह बार—बार ही टूट जाती है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करना चाहूँगी कि इस सड़क के वहां के थोड़े से टुकड़े को तारकोल के बजाए सीमेंट से बनवा दें। अगर ऐसा हो जाएगा तो यह सड़क टूटेगी नहीं। स्पीकर सर, यह मेरी उनसे पर्सनल रिक्सेस्ट है। इसी तरह से मार्किट कमेटी द्वारा बनने वाली सारी सड़के अधूरी हैं उनको भी बनवाया जाए।

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, बहन जी ने जो प्र न किया है और कहा है कि सड़कें अधूरी हैं यह ठीक है। हम बहुत—सी सड़क कई—कई किलोमीटर की बनाने जा रहे हैं इसलिए वे सारी सड़के एकदम से नहीं बनायी जा सकेंगी। हजारों

किलोमीटर की सड़कें बन रही हैं। पहले इन सड़कों पर मिट्टी डालते हैं। अगर एक रैनी सीजन इनके ऊपर से निकल जाए तो इनकी बेहतरीन माना जाता है उसके बाद मैटल वर्क होता है और उसके बाद पहली और दूसरी लेयर पड़ती है इस तरह के एक सड़क के बनाने में एक या डेढ़ साल जरूर लग जाते हैं। स्पीकर सर, पहले फेज में जितनी भी सड़कें बनाने की धोशणा की गयी थी वह सब इस वित्त वर्ष में पूरी कर ली जाएगी और उनको चमका दिया जाएगा। हम हरियाणा प्रदेश की सड़कें इसी प्रकार से बनाते रहेंगे।

Repair of Roads

1056.Smt.Anita Yadav : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that water is accumulated on the road from Kosli station to Dahina passing between Nahrugarh in Salhawas constituency; if so, the time by which the said road is likely to be re-constructed and repaired ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : गांव नेहरूगढ़ में वर्षा के दौरान और वर्षा के बाद तथा साथ लगते मकानों के गंदे पानी के बहाव के कारण सड़क पर पानी एकत्रित हो जाता है। इस सड़क के इस भाग की मरम्मत पहले ही प्रगति पर है। मरम्मत का कार्य 31-3-2003 तक पूर्ण होने की संभावना है।

श्री मती अनीता यादव : स्पीकर सर, मंत्री जी द्वारा हाउस को इस तरह से गुकराह करना अच्छी बात नहीं है। *****

श्री अध्यक्ष : इनकी यह झूठ बोलने वाली बात रिकॉर्ड न करें। अनीता जी, आप सवाल पूछेंगी या बैठना चाहेंगी। आप भाषण मत दें बल्कि आप सवाल पूछें।

श्री मती अनीता यादव : स्पीकर सर, इन्होंने अपने रूलज बना लिए और अधिकारियों ने अपने रूलज बना लिए। होता यह है कि जब मुख्य मंत्री जी कही पर जाते हैं तो केवल वहां-वहां की सड़कों के गड्डों को मिट्टी से भर दिया जाता है और आंखों में धूल झोंक दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछें।

श्री मती अनीता यादव : स्पीकर सर, जब मुख्य मंत्री जी को झड़ौदा साल्हावास रूट से जाना था तो अधिकारियों ने उनका वह रूट चेंज कर दिया और उनको वाया नादड़ निकालकर ले गए क्योंकि झड़ौदा-साल्हावास रूट की सड़क टूटी हुई थी। दूसरे रूट के भी गड्डे मिट्टी से भर दिए गए। इस तरह से वहाँ पर अधिकारियों का यह हाल है और यहाँ पर मंत्रियों का यह हाल है जोकि ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अनीता जी, रूट बदलना या न बदलना प्रशासन का काम है यह काम आपका नहीं है। आप केवल सवाल पूछें।

श्री मती अनीता यादव : स्पीकर सर, मंत्री जी द्वारा हाउस में जो बता दिया जाता है कि सड़कें बन रही हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। (गोर एवं व्यवधान) मंत्री जी ने मेरे सवाल के जवाब में एक बात कही है कि 31-3-2002 तक काम पूरा होने की संभावना है।

चौ. भजन लाल : अनीता जी, आप सड़क का नाम लें।

श्री मती अनीता यादव : सड़क का नाम है ढहीना, कौंसली वाया नेहरूगढ़ उस रोड से खुद मुख्य मंत्री जी गए हैं और उस पर ढाई-ढाई फुट के गड्डे पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : अरन अपरज पूछिए। मुख्य मंत्री जी कहां से जाते हैं यह प्र तासनिक मामला है। आप बैठ जाइए।(गोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : स्पीकर सर, बहन जी का ध्यान न तो सड़क ही तरफ है, न बिजनी की तरफ है इनका ध्यान आलोचना करने पर है। ये मुखर आलोचक बनना चाहती हैं जब मैंने अपने जवाब में बता दिया कि उस सड़क पर काम शुरू करने जा रहे हैं और उस पर 19 लाख रूपये खर्च होंगे और समय भी बता दिया इसके अलावा आप औ क्या चाहता है। आपके हल्के की इतनी सड़के बनाई हैं उनके लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए था बजाय इसके आप आलोचना किए जा रही है। मातनहेल, सालहावास, कौंसली, अम्बोली, बिदला, जटवाड़,

मातनहेल निमली सड़कें 7 लाख 58 हजार रूपये की लागत से बनाई हैं। मातनहेल बहूझोलरी सड़क पर 37.73 लाख रूपये खर्च हुए हैं इसके अलावा 73 लाख रूपये खर्च करके भामनगर सड़क एवं सालहावास खानपुर सड़क बनाई हैं। इसके अलावा बहुत सी सड़कें बनाई गई हैं बहुत सी सड़कों की रिपेयर की गई हैं उसके एि इन्होंने कुछ नहीं कहना है कहना उन्होंने उनके लिए ही है जो प्वाइंट रा गए। सड़कें इतनी अच्छी बनी हुई हैं कि में ममकंगे राम जी को देख रहा था वे कैथल से चंडीगढ़ तो सोते हुए आ रहे थे। जो गड्डे रह गए हैं उनको भी मूंद देंगे वे गड्डे आप ही के खोदे हुए हैं।

श्री मती अनीता यादव : अध्यक्ष महोदय, ढहीना से कौंसली वाया नेहरूगढ़ इस सड़क को हम यदि कौंसली से सुबाना झज्जर तक अगर मिला देते हैं जो काफी समस्या हल हो जाएगी।

श्री आम प्रका । चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से, कहना चाहता हूँ कि सरकार ने नयी सड़कों को बनाने के और सड़को की मरम्मत के ही संभव प्रयास किए है अगर कहीं काई कमी रह गई है तो उस को देख लेंगे और मैं इनको बताना चाहूँगा कि सरकार अपनी परिस्थितियों के अनुकूल सड़कें बनाती है। ऐसी कोई गारन्टी नहीं दी जा सकती कि जहां आप कहेंगे वहीं सड़कें बनायी जाती हैं। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जब सड़कें बनने का प्र न आया था तो आपकी पार्टी के द्वारा व्हिप इू कर दिए जाते हैं

और यहां आकर के सस्ता भाँहरत हासिल करने के लिए प्रैस की लौबी की तरफ देखते हुए बाप यहां पर सड़कें बनाने की बात करते हो। हम काम अपने बजट के हिसाब से करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि अच्छी से अच्छी सड़कें बनाने की बात करते हो। हम काम अपने बजट के हिसाब से करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि अच्छी से अच्छी सड़कें बनें।

Up-gradation of Sub-station Israna

840. Shri Krishan Lal : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under Consideration of the Government to upgrade the Sub-station, Israna (Panipat) from 33 K.V. to 132 K.V. ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :
सिवाल-इसराना लाइन के साथ वर्तमान 33 के.वी. इसराना (पानीपत) का दर्जा 132 के.वी. बढ़ाने की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसकी अनुकानित लागत 5.83 करोड़ रूपए हैं। धन की व्यवस्था कर ली गई है। कार्य अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने पांच करोड़ की राशि 33 के.वी. के सब-स्टेशन को 132 के.वी. का पावर हाउस बनाने पर खर्च की है इसके साथ ही मेरा दूसरा

सवाल माननीय सी.पी.एस. महोदय से यह है कि जिला पानीपत में इसके अलावा भी अन्य कार्ड पावर हाउस अपग्रेड करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है अगर हाँ तो कब तक कर लिया जायेगा।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : स्पीकर सर, वैसे तो बिजली के मामले में काफी डिस्कान हो चुकी है। मेरे माननीय साथी ने अपने क्षेत्र की बात रखते हुए पानीपत जिले के बारे में पूछा है इसके बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इसराना में 132 के.वी.ए. का सब-स्टेशन बनने वाले हैं दूसरा 132 के.वी.ए. का सब-स्टेशन मतलौडा में जो माननीय सदस्य का अपलना गांव है में बनाने का कार्यक्रम है। इसी प्रकार से 132 के.वी.ए. का जलमाणा, 33 के.वी.ए. का जी.टी रोड पानीपत, 33 के.वी.ए. का, सिवाह दीवाना में बनाने का कार्यक्रम है। स्पीकर सर, पानीपत जिले में बिजली के सुधार के लिए अनेकों सब-स्टेशन बनने वाले हैं 33 के.वी.ए. का कोहंड में बनेगा जिस पर 87 लाख रुपये की लागत आयंगी, उपलाना में 87 लाख रुपये की लागत से 33 के.वी.ए. का सब-स्टेशन बनाया जायेगा। बड़सत में 75 लाख रुपये से 33 के.वी.ए. का, काबड़ी में 41 लाख रुपये से 33 के.वी.ए. का, 33 के.वी.ए. का धर्मगढ़ में 25 लाख रुपये की लागत से, इसराना में 33 के.वी.ए. का 35 लाख रुपये से तथा 132 के.वी.ए. का समालखा में 1.80 लाख रुपये का और 132 के.वी.ए. का 175 लाख रुपये में बनाने का कार्यक्रम है। इसी प्रकार से संचार लाइनें बनाई जायेंगी। 132 के.वी.ए. की असंध में

क्षमता बढ़ाई जाएगी। स्पीकर सर, पानीपत जिले में अनेकों सब-स्टे इन बनाने की योजना है जिसमें मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य कृष्ण लाल जी सहमत होंगे कि गुणवत्ता और फ्रिक्वेंसी के सुधार के लिए अनेकों कदम सरकार द्वारा उठाये जा रहे हैं जिसकी वजह से पूरे प्रदेश के किसान, मजदूर, व्यापारी और कर्मचारी माननीय मुख्य मंत्री का गुणगान करते हैं केवल विपक्ष के भाई ही नुकताचीनी करने के लिए बैठे हैं।

Completion of Roads

1024. Prof. Ram Bhagat : Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the construction works of roads of villages Kuba, Tharan, Patwad, Vata, Badla, Bardchhapper, Maula, Jamni Khera, Saigara and Dharam Kheri to Khandti and Khanda to Narnaund Majra, Thaurana to Badla, Dang to Murana are likely to be completed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : प्र नाधीन सड़कों को पूर्ण करने के लिए निश्चित समय अवधि बताना सम्भव नहीं है।

प्रो.राम भगत : स्पीकर सर, ये जो मेरे हल्के की सड़कें हैं इनका निर्माण बहुत जल्द करवाना जरूरी है क्योंकि 1995 में बड़ी खतरनाक बाढ़ आई थी उसकी वजह से सड़कें बिल्कुल जर्जर हो गई थी। बास, बड़ाला, बड़छपपर और मौला की सड़कें काफी टूटी हुई हैं जिससे किसानों को भूगर मिल तक अपना गत्रा पहुँचाने में बड़ी तकलीफ होती है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी

से निवेदन है कि मंत्री जी पहले तो जो मेरे प्र न में गांवों के नाम दिये गये हैं वे सारे गलत दिये गये हैं उनको ठीक किया जाये उसके बाद इन सड़कों की मरम्मत का बाम तत्काल रूप से भुरु किया जाये ताकि वहां रहने वाले लोगों को तकलीफ न हो, किसान आसानी से अपना गन्ना ले जा सके। पुठी गांव में 15 हजार की आवादी है, पिछले साल यह विशय उठाया गया था कि उस गांव में जाने के लिए कोई बस सुविधा नहीं है और सड़क टूटी हुई है इसलिए इस पर जल्दी विचार किया जाए।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का प्र न किया होगा वैसा ही जवाब दिया गया होगा। मेरे माननीय साथी ने एक गांवच0 का नाम लिया है, इन्होंने ठौराना से बाडला सड़क के बारे में कहा है तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि उस सड़क को 31-12-2002 तक ककपूरा कर लिया जाएगा, धर्मखेड़ी से गुराना तक की सड़क को 31-12-2002 तक पूरा कर दिा जाएगा और डाहट से गुराना तक की सड़क के कार्य को भी 31-12-2002 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है जामनी खेड़ा सड़क का काम पूरा हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्र नकाल समाप्त होता है।

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर

Improvement in Power Availability

*886.**Diwan Pawan Kumar:**Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any improvement in the availability of Power in state,if so,the details there of together with the details of Power supplied during the year 1996 to 2002 separately; and

(b) the steps being taken to augment the power in the state ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य की विद्युत उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार है। पिछले 2-1/2 वर्षों के दौरान हरियाणा के लिए 621 मैगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की उपलब्धि प्राप्त की गई है। वर्ष 1996-97 से वर्षानुसार विद्युत उपलब्धता निम्नानुसार है :-

Table Missing

(ख) विद्युत उपलब्धि में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं -

1. राज्य में नयी उत्पादन परियोजनाए बनाई।

10वीं तथा 12वीं पंच वर्षीय योजना समय के दौरान तीन हजार मैगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। भविष्य में चालू होनी प्रस्तावित परियोजनाओं में से कुछ निम्नलिखित हैं -

2. केन्द्रीय विद्युत इकाईयो तथा अन्य स्रोतो से विद्युत क्रय

इसके अतिरिक्त हरियाणा, विद्युत निगम के माध्यम से लम्बी अवधि के आधार पर तथा स्वतंत्र विद्युत क्रेताओं द्वारा स्थापित की जा रही विभिन्न अन्य विद्युत परियोजनाओं के बारे में विचार-विमर्श चल रहा है।

Sarv Shiksha Abhiyan

***883. Sh.Amar Singh Dhanday:** Will the Minister of State for Education be pleased to state the date on which the "Sarv Shiksha Abhiyan" is likely to be launched in the State together with the improvement, if any, to be made in the education system under the said Abhiyan ?

राज्य शिक्षा मंत्री (चौ.बहादुर सिंह) : श्रीमान्, राज्य में सर्व शिक्षा अभियान 1-4-2002 से लागू किया जा रहा है। इसके माध्यम से बहुमुखी प्रयास किए जाएंगे जिससे सन् 2007 तक प्राथमिक शिक्षा और सन् 2010 तक आठवीं तक की शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण किया जा सकेगा। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए अनेक प्रयास किए जाएंगे जैसे अध्यापकों का प्रावधान, भौतिक सुविधाओं को सशक्त करना, योजना बद्ध तरीके से प्रत्येक गांव में माध्यमिक स्कूल सुनिश्चित करना, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रावधान, फर्नीचर आदि की उपलब्धता तथा सेवारत अध्यापकों के व्यापक प्रशिक्षण का प्रावधान करना आदि। इस दिशा में परियोजना की प्रारम्भिक गतिविधियां शुरू की जा चुकी है। इस कार्य हेतु व्यापक कार्य योजना बनाकर भारत सरकार को पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है।

Construction of Bye-pass, Fatehabad

***1022. Chaudhry Lila Krishan:** will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under Consideration of the Government to construct Bye-pass in Fatehabad ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : नहीं, श्रीमान् जी।

Water Courses

***1035. Sh. Jarnail Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the ban has been

imposed for the construction of new water courses (Khal) in Ratia; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to remove this ban.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : वर्ष 1992 में रतिया में नए खालों के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाया गया था यह प्रतिबन्ध रतिया सहित कुछ विकास खण्डों में भू-जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। फिलहाल इस प्रतिबन्ध को हटाने का कोई प्रस्ताव सरदार के विचाराधीन नहीं है।

Road Constructed by H.S.A.M.B.

***939.Dr.Raghuvir Singh Kadian:** Will the Minister for Agricultural be pleased to state the total length of roads in kilometers constructed by Haryana State Agricultural Marketing Board in Beri constituency during the last two and half year ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : बेरी निर्वाचन क्षेत्र में गत अढ़ाई वर्षों के दौरान हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 16.90 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया।

Up-gradation of 33 K.V. Sub-station at Padla

924. Sh. Lila Ram : Will the Chief Minister be Pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the 33 K.V. Sub-station at Village Padla in Kaithal Constituency ; if so, the detail thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हॉ श्रीमान्, 7.39 करोड़ रूपए की लागत से कैथल-पाडला प्रसार लाइन के साथ पाडला में एक 132 के.वी उपकेन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य वर्ष 2002-03 के दौरान पूर्ण होना सम्भावित है।

Number of Posts of Headmasters and Principals

***898.Sh.Ramesh Kumar Khatak:** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) the number of posts of Principle and Headmasters filled up during the year 2001-2002 in the state ;and

(b) the number of posts of Principle and Headmasters,if any, lying vacant in the State at present ?

शिक्षा राज्य मंत्री(चौधरी बहादुर सिंह) :

(क) वर्ष 2001-02 में राजकीय उच्च विद्यालयों के मुख्याध्यापको के 274 पद तथा राजकिय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्राधानाचार्यओ के 206 पद भरे गए है।

(ख) इस समय राज्य में 612 मुख्याध्यापको के पद तथा 169 प्राचार्यो के पद रिक्त हैं 140 मुख्याध्यापक के पद तथा 85 प्राधानाचार्यओ के पद भरने कि लिए मांग-पत्र हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेजा गया है।

Courses started at Post Graduate Center

***863.Sh.Bhagi Ram:** Will the Minister of State for Education be pleased to state the detail of new courses started at PostGraduate Center,Sirsa?

शिक्षा राज्य मंत्री(चौधरी बहादुर सिंह) : हां,श्रीमान् जी। भौक्षणिक सत्र 2000-2001 के दौरान स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केन्द्र सिरसा में पांच नये पाठ्यक्रम-कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर,विधि स्नातक, एम.ए. लोक प्रशासन,कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा भारीरिक शिक्षा में प्रमाण-पत्र आरम्भ किए गए है।

Staff provided in upgraded schools

***879.Sh.Jasbir Mallour:** Will the Minister of State for Education be pleased to state-

(a) whether any Government School from Pimary to Middle and Middle to High has been upgraded in the State during the year 2000-2001;if so, the number of ; and

(b) whether the staff as per norms has been posted there in ?

शिक्षा राज्य मंत्री(चौधरी बहादुर सिंह) :

(क) जी हां,वर्ष 2000-2001 में 151 प्राथमिक विद्यालयों से माध्यमिक विद्यालय और 69 माध्यमिक विद्यालयों से उच्च विद्यालयों का दर्जा बढ़ाया गया है।

(ख) इन स्तरोन्नत विद्यालयों में अमला निर्धारित नॉर्म अनुसार स्विकृत कर दिया गया है।

Number of cases of murder/theft etc. registered in the state

***1043. Capt.Ajay Singh Yadav, Shri Krishan Pal, Shri BalwantSingh (Sdhaura):**

(a) the number of Absconders in the state in 1st May, 1998 and as at present;

(b) the number of cases of murder,rape,kidnapping abduction,dacoity,highway robberies, theft in general and vehicles in particular,xnatching of ornaments and vehicles registered in the state during the period from 1st January,2001 to date; and

(c) the number of cases out of those as referred to in part (b) above in which thw accused have been arrested convicted and acquitted during the said period ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क) राज्य में दिनांक 1 मई 1998 को तथा वर्तमान भगौड़े अपराधियों की संख्या,

भगौड़े अपराधियों की कुल संख्या

1 मई 1998

(ख) राज्य में 1 जनवरी 2001से अब तक हत्या,बलात्कार, अपहरण, अपनयम,डकैती, राजमार्गों पर लूटपाट, कुल चोरी, वाहन चोरीवि शेषकर, वाहन छिनना और गहने छिनने के दर्ज अभियोगों की संख्या

(ग) राज्य में 1 जनवरी, 2001 से अब तक उपरोक्त (ख) में वर्णित अपराधों में दर्ज किए गए अभियोगों की संख्या, जिनमें दोशी गिरफ्तार हुए,सजा हुए और बरी हुए

Construction of Mini Secretariat Tohana

1039. Sh. Nishan singh : Will the Minister for Town and Country Planning be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Mini Secretariat at Tohana ?

राजस्व मंत्री (श्री धीरपरल सिंह) : लघु सचिवालय केवल जिला मुख्यालयों पर ही निर्मित हकये जाते हैं। फिर भी, टोहाना में प्रासकीय/न्यायिक परिसर निर्मित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Number of Vacant Posts in Medical College, Rohtak

975. Shri Shadi Lal Batra : Will the Minister of State for Health be pleased to state—

(a) the group-wise total number of sanctioned posts in each department of Medical College, Rohtak;

(b) the number of posts out of the posts referred to in part (a) above are lying vacant, togetherwith with the date since when these are lying vacant; and

(c) the steps taken for filling up of these posts including director Principal during the last two years ?

श्री अध्यक्ष :मेरे पास इस क्वै चन के संदर्भ में एक रिकवैस्ट आई है। जिसमें मंत्री जी ने जवाब देने के लिए कुछ समय मांगा है। जो कि मैंने ग्रान्ट कर दिया है और वह लैटर इस प्रकार है—

Dr.M.L.Ranga

D.O. 321-MH

Minister of State for

Health, Medical Education &

Ayurveda Departments

Haryana, Chandigarh.

Dated 15-3-2002

Respected Shri kadian Ji,

This is regarding Starred Assembly Question No.975 asked by Shri Shadi Lal Batra, M.L.A. reegarding group wise total number of sanctionde posts in each department of

Medical College, Rohtak and number of posts lying vacant together with date since when. He has also asked for steps taken to fill up these posts including that of Director Principal during the last two years. It is stated, Sir, that there are more than 38 departments in the PGIMS, Rohtak and it is very difficult to furnish staff position department wise and reasons thereof to not fill them up as it is very voluminous and labour consuming. Department may not be able to file reply in proper manner and well shaped immediately and more time will be needed to collect the detailed information. It is requested that more time may be given to file the reply. Approval of Hon'ble CM has been obtained to seek more time to reply this question. You are requested to kindly accede to this request and not to list the question.

With regards

Yours sincerely,

(M.L.Ranga)

Shri Satbir Singh Kadian

Hon'ble Vidhan Sabha, Chandigarh.

Educational uplifting of S.C. & B.C. Students

993. Sh. Banta Ram Balmiki : Will the Minister of State for Education be pleased to state whether any scheme has been introduced for educational upliftment of students belonging to Scheduled Castes and Backward Classes; if so, the detail thereof ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ. बहादुर सिंह) : हॉ श्रीमान्
जी।वक्तव् सदन के पटल पर रखा जाता है।

वक्तव्य

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों के
भौक्षणिक उत्थान के लिए निम्नलिखित स्कीमें आरम्भ की गई है
:-

प्राथमिक शिक्षा :

1. लड़कियों के लिए निः शुल्क वर्दियां
2. उपस्थिति पुरस्कार
3. निः शुल्क लेखन सामग्री
4. निः शुल्क पाठ्य पुस्तकें
5. विशेष उपस्थिति भता
6. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां
7. विमुक्त कबीलों के बच्चों को वजीफा

माध्यमिक शिक्षा :

1. नौवीं से बारहवीं कक्षा तथा अन्यविभागीय पाठ्यक्रमों
में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वजीफा देना

तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी को परीक्षा भुल्क की प्रतिपूर्ति ।

2. नौवीं से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को वजीफा देना ।

3. छठी से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/अवसर खर्च प्रदान करना ।

4. छठी से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के विद्यार्थियों को लेखन सामग्री खरीदने हेतु अनुदान ।

5. छठी से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले विमुक्त जातियों/टपरीवास विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना ।

6. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे माता-पिता के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति प्रदान करना ।

7. नौवीं से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली अनुसूचित जातियों की छात्राओं को मैरिट छात्रवृत्ति प्रदान करना ।

8. अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग स्कीम ।

9. अनुसूचित जातियों के छात्रों की मैरिट के उन्नयन हेतु स्कीम ।

10.राजकीय विद्यालयों में छठी से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाली अनुसूचित जातियों /समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की छात्राओं को निः शुल्क वर्दियां प्रदान करना ।

11.ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को चिकित्सा/इंजीनियारी पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षाओं के लिए विशेष निः शुल्क कोचिंग ।

12. हरियाणा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के छात्रों के भौक्षणिक उत्थान हेतु मुख्य परियोजना स्कीम ।

उच्चतर शिक्षा :

1. राज्य सरकार द्वारा हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के मेधावी छात्रों को निः शुल्क आवास सुविधा प्रदान की गई स्कीम आरम्भ की गई है ।

2. राजस् सरकार द्वारा हाल ही में अनुसूचित जातियों के छात्रों की विभिन्न सेवाओं में भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए एक नई स्कीम आरम्भ की गई है ।

3. अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों को प्रवेश हेतु आरक्षण का लाभ दिया जाता है ।

4.अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों को शुल्क में छूट दी जा रही है ।

5. अनुवूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के छात्रों को विशेष छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही है।

6. कुरुक्षेत्र वि विद्यालय में स्थित महात्मा गांधी अखिल भारतीय सेवा संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों की अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाई जाती है।

स्थगन प्रस्ताव की सूचना/वाक आउट्स

श्री कृष्ण पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दुःखद घटना की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो 17 तारीख को लोहारू में घटी।

श्री अध्यक्ष : उस पर गवर्नमेंट की स्पेसमेंट आ चुकी है।

श्री कृष्ण पाल : अध्यक्ष महोदय, उस घटना में बी.जे. पी. के कार्यकर्ताओं को झूठा फंसाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : कृष्णपाल जी, आपने तो उस बारे में कुछ लिखकर नहीं दिया। (गोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल : अध्यक्ष महोदय, मैं जीरो आवर में बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : कृष्णपाल जी आप बैठें। कृष्णपाल की कोई बात रिकॉर्ड न की जाएं। (गोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, एक गैर जरूरी मामला था, वैसे उस पर केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकारकी अनर्गल बातें करते हैं तब तो सदन में होते नहीं, केवल सस्ती लोकप्रियता हाविल करने के लिए इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं जो कुछ लोगों की आदत होती है। बिना किसी डिमांड के उस दुःखद घटना से मैंने पूरे सदन को अवगत कराया था और सारी स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी। यह जनतंत्र है और जनतांत्रिक प्रणाली में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है चाहे वह इंडियन नेशनल लोकदल को, चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो अथवा किसी भी राजनीतिक पार्टी का असामाजिक तत्व हो जो इस प्रकार की घटनाएं करके प्रदेश के सुख भ्रान्ति के वातावरण में तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं उनके साथ सरकार सख्ती से निपटेगी।

श्री कृष्ण पाल:

श्री अध्यक्ष : कृष्णपाल गुर्जर की कोई बात रिकॉर्ड न की जाए। भतन लाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो कहें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, कल भी हमने एक सीरियस मैटर उठाया था और वह बड़ा अहम् मुद्दा था, कल आपने उस पर बोलने के लिए अलाए नहीं किया और आत भी हमने एक सररियस मैटर के बारे में आपको लिख कर दिया था और जैसा

कि मल आपने कहा था कि “आपने यह मैटर 12 मिनट पहले दिया है, आपको एक घंटा पहले देना चाहिए था।” इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज हमने एक घंटा पहले आपको मैटर के बारे में लिखकर दिया है, उस पर हमें बहस करने की इजाजत दी जाए।

श्री अध्यक्ष : वह डिस-अलाउ कर दिया गया है।

चौधरी भजन लाल : वह किस बात पर डिस-अलाउ पर दिया गया है उसके पीछे कोई कारण तो हो। सी.ए.जी. जी रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि 600 करोड़ रुपये का घपला हुआ है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के भाइयों ने जो एडजोर्नमेंट मोशन दी थी वह रद्द कर दी है लेकिन चूंकि कल भी इन्होंने यह मुद्दा उठाया था और आज फिर उठा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश का दुर्भाग्य तो यह है कि विपक्ष के भाई अपनी विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से असमर्थ रहे हैं। (विधन)

पहले ये सरकार के खिलाफ अविश्वास लाये और मंजूर होने के बाद उस पर चर्चा से पहले भाग गये।

उसके बाद ये अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आये। उसमें इन्होंने कानून कायदे की पालना नहीं की जिसके कारण वह रद्द हो गया। तीसरी दफा यं फिर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आये लेकिन जरूरी संख्या न हुटा पाने के कारण वह भी रद्द हो गया। अध्यक्ष महोदय, इनको जो यह

भी ज्ञान नहीं कि राज्यसभा के सदस्य के लिए नोमीने इन पेपर कैसे फाईल किए जाते हैं और किस तरह से पेपर रिजैक्ट होते हैं। जो मुद्दा ये आज

25 से 28 पेज नम्बर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप फेसला पढ़िये। (विधन एवं भाोर) आप भूमिका न बनाएं, आप कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़िये। (विधन एवं भाोर) इस बारे में कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है आप उस वर्डिक्ट को सम्मनित सदस्यों को सुना दीजिए वह सब मानेंगे आप और कोई बात न कहिए। (विधन एवं भाोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिए (विधन एवं भाोर) मैं फेसला भी बता दूंगा। (विधन एवं भाोर)

श्री अध्यक्ष : आप फैसला पढ़ियें (विधन एवं भाोर) अगर आपने फैसला नहीं पढ़ना है जो आप बैठ जाएं। (विधन एवं भाोर) आप यह बताएं कि आपने फैसला पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आप फैसला पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं आप फैसला पढ़ें वह पक्ष में है या खिलाफ है।

चौधरी भजन लाल : आप सुनोगे तभी ना (विधन एवं भाोर) आप मेरी बात को सुन तो लें (विधन एवं भाोर) भूमिका तो बतानी ही पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : भजनलाल जी, फैसले में सारी चीज होती है, भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है बाप बैठ जाइये। (विधन एवं भाोर) भजन लाल जी फैसला पढ़ें तो रिकॉर्ड करना नहीं तो इनकी कोई और बात रिकॉर्ड न की जाए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : आप फैसला पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। (विधन एवं भाोर) इनकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। (विधन एवं भाोर)

श्री ओम प्रका ा चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे पता था कि ये पढ़ नहीं सकेंगे। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन अजय सिंह, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। सदन के नेता बो रहे हैं आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रका ा चौटाला : मैं स्पीकर की परमि ान से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। (गोर एवं व्यवधान) आप बुद्धिमान आदमी हैं आपसे मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। (गोर एवं व्यवधान) मुझे अध्यक्ष ने परमि ान दी हुई है और मैं बतौरे सदन के नेता बोल रहा हूँ। (गोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह :

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता बोल रहे हैं आप कृपा अपनी सीट पर बैठ जाएं। (गोर एवं व्यवधान) कैप्टन साहब जो भी बोल रहे हैं वह कुछ रिकॉर्ड नहीं किया जाए।

कैप्टन अजय सिंह : *****

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी भजन लाल जी को बताना चाहूंगा कि कई ऐसे मामले थे जो मेरी समझ में नहीं आते थे। मैं उस बारे में कोई गिल्टी महसूस नहीं करता था, मेरे में कोई इनफेरियोरिटी कॉम्प्लैक्स नहीं होता था। मैं स्वयं ही क देता था कि इस बारे में सम्पत सिंह बताएंगे। अगर आपकी समझ में यह नहीं आता है तो आप अपने उप नेता को कह सकते हैं। आप उनको नेता तो मानते नहीं है लेकिन हाउस में ये आपकी बाजू में बैठते हैं और यहां पर आपकी बात तो कह सकते हैं। (गोर एवं व्यवधान) मैंने तो पहले ही इस बारे में कहा था कि मैं बता दूंगा लेकिन आप कहने लगे कि आप ही बताएंगे। लेकिन आप यहां पर वह बता नहीं सके। अब हाईकोर्ट का जो फेसला है उसके मुताबिक मैं आपको यहां पर बता दंता हूँ। हाईकोर्ट ने मैसर्ज औरबीट रिजार्ट प्रावेट लिमिटेड से किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया है। मैं यह हाईकोर्ट का फेसला सुना रहा हूँ। मैसर्ज औरबीट रिजार्ट प्राइवेट लिमिटेड ने हाईकोर्ट के फेसले के बाद दोबारा से हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। 29.2.1991 को यह रिट सिंगल बेंच द्वारा खारिज कर दी गई थी किन्तु 11.1.1999 को माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा हाईकोर्ट के

डिविजन बेंच ने एल.पी.ए रद्द कर दी । उस समय मैं मुख्यमंत्री नहीं था। यह रिज्म्पान आर्डर भी अदालत में उस समय क्वेरा हो गए। अदालत ने यह निश्कर्ष निकाला कि श्री भजन लाल ने केस को मैलाफाइडी,(इसका मतलब है कि गलत) गलत तरीके से प्लीड किया, रिज्यूम करवाया। एच.एस.आई.डी.सी. ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को उच्चतम न्यायालय में भी चुनौती दी, जो कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा 3.12.1999 को रद्द कर दी गई। एच.एस.आई.डी.सी और गवर्नमेंट दोनों उच्चतम न्यायालय में गए और उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि मैसर्ज औरबीट रिजार्ट प्राइवेट लिमिटेड को इस भारत पर प्रोजेक्ट दिया था कि वे इसको दो वर्षों में पूरा करेंगे। इस प्रकार से स्पष्ट है कि मैसर्ज औरबीट रिजार्ट प्राइवेट लिमिटेड को इस प्लॉट की जो अलॉटमेंट थी वह वैध करार दी गई।(गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैटर खत्म हो गया है। (गोर एवं व्यवधान) आप अपनी सीटों पर बैठ जाएं। आप इस तरह से सुप्रीमकोर्ट के फेसले पर नहीं बोल सकते हैं।(गोर एवं व्यवधान)

चौ.बंसी लाल :अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया गया है इसलिए मैं इस बारे में क्लेरिफिकेरा देना चाहता हूँ।(गोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरा नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, मुख्य मंत्री जी ने आपका नाम नहीं लिया है इन्होंने यह बताया कि उस समय आपकी टर्म थी। (गोर एवं व्यवधान)

चौ.बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जब हमने यह केस दायर किया था तो उस वक्त सरकारकी तरफ से वकील थे श्री भांति भूशण, श्री सीता रे और श्री प्रेम मल्होत्रा। एच.एस.आई.डी. सी की तरफ से वकील थे श्री डी.डी.ठाकुर और दूसरे वकील थे। Upon hearing counsel the Court made the following order -
2

“Issue notice. Let both the party matters come up together.”

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ जब हियरिंग के ऊपर केस आया तो उससे पहले वकील दूसरा था। उस समय प्रकाश सिंह बादल के लड़के का वकील श्री महाबीर सिंह था उनको हरियाणा की सरकार ने मेरी सरकार के जाने के बाद अपना वकील आर्न रिकार्ड मुकर्रर कर दिया। उसने फिर यह लिखा कि फलानं आदमी को वकील किया जाए। वह वकील है श्री महेश माथुर। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नो-नो। आप ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के डिसिजन पर मत बोले। (गोर एवं व्यवधान) बंसी लाल जी, अब फैसला हो चुका है इसलिए अब आप बैठें। सुप्रीम कांर्ट के फेसले को हम यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते। अब तो फैसला हो गया

है अब आप बैठें। बंसी लाल जी की कोई भी बात अब रिकॉर्ड न की जाए। (गोर एवं व्यवधान)

चौ.बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, ***** (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, अब आप बैठ जाएं। कोर्ट में पहले आर्गुमेंट्स होते हैं और उसके बाद ही डिस्मिस होना है।

चौ.बंसी लाल : *****

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, अब फैसला हो गया है इसलिए आप बैठिए। (गोर एवं व्यवधान) बंसी लाल जी, आपकी कोई बात अब रिकॉर्ड नहीं हो रही है इसलिए अब आप बैठें। अब फैसला हो गया अब कुछ नहीं हो सकता। जो फैसला हो गया ठीक हो गया। बड़ी बुद्धिमान से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है चाहे वह किसी के भी पक्ष में गया हो। हमें कोई मतलब नहीं कि वह किसके पक्ष में गया है लेकिन बात यह है कि फैसला तो हो गया। (गोर एवं व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है हम उसके फैसले के बारे में यहां पर इस तरह से चर्चा नहीं करेंगे। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसलिए इस फैसले के बारे में हम यहां पर डिस्कशन नहीं कर सकते। (गोर एवं व्यवधान) बंसी लाल जी, आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है इसलिए अब आप बैठ जाएं।

चौ.बंसी लाल : *****

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी बंसी लाल जी से कहना चाहता हूँ कि ये अब बैठ जाएं क्योंकि इनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, इनकी कोई भी बात अब रिकॉर्ड नहीं हो रही है, इनकी कोई भी बात लिखी नहीं जा रही है। वैसे तो चौधरी बंसी लाल जी लॉ ग्रेज्यूट हैं डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और बदकिस्मती से मुख्य मंत्री भी कई मर्तबा रहे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठें। इनकी कोई बात रिकॉर्ड न करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिए। (तोर एवं व्यवधान)

चौ.जय प्रकाश : स्पीकर सर, यह तो आपकी कोई बात नहीं है यह आपका कया तरीका है बाप किस तरह से उनको बोल रहे हैं ? (तोर एवं व्यवधान) मैं सबको बड़े प्यार से कहता हूँ कि प्लीज आप बैठें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : भजन लाल जी, क्या आप हाउस से भागना चाहते हैं ?

श्री भजन लाल : हम हाउस से भागना नहीं चाहते।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : फिर आप आराम से बैठें और अपने मैम्बरज को बैठाते क्यों नहीं ? (तोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बंसी लाल जी को पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हमें यहां पर डिसकस नहीं करना चाहिए वरना यह कंटैम्प्ट का मामला नहीं बनता है (तोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, कोई कंटैम्प्ट का मामला नहीं बनता।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : बंसी लाल जी, जब हाई कोर्ट में इस बारे में फैसला हुआ था और जब अपील की गयी थी उस समय मुख्य मंत्री कौन था तब आप मुख्य मंत्री तो थे न ?

चौ. बंसी लाल : हाँ, मैं मुख्य मंत्री था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : क्या आपने इस मामले की उस वक्त पैरवी नहीं की और अगर की तो आप कैसे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमने पैरवी नहीं की। आपने अपील दायर की। जब हमारी सरकार थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में दूसरे फरीख ने अपील दायर की थी। लेकिन उस समय आप स्वयं मुख्य मंत्री थे और आपने अपील दायर की और आपके मुख्यमंत्रित्व काल में ही हाईकोर्ट ने फैसला सरकार के खिलाफ दिया था। (तोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, बंसी लाल जी तो बिना रिकोगनाइज अपोजी उन लीडर के हाई कोर्ट में मेडीकल बिल्ज का पैसा मांगने के लिए गए थे कि मैं उस वक्त अपोजी उन लीडर था इसलिए

उसका मुझे पैसा दिया जाए जबकि ये उस वक्त किंगनार्डज अपोजी इन लीडर थे ही नहीं। ये तो गलत काम के लिए की कोर्ट में जाते है ठीक काम के लिए तो ये कोर्ट में जाते ही नहीं है।

चौ. बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, वह मुकदमा भी ये हार गए और मैं जीत गया। (गोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बंसी लाल जी सीलियर मोस्ट मैम्बर है और एक पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे हैं ये अपना इलाज तो दिल्ली में करवाते हैं और उसका पैसा हरियाणा सरकार से मांगने के लिए कोर्ट में जाते है कि मुझे पैसा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, यह ठीक काम के लिए तो कभी कोर्ट में नहीं जाते है। (गोर एवं व्यवधान)

चौ.भजन लाल : स्पीकर साहब,यह इस तरह की बातें करके हाउस का ध्यान डायवर्ट करना चाहते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

चौ. बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, बाप मेरी बात तो सुन लें। मुख्य मंत्री द्वारा बार-बार मेरा नाम लिया जा रहा है। (गोर एवं व्यवधान)

चौ.भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, आप बैठ जाएं। भजन लाल जी आने वायंट ऑफ आर्डर पर खड़े है। (तोर एवं व्यवधान)
भजन लाल जी, आप अपने प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलें।

चौ.भजन लाल : स्पीकर साहब, बंसी लाल जी भी अपनी बात कहना चाह रहे हैं वे सीनियर मैम्बर हैं आप पहलेउनकी बात सुन लें। (तोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले आप दोनों सलाह कर लें। भजन लाल जी,आप पहले अपनी बात कहें क्योंकि पहले आपने प्वायंट ऑफ आर्डर लिया है।

चौ. बंसी लाल : स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी बार—बार मेरा नाम ले रहे हैं इसलिए आप मेरी बात तो सुन लें। (तोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी मर्जी चलेगी कि मेरी मर्जी चलंगी।
(तोर एवं व्यवधान)

चौ.भजन लाल : लेकिन हम ठीक बात तो कह सकते हैं। चौधरी बंसी लाल जी की बात तो आप सुन लें। यह बहुत ही सीरियस मैटर है।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, क्या आपका यही प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। यहां सिफारि 1 की जरूरत नहीं है,बगैर सिफारि 1 के हाउस चलता है।

चौ.भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी की यह बात रिकॉर्ड न की जाए। (गोर एवं व्यवधान)

चौ. बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई अनार्लियामेंट्री भाशा का इस्तेमाल नहीं किया। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। चौधरी भजन लाल जी आप दो मिनट बैठ जाएं। (गोर एवं व्यवधान) ये लनेंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है Learned counsel for the respondents states that the respondents shall pay all the outstanding dues within a period of six month from today and the construction willbe completed within two years. The respindents shall file an undertaking to that effect within one week from today.With these directions, the special leave petitions and writ pettions are disposedof, application for impleading party is not pressed. ताज्जुब की बात यह हे कि हम पेटी अनर है और आर्गूमैंट आई है सिर्फ रिसपोंडैंट की । हमारा वकील बोला ही नहीं। हमारे वकील का नाम तो ऊपर लिखा था लेकिन उसने लफज एक भी नहीं बोला *****

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी की यह बात रिकॉर्ड न करें। यह फैसला बहुत पुराना है अब गढ़े मुद्दे उखाड़ने का कोई फायदा नलहीं है आप बैठ जाइए। (गोर एवं व्यवधान)

चौ.भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, 1300 गज का प्लॉट 5 करोड़ रूपये में दिया जबकि सी.ए.जी. जी रिपोर्ट के मुताबिक

उसकी कीमत 21 करोड़ रुपये बनती है जबकि 18 एकड़ की कीमत 700 करोड़ रुपये बैठती है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। (गोर एवं व्यवधान)

चौ.भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुनी नहीं जा रही है और रिकॉर्ड नहीं की जा रही है इसलिए हम ऐज ए प्रोटेस्ट सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन से वाकआउट कर गए।)

श्री उपाध्यक्ष (श्री गोपी चंद गहलौत) : माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरे क्षेत्र गुड़गांव का मामला है इसलिए मेरी बात सुनें। चौधरी भजन लाल जी व बंसी लाल जी मैं आप दोनों की मिलीभगत बताता हूँ आप सुनने की क्षमता रखें। (गोर एवं व्यवधान)

चौ.बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन तो सुन लें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, आप बैठ जाएं।

चौ. बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन नहीं सुनी जा रही है इसलिए हम ऐज ए प्रोटेस्ट सद से वाक आउट करते हैं।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सदन से वाकआउट कर गए।)

श्री उपाध्यक्ष (श्री गोपी चंद गहलौत) : अध्यक्ष जी, गुड़गांव के बारे में जमीन घोटाले की बात कर रहे हैं यह जो एच. एस.आई.डी.सी. की जो जमीन दी गई उसके बारे में तो हमारे मुख्य मंत्री जी ने बता दिया है। अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव के इतिहास ज्यूडिचियरी के मामले में जो सबसे काला दिन था वह था 6-7-1998। वह ऐसा दिन था जैसा की भाई चन्द्र भाटिया ने परसों-चौथ बताया था कि भायद हरियाणा के इतिहास में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ होगा जैसा कि गुड़गांव के डी.सी. सहित 12 आदमियों को 6 महीने की कैद की सजा हुई और प्रत्येक को दो-दो हजार रुपये जुर्माना और एक लाख रुपये कोस्ट देनी पड़ी। वह यह बतायें कि यह मामला क्या था ? इसके बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि यह जो 20 एकड़ की बात कर रहा हूँ केवल मात्र 300 रुपये गज के हिसाब से एच.एस.आई.डी.सी. ने दी इस 20 एकड़ जमीन की किस दिन रजिस्ट्री के पैसे दिये गये। यह मामला आज से तीन दिन पहले भी आया था कभी कोई ऐसी मिसाल नहीं मिली होगी जिसके अन्दर कभी डी.सी. और एस.एच.ओ. सहित कई अन्य अधिकारियों को सजा हुई हो यह बड़ी निन्दनीय बात है कि चौधरी बंसीलाल जी कह रहे थे कि एक और मामला था कि यह डी.एल.एफ.। अंसल के अन्दर अढ़ाई एकड़ जमीन इन लोगों ने वक्फ बोर्ड की भी नहीं छोड़ी। उस जमीन को

कितने पैसे में खरीदा और किस ने खरीदा। चौधरी भजन लाल जी यह अढ़ाई एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की एफ.आई.आर. नं. 453 में दर्ज है जिसके ऊपर जबरन कब्जा कर लिया गया। गोलियां चली और पुलिस की तरफ से 53 आदमियों पर झूठे मुकदमे बनायं गये उस मामले में बपद इन्म्वायरी हुई जो मिली भगत की बात कर रहे थे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आपको इजाजत नहीं दी है। कर्ण सिंह की बात को रिकॉर्ड न किया जाये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल ने जो कहा है वह रिकॉर्ड न किया जाये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष (श्री गोपी चंद गहलौत) : अध्यक्ष महोदय, इनके अन्दर सुनने की क्षमता होनी चाहिये। डी.एल.एफ. की जमीन में और सु तांतलोक की जमीन में तीन आदमी बिल्कुल इकट्ठे थे खलील अहमद तहसीलदार, वीरेन्द्र सिंह कानूनगी बौर

जसवंत पटवारी यं असमें भी थे और इसमें भी थे परन्तु वक्फ बोर्ड की भी सु तांतलोक की जो अढाई एकड़ जमीन थी उसमें एक नाम नया था वह था कुलदीप सिंह बिानोई जिनके खिलाफ हाई कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ जिसके खिलाफ एफ.आई.आर. नम्बर 1106 दर्ज हुई। एफ.आई.आर. नं. 453 चौधरी भजनलाल जी के समय में कब्जा हुआ तब की बात है और एफ.आई.आर. नं. 1106,2-10-1996 को दर्ज हुई जब चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के मुख्य मंत्री थे। इससे बड़ी बात कहीं नहीं हुई होगी कि कोर्ट से कागज गायब हुये थे। 27 तारीख को छुट्टी के दिन जब हाई कोर्ट से सट्ट मिल गया। उसके बाद रजिस्ट्री तहसीलदार के या डी.सी. के घर बैठकर हुई। कहीं भी ऐसा संयोग नहीं मिलेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि ये इन दोनों मामलों की जिसमें 20 एकड़ की जमीन जो सरहोल गांव की है जिसकी फरियाद लेकर एक विधवा दर-दर घूम रही है करोड़ों रुपये की जमीन है लेकिन उसके पैसे का भुगतान नहीं हुआ। जबरन जमीन पर कब्जा हुआ है तथा दूसरी सु तांत लोक की जिस की चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। मैं आपसे चाहूँगा कि इन दोनों मामलों की तहकीकात विजिलेंस से करवायी जाये ताकि इन दोनों को अपने चेहरे का पता लग सके वह बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, Not allowed.।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। आप सुन तो लीजिये। मैं गलत नहीं कह रहा।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, आप बगैर इजाजत बोल रहे है आप गलत कहो या ठीक कहो आप इजाजत लेकर नहीं बोल रहे हैं इसलिए बैठ जायें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी बात सुनें। मैं कोई गलत बात नहीं कहूँगा।

श्री अध्यक्ष : आप तो कोई गलती नहीं करते आप तो वैल में आकर भी खड़े हो जाते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने का हक है।

श्री अध्यक्ष : जब आपको अलारूड नहीं किया गया है तो फिर आपके बोलने का कोई मतलब नहीं है, आप बैठ जाइये।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। मैं अण्डर रूल अपनी बात कहना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष : कोई रूल नहीं, आपने जाना है आपकी कम्पली चली गई है इसलिए आप भी जाने वाले है। आप बैठ जायें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। आप मुझे मेरी बात तो कहने दीजिये। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बड़े सीनियर मैम्बर है, आपको बोलने की इजाजत नहीं है, आप बजट पर भी बोले है और बापको बोलने का पूरा मौका ला है। इसलिए आप बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे सीनियर मैम्बर मानते हैं इसके लिए आपकी मेहरबानी।

श्री जगजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब कोई अच्छा सुझाव देना चाहते हैं इसलिए आप उनकी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह दलाल और जगजीत सिंह सांगवान की कोई बात रिकॉर्ड न की जाए। (गोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है इसलिए हम एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीकर्ण सिंह दलाल एवं नै नलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री जगजीत सिंह सांगवान सदन से वाक आउट कर गए।)

श्री उपाध्यक्ष (श्री गोपी चंद गहलौत) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपी रिक्वैस्ट कर दी कि हमारे क्षेत्र के साथ 2-3 केसिज में बड़ा अन्याय हुआ है, मैं सरकार से चाहूँगा कि वहाँ विजीलेंस से जाचं कराई जाए। 20 एकड़ की जमीन में से उस विडो को एक रूपया भी नहीं दिया गया। भजन लाल जी मेरे साथ बैठे हुए पूछ रहे थे कि उस समय कांग्रेस का कौन एम.एल.ए. था तो मैं बताना चाहूँगा कि उस समय पुरुशभान कांग्रेस का एम.एल. ए. था और उसके भाई वृशभान को सजा ीी हुई ही इसनिए मैं सरकार से चाहूँगा कि इन 2-3 केसिज में तहकीकात क जाए और विजीलेंस से इसकी इन्क्वायरी करवाई जाए।

श्री ओम प्रका 1 चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय गोपी गहलोत ने जिन केसिज का उल्लेख किया है, इनके बताने के मुताबिक ये खासे गम्भीर मामलात दिखाई देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि गोपी चन्द गहलोत जी इस मामले से सम्बन्धित सारे डाक्यूमेंटस प्रस्तुत कर दें, सरकार विजीलेंस के द्वारा इसकी इन्क्वायरी करवाएगी।

श्री कृष्णपाल गुर्जर :

श्री अध्यक्ष : कृष्ण पाल जी जो कुछ कह रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाए।

वर्ष 2002-2003 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will give reply on the Budget for the year 2002-2003.

वित्त मंत्री (प्रो. सम्पत सिंह) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 13 मार्च 2002 को मैंने सदन के सामने हरियाणा का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट पर माननीय सदस्यों ने 3 दिन तक लगातार बहस की। काफी अच्छे-अच्छे सुझाव भी आए हैं, कुछ लोगों ने रचनात्मक आलोचनाएँ भी की हैं। अधिकतर सदस्य बजट से अलग होकर भी बोलें हैं। मैंने उस दिन भी बीच में उठकर कहा था कि आपको एक-एक बात का जवाब हम देंगे। लेकिन आप उस वक्त उपस्थित जरूर हों। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अपोजि उन कोई न कोई बहाना बनाकर सदन से एक आउट कर गई। इसी तरह से जब गवर्नर एड्रेस पर मुख्य मंत्री महोदय की रिप्लाय आई, तब भी ये वाक आउट करके चले गये थे। जबकि इनका यह फर्ज बनता था कि मौके पर मौजूद होते, रिप्लाय के समय इनको एक-एक बात का जवाब दिया जाता उस जवाब को ये सुनते और ये बात लोगों तक पहुंचती और क्लैरीफिके उन होती। आज बजट का रिप्लाय आ रहा है। हरियाणा प्रदेश की तकदीर का सवाल बजट से जुड़ा हुआ है। यह सारे साल का लेखा-जोखा होता है ये केवल आंकड़े ही नहीं होते हैं, सरकार की

नीतियां होती हैं कि सरकार किस-किस विभाग में किन-किन वर्गों के लोगों के लिए क्या-क्या करने आज फिर विपक्ष के भाई सदन में नहीं हैं। इससे ज्यादा हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है ? विपक्ष के भाइयों का व्यवहार बहुत गैर-जिम्मेदाराना है ये अपनी उल्टी-सीधी बातें कह देते हैं और जब सरकार का जवाब देने का समय आता है तो ये यहां से चले जाते हैं। ये जवाब सुनने की हिम्मत नहीं रखते। स्पीकर सर, आप स्वयं जानते हैं कि आज के दिन दुनियां किस दौर से गुजर रही है। अकेला हिन्दुस्तान नहीं बल्कि ग्लोबल लैवल पर रिसैरुन आया हुआ है। आज मंदी का दौर चल रहा है। अमेरिका और यूरोप जैसे देश जो अपने आपको लीडिंग कन्ट्रीज मानते हैं कि आज के दिन दुनियां किस दौर से गुजर रही है। अकेला हिन्दुस्तान नहीं बल्कि ग्लोबल लैवल पर रिसैरुन आया हुआ है। आज मंदी का दौर चल रहा है। अमेरिका और यूरोप जैसे देश जो अपने आपको लीडिंग कन्ट्रीज मानते हैं वहां भी बहुत जबरदस्त रिसैरुन आया हुआ है। वहां से लाखों लोग आई.टी और कम्प्यूटर सैक्टर से बेरोजगार होकर अपने-अपने देश आ रहे हैं। स्वाभाविक है कि मंदी की मार हिन्दुस्तान पर भी पड़ी है, हिन्दुस्तान की सरकार पर पड़ी है और हरियाणा जो कि एक छोटा सा प्रदेश है उस पर भी मंदी की मार पड़ी है, मैं यह बात मानता हूँ। लेकिन मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हम अपने मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के दिशा निर्देशों पर चलते हुए, उनकी लीडरशिप में काम करते हुए अपने वित्त पर कंट्रोल करके जितना भी हमारे पास बजट

मौजूद था, जितने हमारे संसाधन थे उन संसाधनों का सही इस्तेमाल करके लोगों तक अच्छी सेवाएं पहुँचाई है। इसका श्रेय मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को देना चाहता हूँ। स्पीकर सर, भायद ही कोई ऐसी स्टेट होगी जहां मुख्य मंत्री ऑर्डर करें और वित्त विभाग उन ऑर्डरों को न मानें या वापिस भेज दें। मेरे कहने का मतलब यह है कि मुख्य मंत्री जी के ऑर्डर कोई टाल नहीं सकता लेकिन इस बात के लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि इन्हें कड़वे से कड़वा फैसला लेना पड़ा ही लेकिन इन्होंने बजट को विदिन लिमिट रखने में, प्लॉन को पूरा करने के लिए नॉन प्लॉन एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, रैवेन्यू रिसीटस को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और अच्छा बजट बनाने में वित्त विभाग का मार्गदर्शन किया है। हमारे मुख्य मंत्री ने वित्त विभाग की हर बात मानी है और मुख्य मंत्री जी तकरीबन हर माईल पर लिख देते हैं कि वित्त विभाग से राय लें ली जाये। हिन्दुस्तान में ऐसा भायद ही कोई और मुख्यमंत्री हो जिसने वित्त विभाग का इतना ज्यादा मार्गदर्शन किया हो, वित्त विभाग का इतना साथ दिया हो। वरना मुख्यमंत्री फरमान जारी कर देते हैं चाहू उससे वित्त विभाग पर, कितना भी बोझ क्यों न पड़े, चाहू वित्त विभागका उससे प्रबंध बिगड़ जाये और सारा प्लॉन खत्म हो जाये, चाहू सारी अर्थ-व्यवस्था चरमरा जाये। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे विभाग की कद्र की है और जितनी बधाई दूँ वह कम है। स्पीकर सर, विपक्ष के साथियों ने बजट के बारे में जो जिक्र किया है उस बारे में मैं सबसे पहले जो हमारे अखबार हैं, न्यूज पेपर हैं,

मीडिया हैं उनकी मैं प्र संसा करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे बजट के लिए सरकार की सराहना की है, अखबारों की तरह विपक्ष के भाइयों को भी सच बोलना चाहिए था। कुछ अखबारों ने तो यहां तक लिखा है कि हरियाणा प्रदेश का बजट संतुलित बजट है। मौजूदा हालातों में, परिस्थितियों में इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त अखबारों ने यह भी लिखा है कि हरियाणा के साथ मंजाब और हिमाचल प्रदेश पड़ते हैं। इन दोनों प्रदेशों का जिक्र किया है कि ये दोनों प्रदेश भारत सरकार की सहायता के रहमो-करम पर चल रहे हैं अगर भारत सरकार इनको सहायता न दे तो ये राज्य अपने कर्मचारियों को तनखाह भी नहीं दे सकते। साथ में यह भी लिखते हैं कि उन दोनों के बजट के मुकाबले हरियाणा का बजट हजार दर्जे अच्छा है। स्पीकर सर, यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह बात न्यूज पेपर कह रहे हैं जो कि निष्पक्ष हैं और जनता तक अपनी सही बातें पहुँचाते हैं। इससे ज्यादा हरियाणा प्रदेश के बजट की और प्र संसा क्या होगी ? स्पीकर सर, हमने इस बजट में मूल संरचना के अमूक ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान दिया है। चाहे इरिगेशन हो, पावर हो, रोडज हो, ट्रांसपोर्ट हो हर विभाग की तरफ हमने विशेष ध्यान दिया है। इसी तरह से कृषि पर और जिला ग्रामीण विकास पर भी ध्यान दिया गया है। खासकर सामाजिक सेवाओं पर सबसे ज्यादा बल दिया है। चाहे बुढ़ापा पैशन की बात हो, चाहे निराश्रित लोगों की बात है, चाहे विडोजकी बात है, हरेक की तरफ ध्यान दिया गया है इसी तरह सामाजिक सुरक्षा की

तरफ ध्यान दिया गया है हमारे वित्तीय साधनों पर भी प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार से जो भारत सरकार से मदद आनी थी वह भी कम हुई है। हम मानते हैं कि भारत सरकार की भी अपनी लिमिटेड एंज हैं, उन पर भी मन्दी का असर पड़ा है इसलिए हमें 90 करोड़ रुपये तो केन्द्र सरकार की तरफ से कम आये और आर्थिक मन्दी के कारण हमारे राजस्व में भी 130 करोड़ रुपये की कमी आयी है। ये जो कह रहे हैं कि प्लॉन में खर्चा कम किया गया, इसको कम करना हमारी मजबूरी थी।

इसी तरह से सहारी संस्थाएं जो हैं, जैसे चीनी मिल हैं, सीनीय निकाय हैं, इन पर भी अधिक बोझ आया है। सरकार ने भी इन संस्थाओं को वित्तीय मदद दी है और अब चौधरी बंसी लाल जी को बताना चाहूंगा कि इनके वक्त के गन्ने के बकाया पैसे जो तकरीबन 21 करोड़ रुपये थे, वे भी मौजूदा सरकार ने दिये हैं। इसी तरह से म्यूनिसिपल कमेटी के कर्मचारियों को जिनको दो-दो साल से तनख्वाह नहीं मिल रही थी उनकी तनख्वाहों की अदायगी भी मौजूदा सरकार ने की है। इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट ऐडिड प्राइवेट स्कूलों सरकार ने दिया है। मेरे कने का मतलब यह है कि जब इस सरकार ने सत्ता सम्भाली तो काफी देनदारियां हमने देनी थी। हमारी सरकार को आते ही कुछ ऐसे खर्चे करने पड़े जिस कारण प्लॉन का खर्च कम हुआ है और नॉन प्लॉन में खर्च अधिक बढ़ा है। हमने जो किया है वह लोगों की भलाई के लिए किया है। इसके बावजूद भी सरकार ने अच्छा

वित्तीय प्रबन्ध किया है उसकी झलक भी इस बजट में दे रखी है। पूरा बजट पढ़ें तो आप पायेंगे कि हमने गैर उत्पादक खर्चों में कमी की है याजि उनको कम किया है। इसी प्रकार से कर प्रणाली में भी सुधार करके उनका सरनीकरण करके, आय साधन जुटा करके और अपने दूसरे खर्चों में भी कमी करने जा रहे हैं। 11 वें वित्त आयोग ने जो वित्तीय सुधार करने के लिए हमारे को जो दिना-निर्देश दिए हैं उनकी तरफ भी हम पूरी तरह सेकदम बढ़ा रहे हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि एस्एब्लिमेंट पर खर्च बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ कह दिया कि कर्मचारियों के 5400 पद खत्म कर दिये हैं। स्पीकर साहब, अगर हम सारे देशों के इस बारे में आंकड़े लें और पर-थाऊजैण्ड मुलाजिम देखें तो आपके प्रदेश में 1000 आदमियों पर 16 आदमी सर्विस में हैं यानि हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा है। दूसरा नम्बर पंजाब का आता है। पंजाब की माली हालत के बारे में भी आपको पता है। वहां प्रति 1000 के पीछे 14 कुछ हैं। इसके बाद थर्ड नम्बर राजस्थान का आता है जहां पर प्रति 1000 के पीछे 4.6 की मुलाजिम की पोजीशन हैं। हमारे यहां दूसरे राज्यों की अपेक्षा 4 गुणा मुलाजिमियत है। इसके बावजूद भी हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के विकास के लिये, लोगों के हितों के लिए, उनके विकास के लिए काम कर रही है और इन सब के बावजूद भी लोगों के विकासके कामों में हर्ज नहीं आने दे रही है। इमने अब फैसला किया है कि जा अननैसेसरी पद हैं, जो दो साल से खाली पड़े हैं और जिनकी जरूरत नहीं है उन पदों को खत्म किया जायेगा लेकिन जहां

जरूरत पड़ी है, जैसे पुलिस महकमे में भर्ती की जरूरत पड़ी, डाक्टर की भर्ती करने में जरूरत पड़ी, पालिका में भर्ती की जरूरत पड़ी या अन्य कवभागों में भर्ती की जरूरत पड़ी है तो उन सब में भर्ती भी की है लेकिन नाजायज पदों को भी खत्म किया है और जायज पद भरे भी हैं। इस तरह से हमने अपने बजट को संतुलित रखा है। स्पीकर साहब, जहां तक एग्जिजिटिव बजट का खर्चा है इस बारे में चौधरी बंसी लाल जी ने भी और दूसरे सदस्यों ने भी कहा कि इस पर काफी ज्यादा खर्च बढ़ गया है। जबकि हम कह रहे हैं कि हमने यह खर्च घटाया है। इस बारे में बजट में दिए हुए आंकड़े बता रहे हैं। इन उपायों के ही परिणाम निकले हैं कि जहां पहले वेतन खर्च में कटौती और राजस्व प्राप्तियां 52.23 प्रति सैकड़ थीं वहां अब कम होकर चालू वर्ष में 50.88 प्रति सैकड़ हो गईं। इसी प्रकार से पिछले वर्ष ब्याज अदायगी पर जो खर्च था, जो राजस्व प्राप्तियां थीं, वे 23.82 प्रति सैकड़ थीं लेकिन अब घटकर 22.82 प्रति सैकड़ हो रही हैं। स्पीकर साहब, इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम सुधार की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं इसी तरह से चालू वित्त वर्ष में संशोधित अनुमानों में जो राजस्व घाटा है वह 1170.48 करोड़ रुपये रह गया है जो कि 2002-03 के बजट अनुमानों के अनुसार 114.25 करोड़ रुपये से घट कर 1056.23 करोड़ रुपये रह जायेंगे। स्पीकर साहब, इस बारे में मेरे पास दूसरी स्टेट्स के भी आंकड़े हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है लेकिन वहां हमारे से डब्ल्यू.टी.ए. यानि 1502 करोड़

रूपये डैफीसिट है। इसी तरह से कर्नाटक में 2664 करोड़ रूपये, राजस्थान में 3 हजार करोड़ रूपये और दिल्ली में भी जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर भी 2 हजार करोड़ रूपये का डैफीसिट है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारी विलीय स्थिति कैसी है हमारी वित्तीय स्थिति बेहतर हो गई है। अगले वर्ष राजस्व की प्राप्तियों में 12.3 की वृद्धि सम्भावित आंकी गई है इसके मुकाबे राजस्व खर्च है एक तरफ रैवेन्यू रिसीट्स और दूसरी तरफ रैवेन्यू एक्सपेंडिचर की वृद्धि 9.3 रहेगी इसका मतलब यह है कि राजस्व वृद्धि से 3 कम है यह भी सुधार की तरफ कदम है, पोलिटिव स्टैप है। स्पीकर साहब, इन तथ्यों से यह प्राप्तियां पिछले वर्षों के सकल घरेलू उत्पाद की 8.01 थी जो बढ़ कर चालू वित्त वर्ष में 8.26 आ गई है यह इण्डिके इन स्पष्ट को रहा है। जहां तक बजट घाटे को पूरा करने की बात का सवाल है, यह कहा जा रहा है कि बजट घाटा आपका 202 करोड़ रखा गया है। पिछले वर्ष 191.7 करोड़ का घाटा था जब कि इस वर्ष 202 करोड़ रूपये का घाटा रखा गया है। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया है कि इसका कारण केन्द्रीय सरकार से 90 करोड़ रूपये कम आना तथा दूसरे वर्ल्ड बैंक से 74 करोड़ रूपये कम आना रहा है। प्रोजैक्ट का फर्स्ट फेस 31 दिसम्बर को खत्म हो गया था अगर वह प्रोजैक्ट 31 मार्च तक चलता तो हमें 100 करोड़ रूपये के करीब फालतू मिल जाने थे अतः यह बजट घाटा ऑलमोस्ट मीट आउट हो जाता। स्पीकर सर, इस घटे के यं कारण रहे हैं अगले वर्ष में 202 करोड़ रूपये का जो घाटा रखा है इसमें स्पीकर सर, मैं यह क्लीयर करना

चाहूँगा कि जो केन्द्र सरकार का बजट है उससे हमें कुछ अधिक पैसा मिलने की उम्मीद है। उसकी वजह से अतिरिक्त सहायता से घाटा पूरा किया जाएगा। केन्द्र सरकार के अगले बजट में राज्य सरकारों की केन्द्र में हिस्सेदारी और बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त लघु बचत योजनाएं, स्मॉल सेविंग्स का 80 लघु बचतों के अगेन्स्ट मिलता था अब केन्द्र सरकार ने फैसला कर लिया है कि 100 इसका हमें मिलेगा। पिछले दिनों आपने अखबारों में पढ़ा होगा मुख्यमंत्री जी ने डी.सी.जी. और ऑफिसर्स की मीटिंग में हमने जो टोटल टारगेट रखा था उसको भी दुगना कर दिया है। स्पीकर सर, यह जो पैसा आएगा इससे बजट घाटा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और अगले साल यह घाटा खत्म हो जाएगा। स्पीकर सर, इसी प्रकार से आने वाली 5 अप्रैल, 2002 को मुख्यमंत्री महोदय योजना आयोग से मिलने जा रहे हैं और फाईनैस क पूरी टीम भी उनके साथ जा रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो बैस्ट फाईनैसियल मैनेजमेंट रहा है उसकी वजह से हमें और फालतू पैसा मिलेगा। पिछली बार भी हमने इस बारे में प्रयास किया था उन्होंने इस तरह के इण्डिकेन्स दिए थे कि आप यह-यह सुधार करके आएं तो आपको फालतू पैसा दिया जाएगा। जिनकी मैनेजमेंट अच्छी है जिनकी गुड गवर्नेंस है, को केन्द्र की तरफ से अतिरिक्त पैसा दिया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें उनसे भी पूरा पैसा मिलेगा। स्पीकर सर, काफी माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया विशेषकर मांगे राम गुप्ता जी और दूसरे साथियों ने भी जिक्र किया है इन्फ्रास्ट्रक्चर पर इस बार खर्चा

कम कर रहे हैं। पिछली दफा यह 54.6 था इस बार 42.14 रख रहे हैं। स्पीकर सर, इस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार जो 54.6 रखा था उसके अन्दर जो वर्ल्ड बैंक के लोन से आना था वह पैसा मिला हुआ था यानि वो पैसा भी शामिल था क्योंकि सरकार में खजाने में आ कर उसके बाद बिजली बोर्ड को मिलता था अब क्योंकि स्पीकर याहब, वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं ले रहे हैं। बिजलीह बोर्ड, पी.एफ.सी. से आर.ई.सी. से साधन जुटा रहा है क्योंकि वर्ल्ड बैंक की भाती को मानने के लिए हम तैयार नहीं थे उसकी वजह से जो लोन लिया जा रहा है वह केन्द्र की दूसरी संस्थाओं जैसे पावर फाइनेंशियल कारपोरेट्स है, इलैक्ट्रीफिके टन कारपोरेट्स है उनसे जो पैसा लोन पर ले रहे हैं इस साल में भी तकरीबन 634 करोड़ रुपये आया है और अगले साल तक 600 करोड़ से ऊपर आयेगा। अगर वह पैसा इसमें और जोड़ लिया जाए तो यह इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 56 से ऊपर खर्चा पड़ेगा जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। स्पीकर सर, इससे अर्थ व्यवस्था में सुधार होगा स्टेट की आमदनी के साधन बढ़ेंगे, उत्पादन के साधन बढ़ेंगे और प्रोजैक्ट को और जोड़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 64 से फालतू यह खर्च होना है। बिजली, पानी, सड़कें जिनको इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्चा बोलते हैं उन पर यह 64 से ऊपर जा कर पड़ जाएगा। स्पीकर सर, यह राजस्व के लक्ष्य प्राप्ति की बात है। मेरे कई साथी विधायकों ने जिक्रकिया कि इस चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान में यह राजस्व 5105.92 करोड़ रुपये रखा था। जिसमें संशोधित अनुमान 4975.

10 करोड़ रूपए कर दिया है। अब इन्होंने यह कह दिया कि आपने इतना कम क्यों कर दिया। स्पीकर साहब हमने कोई टैक्स नहीं लगाए हैं। अब सदन में विपक्ष के साथी होते तो वे ही बताते हक हमने कौन सा टैक्स लगाया है। हमने केवल मात्र लोकल एरिया डिवेलपमेंट टैक्स लगाया था। आज भी ये स्पीकर साहब उसको लागू नहीं होने दे रहे थे। कोर्ट कचहरी में झमेलाहोने की वजह से वह रूक गया था। हाई कोर्ट में हलांकि सरकार केस जीत गई है। अब वाला पैसा आएगा और जब वह पैसा आएगा जो यह जो अनुमान हमने रखा था हमारा वह अनुमान पूरा हो जाएगा। अदरवाईज हरियाणा प्रदे 1 में हमारी सरकार बनने के बाद एक नए पैसे का कोई कर नहीं लगाया गया है। किसी डिपार्टमेंट में सर्विस चार्जिज बढ़ा दिए, यूजिज चार्जिज बढ़ा दिए वह अलग बात है। अब यहां पर म्यूनिसिपल कमेटी की बात कर दी। म्यूनिसिपल कमेटी अपने आप में एक ओटोनोमस बाडी है उनका जिक्र बजट के अन्दर नहीं आता है। इसी तरीके से दूसरे और भी मद हैं जिनका जिक्र बजट में नहीं आता है हमारी इस हरियाणा सरकार का जहां तक सवाल है तो हमारी सरकार ने एक नया पैसा नहीं बढ़ाया है बल्कि हमने तो घटाया है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमने एच.आर.डी.एफ. का फंड घटाया है, मार्किट फीस घटी है, जितना मोटा अनाज था चाहू वह बाजरा था, ज्वार था, चने की दाल थी ऐसी-ऐसी तकरीबन 20 से 25 के करीब आईटम्ज बनती हैं इसको हमने 12 से 8 प्रति शत किया है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि हमने

घटाने का काम किया है बढ़ाने का काम नहीं किया है। इसी तरह हमने टैक्स के अन्दर सुधारीकरण का काम किया है। उसकी सिम्पलीफिके 1 न की गई है। स्पीकर सर, पांच करोड़ रुपये की सैल्फ असैसमेंट के ऊपर जिसको हम डीमड असैसमेंट बोलते हैं। व्यापारियों को दफ्तरों में चक्र नहीं काटने पड़े, इन्सपैक्टरी राज खत्त हो जाए। जो असैसमेंट 5 करोड़ रुपये तक की दे देते हैं इनको होती है उनको विभाग मान लेता है। इन्कम टैक्स की तरफ से सक्रूटनी करना एक अलग बात है। इससे बड़ी सुविधा हरियाणा सरकार और क्या दे सकती है। इसी वजह से पिछली आय के मुकाबले में साढ़े 15 प्रति 100 के करीब आय बढ़ी है। हमारे से पहले चौधरी बंसी लाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनके जाने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार सम्भाली तो उनके वक्त में जो टैक्सों की इन्क्रीज थी वह 1.7 प्रति 100 दिखाई गई थी। वह कैसे दिखाई थी कि अप्रैल महीने की पहले ही असैसमेंट करके मार्च महीने में एडवांस में कलैक्ट 100 लेकर दिखाई थी। अदरवाईज हरियाणा में इतिहास में माईनस टैक्स का रिकॉर्ड होता। आज की सरकार 15 प्रति 100 एक्साईज का मिलाकर दे रही हैं। यह भी बहुत सराहनीय काम है। यह कैसे हो पाया है, यह सरकार के अधिकारियों की वजह से हो पाया है, सरकारकी स्पष्ट नीति की वजह से हो पाया है। आज एक अच्छा वातावरण देने की वजह से, व्यापारियों के साथ फरैन्डली रिले 100 देने की वजह से रैवेन्यू बढ़ाया जा सका है। मैं इन लोगों को बताना चाहूँगा कि लाठियां चलाकर, गोलियां चला कर व्यापारियों

पर 307 के तहत केस दर्ज करके रैवेन्यू नहीं बढ़ाया जा सकता है। हमने बकायदा लोगों के साथ मिलकर के यह रैवेन्यू बढ़ाया है। (गोर एवं व्यवधान) इसी तरह से यहां पर एक्सरईज ड्यूटी की बात आई। इस बारे में मेरे कुछ भाईयों ने यह सं गाय जाहिर की कि एक्सरईज में कमी आई है। पिछले वर्ष में एक्सरईज ड्यूटी का लक्ष्य 870 करोड़ रूपये का रखा गया था जिसमें फरवरी तक 801.73 करोड़ रूपया आ गया है। स्पीकर सर, एक महीने की एवरेज लगाएं तो जो लक्ष्य हमने 870 करोड़ रूपए का रखा था उससे फालतू ही बैठता है। मुझे पता नहीं कि ये कैसे कह रहे हैं कि यह कम हो गया है। स्पीकर सर, इस मद में 2002-2003 में 940 करोड़ रूपये का लक्ष्य रखा गया है जो कि 8 है और उसको हम पूरा करेंगे। सदन में मुख्य क्षेत्रों में धन की कम व्यवस्था का भी जिक्र किया गया है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि कृषि में 928.37 करोड़ रूपये का पिछली बार प्रोविजन किया गया था इस बार इस को बढ़ा कर 944.61 करोड़ रूपये का प्रोविजन है। बिजली के बारे में मैंने पहले भी बताया कि पिछले वर्ष 882 करोड़ रूपये थे इस बार इसमें 1144 करोड़ रूपये रखे गए हैं। इसके अलावा 600 करोड़ रूपये का जो लोन है वह अलग से है। पहले जो वर्ल्ड बैंक का जो लोन आता था वह सरकार के खाते में आता था इस लिए वह बजट में दिखा दिया जाता था। अब जो लोन है वह डायरेक्ट बोर्ड को मिलता है। अगर इसको मिलाए तो यह 11 प्रति सत से 14 प्रति सत हो जाता है। इसी तरह से सिंचाई है इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले में 730 से बढ़ा कर 767 करोड़

रूपये, सड़क एवं भवन में 468 करोड़ से बढ़ा कर 555 करोड़ रूपये, शिक्षा में 15 से 16, 16 से 17 और 17 से 65 करोड़ रूपये, स्वास्थ्य विभाग में 348 से बढ़ा कर 405 करोड़ रूपये, समाज कल्याण में 480 से बढ़ा कर 503 करोड़ रूपये किए हैं। हरेक में बढ़ोतरी हुई है न जाने ये कहां से आंकड़े ले कर आए हैं पता नहीं सब चीजों के अन्दर बता रहे हैं। ये ऐसे यहां पर बोलते रहते हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री मागें राम गुप्ता : स्पीकर साहब, ऑन-ए-प्वायंट ऑफ ऑर्डर, वित्त मंत्री जी फरमा रहे हैं कि पता नहीं हम कहां से आंकड़े ले आए। मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये आंकड़े इन्होंने ही दिए हैं। (विधन) स्पीकर साहब, हमने जो भी आंकड़े पढ़े हैं वे वही पढ़े हैं जो वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में पेश किए हैं। स्पीकर साहब, मुझे बड़ा अफसोस है कि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि सरकार के रिसोर्सिज बढ़े हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बजट में पहली प्लॉनिंग पेश की थी उसको ये 2500 करोड़ रूपये से घटा कर 1800 करोड़ रूपये ले आए। इसी तरह से प्लॉन 2100 करोड़ से घटा कर 1900 करोड़ रूपये पर ले आए थे। ये आंकड़े हमने अपनी तरफ से नहीं दिए हैं। स्पीकर साहब, ये हाउस को गुमराह क्यों कर रहे हैं। यह मेरे आंकड़े नहीं हैं। ये बताएं कि अब इनके रिसोर्सिज बाकी कहां रह गए ? ये 2500 करोड़ रूपये से 1800 करोड़ रूपये पर ले आए और फिर 1900 करोड़ रूपये से 1800 करोड़ रूपये पर ले आए एवम उसके बाद 5400 करोड़

रूपये से यह 200 करोड़ रूपये पर ले आए। इस तरह से इन्होंने करीब बीस हजार करोड़ रूपये तक यह पहुँचा दिया। ये क्या हाउस को बता रहे हैं ? इन्होंने 5500 करोड़ रूपये का घाटा 200 करोड़ रूपये ला दिया। इनके रिसोर्सिज कहां है (विधन) सम्पत सिंह जी, इतना हाउस को गुमराह न करें। (विधन)

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, अब आप बैठ जाए। अब इनकी कोई बात रिकार्ड न करे।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय,

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, आप इनसे कहे कि ये बीच में टोका-टाकी न करे। इनको आराम से हमारी बात सुननी चाहिए। मांगे राम जी, आप धैर्य रखे। (विधन)

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर,

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, अब आप बैठ जाए। अब इनकी कोई बात रिकार्ड न करे।

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, ऐसा है कि एक घण्टे से भी ज्यादा समय तक गुप्ता जी बोले थे उस वक्त मैंने इनको एक जगह पर भी इंटरप्ट नहीं किया था अगर किया हो तो ये बता सकते हैं। अब ये मुझे बार-बार क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं। प्लॉन पर तो मैं अभी तक आया ही नहीं इन्होंने वैसे ही एडवांस गाड़ी चला

दी। प्लॉन के बारे में अभी मैं बताऊंगा। लेकिन ये सुनना ही नहीं चाहते। (विधन)

श्री अध्यक्ष : मांगे राम जी, यह आप की तरह लोकल गाड़ी नहीं है बल्कि एक्सप्रेस गाड़ी है।

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, प्लॉन के बारे में जैसा गुप्ता जी ने कहा है कि पहले इतना प्लॉन दे दिया और उसमें कट कर दिया। स्पीकर साहब, आप को भी पता है कि प्लॉन के हमें पहले अनुमान लगाए जाते हैं और उसके बाद ही प्लॉन बनाया जाता है। चाहे इन्होंने अपने समय में अनुमान लगाएं हो या चाहे बाद में चौधरी बंसी लाल जी के समय में अनुमान लगाएं हों, किसी के समय में भी अनुमान पूरे नहीं हुए। हमें तो मांगे राम जी द्वारा ऐप्रीट करना चाहिए कि अनरिएलिस्टिक अनुमानों को हम रिएलिस्टिक लाना चाहते हैं। इसके लिए इनको सरकार को दाद देनी चाहिए कि हम पहली बार रिएलिस्टिक फिगरज की तरफ आ रहे हैं वरना पहले ऐसा नहीं होता था। मैं गुप्ता जी के समय की बात इस बारे में बताना चाहता हूँ। 1996-97 का जब इन्होंने बजट पेश किया था उसमें इन्होंने 1434 करोड़ रूपए का प्लॉन रखा था लेकिन बाद में उसको रिवाइज करके इन्होंने 1370 करोड़ रूपए का कर दिया था और उसके बाद आप 1247 करोड़ रूपए के प्लॉन पर आ गए थे और उस समय लगभग दो सौ करोड़ रूपए पर आ गए थे। इन्होंने 1996-97 का प्लॉन भायद रखा था।

श्री मागें राम गुप्ता : स्पीकर साहब, 1996 में तो हम छोड़ कर चले गए थे। यह रिवाइज करके अगली सरकार ने घटाया है।

प्रो. सम्पत सिंह : चलो कोई बात नहीं, मैं 1995-96 का बता देता हूँ।

श्री मागें राम गुप्ता : स्पीकर सर, यह हाउस को गुमराह कर रहे है। 31 मार्च, 1996 को हमारी सरकार नहीं थी।

प्रो. सम्पत सिंह : चलो कोई बात नहीं, चौधरी बंसी लाल जी का टाईम होगा। स्पीकर सर, उस समय प्लॉन 1257 करोड़ रूपए का रखा था और ऐक्चुअल ऐक्सपेंडीचर 1116 करोड़ रूपए का हुआ था। उस वक्त इन्होंने 140-150 करोड़ रूपए बढ़ा चढ़ाकर रखे थे। ये बताएं कि यह क्यों रखे थे ? स्पीकर सर, यह रिवाइज आउट ले का और ऐक्चुअल ऐक्सपेंडीचर का कम्पैरिजन किया जाता है और 31 मार्च के बाद जब सारा ब्यौरा आ जाता है उसके बाद ही रिवाइज प्लॉन का करते है। रिवाइज प्लॉन में ये केवल 91 प्रसैंट को ही अचिवमेंट ले पाए थे। उसके बाद इनकी सरकार जाने के बाद चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के वक्त की भी मैंने फिगरज दी थी। 1996-97 में 91 प्रसैंट की ही अचिवमेंट उन की थी इसी तरह से 1997-98 में 92 प्रसैंट की अचिवमेंट थी। 1998-99 में 84.6 प्रसैंट की अचिवमेंट की। मांगे राम जी, आप इंडिकेटर देख लें। उस टाईम जब हमने राज

संभाला था। उस समय दो साल ऐसे गुजरे थे जो हरियाणा प्रदेश में कि काला इतिहास रहे। एक तरफ तो 1400-1500 करोड़ रूपए का रैवेन्यू घट जाना दूसरी तरफ जो नोजवान गुमराह हुए उनको ठीक रास्ते पर लाने के लिए सरकार को जो खर्च करना पड़ा वह अलग बोझ पड़ा। मांगे राम जी, आप ने पांच बार बजट पेश किए हैं और वाणिज्य परिवार में आपने जन्म लिया है, मैंने किसान के परिवार में जन्म लिया है मैं तो आपसे सीखता हूँ। I am a learner. सारा कुछ इसमें दिया हुआ है फिर भी आप इसको नकार रहे हैं। 1400-1500 करोड़ रूपए के लगभग सरकार को रैवेन्यू का नुकसान हुआ था। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मांगे राम जी, आप बैठ जाएं। (गोर एवं व्यवधान) यह कोई क्वै चन ऑवर नहीं है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह तो क्वै चन ऑवर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : मांगे राम जी की कोई बात रिकार्ड न की जाएं। आप बैठ जाइए।

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, हमने कोई टैक्स नहीं लगाया। मांगे राम जी सुन ही नहीं रहे हैं। (विधन) एक एल.ए.डी. टी. को छोड़ कर वह भी कोर्ट कचहरी के झमेले में रह गया था। अब कोर्ट ने सरकार के हक में किया है इसके अलावा हमने एक नए पैसे काम भी टैक्स नहीं लगाया बल्कि माफियां दी हैं। कोई

यूजेज चार्जेज, कोई सर्विस चार्जेज या जो कमेटियां टैक्स लगाती है कोई कारपोरेट इन लगा दे, कोई बोर्ड लगा दे, वह तो अलग चीज हुई लेकिन हरियाणा सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये भाई आ जाएं और बात सून लें। हमने कोई टैक्स नहीं लगाया था। 84.6 प्रसेंट अचिवमेंट चौधरी बंसी लाल जी के समय में पूरी हुई थी और स्पीकर सर, मांगे राम जी की सरकार के समय यह अचिवमेंट 91 प्रसेंट थी। यह सरकार आने के बाद 1785 करोड़ रूपया रिवाइज्ड एस्टिमेट में रखा था उसमें 1672.99 करके 93.7 प्रसेंट की प्लॉन हमने अचिव की है। 2000-2001 में हमने 95.5 प्रसेंट प्लॉन अचिव की है ऐज कंपेयर्ड टू रिवाइज्ड। मांगे राम जी मैं ऐज रिवाइज्ड कह रहा हूँ। करैक्ट यूअरसैल्फ। स्पीकर सर, ये समझ नहीं रहे है जब आप 31 मार्च से पहले बजट पे 1 करते है उससे पहले अनुमान लगाते है 31 मार्च के बाद प्लॉन को रिवाइज करते है, रिवाइज करने के बाद जो अचिव करते है उसको माना जाता है ये तो 91 प्रसेंट अचिवमेंट को जोकि चौधरी बंसी लाल के समय में घटती गई। उसके बाद हमने 93.7 अचीव किया है। पिछली बार 95.5 भी अचीव किया है। 1922 करोड़ रखा है यह बड़ा रिएलिस्टिक है। हमने पुरानी सरकार से लैसन लिया है। हम मानते है कि हमने इन भाईयों से लैसन लिया है कि बढ़ा चढ़ाकर प्लॉन नहीं रखेगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या आप रिवाइज्ड का बता रहे हैं ?

प्रो. सम्पत सिंह : हां, मैं रिवाइज्ड का ही बता रहा हूँ 1922 करोड़ रुपया प्लॉन में रखा है यह रिएलिस्टिक रखा है। I was learner. मैं किसान के घर पैदा हुआ हूँ। Speaker Sir, now I have learned. ये बड़ी रिएलिस्टिक फिगर है इनमे कोई अति योक्ति नहीं है ये केवल मात्र झुठी प्रतिशता में पड़े रहते थे और फाल्स प्रेस्टिज में पड़ कर बढ़ा दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है हमने स्पष्ट प्लॉन आपके सामने रखी है। फिर भी स्पीकर सर, सरकार की ऋण देयता में बढ़ोतरी की बात कहीं। राज्य की ऋण देयता के बारे में बजट एट ए ग्लैन्स जो आपको दिया है उसमें दिया हुआ है। 31-3-2001 को 14264 करोड़ रुपए था जो बढ़कर बाद में 16950 करोड़ रुपए हो गई और बाद में 19297 करोड़ रुपए होने की संभावना इन्होंने बताई। स्पीकर सर, राज्य की कुल ऋण देयता सकल घरेलू उत्पाद की लगभग 27 प्रति शत है और नैनल एवरैज 30 प्रति शत है। गुप्ता जी यह मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम लोन ले रहे है, केन्द्र ने लोन लिया है,इसलिए हम उसको जस्टिफाई कर रहे है केन्द्र का सकल घरेलू उत्पाद का औसत 30 प्रति शत है जब कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद का 27 प्रति शत है तीन परसेंट हालांकि उनसे कम है जैसा कि मैंने ग्लोबलाइजे शन के बारे में पढ़ा,भारत सरकार का पढ़ा और दूसरे प्रदेशों का पढ़ा मैंने आपकी दूसरे प्रदेशों में सरकारों का पहले जिक्र कर दिया।आप उस समय हाउस में नहीं थे कि जाक डैफिसिट है चाहु दिल्ली की सरकार, मध्यप्रदेश की सरकार,कर्नाटक की सरकार और दूसरी सरकारों

का मैंने पहले जिक्र कर दिया। उन सबसे बेहतर अगर मैनेजमेंट है तो वह आज हरियाणा प्रदेश की सरकार का है। स्पीकर सर, इस बात को प्लॉनिंग कमीशन ने भी माना है। यह देयता एक साल में नहीं बढ़ी, दो साल में नहीं बढ़ी बल्कि हर साल बढ़ती रही है। जैसा कि मैंने कहा गैर उत्पादन बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उत्पादन पर खर्च बढ़ेगा जब उत्पादन बढ़ेगा तो धीरे-धीरे इनको चुकता भी किया जायेगा। मांगे राम जी एक दिन में ऋण पूरे नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में नहीं खड़े होते उसमें टाइम लगता है। हुड्डा साहब ने एक बात कही थी कि किसान गांव में घर गिरवी रख कर जमीन लेता है और उस जमीन की पैदावार से उस घर की गिरवी रखी रजिस्ट्री को वापिस ले लेता है। सरकार भी उत्पादन खर्च कर रही है, हम नैगेटिव टाइप के खर्च नहीं कर रहे हैं। आने वाले वक्त के अन्दर यह ऋण भी पूरे किये जायेंगे लेकिन इसमें समय लगेगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव : आप इसे कैसे पूरा करेंगे।

प्रो. सम्पत सिंह : हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है इसलिए करेंगे और उत्पादन बढ़ाया है इसलिए करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : प्राइमरी सैक्टर में नैट ग्रोथ क्या है ?

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैं इस पर आना नहीं चाहता था कि इसका जिक्र करूं, प्राइमरी, सैकेन्डरी और ट्रसरी

सैक्टर इन तीनों का हुड्डा साहब आपको मालूम होना चाहिए। किसी अर्थ शास्त्रीसे पूछ लें और चौधरी भजन लाल जी से पूछ लें। कृषि पर अकेला बोझ जब तक रहेगा बात नहीं बनेगी। मैं यह कह रहा हूँ कि कंट्रीब्यू इन हुआ है। कंट्रीब्यू इन में प्राइमरी सैक्टर की बजाए द्वितीय और तृतीय सैक्टर का कंट्रीब्यू इन बढ़ा है। जोकि सराहनीय होना चाहिये। द्वितीय सैक्टर आप किसको कहते हैं आपका ट्रेड, मैन्यूफैक्चरिंग द्वितीय सैक्टर है और सर्विसीज तृतीय सैक्टर है और इन दोनों सैक्टरों में अगर आपका कंट्रीब्यू इन बढ़ेगा तो कृषि का कंट्रीब्यू इन घटैगा। सपीकर सर, उसी से इक्नोमी की ग्रोथ की नि गानी है। अब ये इसको भी उल्टा मान रहे है। अगर आप किसी अर्थ शास्त्री से पूछें तो आपको पता चले। अब कादयान साहब भी सदन से चले गये। दलाल साहब हैं इनसे आप पूछ लें कि सैकेंडरी और ट्रसरी सैक्टर का कंट्रीब्यू इन बढ़ रहा है तो वह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा इंडीकेटर है। अच्छा किया आपने याद करवा दिया। स्पीकर सर, जितनी भी अण्डरटेकिंग हैं वे जो पहले लोन लेती रही हैं और लोन के लिए अगर सरकार गारन्टी देती थी,सिक्योरिटी देती थी, सरकार ने अब उस पर दो प्रति शत सिंकिंग फण्ड लगा दिया है। दो परसेंट सिक्योरिटी लगा दी है। दो परसेंट सिक्योरिटी से क्या होगा। उस सिंकिंग फण्ड में जाकर जमा होगा और आईन्दा के लिए ऐसे पब्लिक अण्डरटेकिंग जो घाटे में चले जाये या बैठ जाये बौर उनकी देनदारी सरकार पर पड़ जाये तो सरकार कहां से देगी। इसलिए स्पीकर सर, यह भी एक पोजीटिव कदम सरकार

ने उठाया है और अगस्त से दो प्रतिशत सिक्क्योरिटी लागू भी कर दी है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि ये इन्वैस्टमेंट के बारे में भी बता दें।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इन्वैस्टमेंट के बारे में बता दिया कि इसको बढ़ा दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा दिया गया, लगता है इन्होंने सुना नहीं, मैं बता चुका हूँ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बाद में पूछ लेना।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, नॉन प्लॉन खर्चों में बढ़ोतरी के बारे में सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन में अधिक खर्च के बारे में, ब्याज भुगतान के अधिक खर्च के बारे में, ऋण अदायगी के खर्चों में बढ़ोतरी के बारे में, अन्य गैर योजनाओं के खर्च में बढ़ोतरी के बारे में, योजना खर्च में कमी के बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता जाहिर की है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि गैर योजना के खर्चों में पिछले कई वर्षों से बढ़ोतरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन इसका मुख्य कारण वेतन और ब्याज की अदायगी है। ऋण केवल हमने ही नहीं लिए थे, गुप्ता जी के समय में भी लिए गए थे। ऋण केवल हमने ही नहीं लिए थे, गुप्ता जी के समय में भी लिए गए

थे। ऋण अदायगी मद में अधिक खर्च होने की वजह से और सरकारी कर्मचारियों और पैं इन भोगियों के खर्च के कारण ही नॉनप्लॉन खर्च में बढ़ोतरी हुई है। जो फिफ्थ पे—कमी इन आया था उसने हर सरकार की कमर तोड़ी है मैं यह नहीं कहता कि इस कमी इन का असर सिर्फ हरियाणा पर हुआ है। इसका असर सभी स्टेट्स पर हुआ है। हिन्दुस्तान में कोई भी स्टेट नहीं है जो अपने एम्पलायज को वक्त पर तनख्वाह दे। लेकिन यह हरियाणा का रिकॉर्ड है कि हरियाणा में जितने भी कर्मचारी हैं उनको महीने के पहले दिन ही पे दे दी जाती है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूँगा। कि कॉलेज के सेवानिवृत्त लेक्चरार्ज को पैं इन नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप बिना परमी इन के न बोलें।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनको ध्यान में होगा कि केरल में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस ने योजना का केवल 25 प्रतिशत पार्ट ही पूरा किया और उसके बाद उन्होंने अपने कर्मचारियों की तनख्वाहों पर कंट्रोल लगा दिया और कहा कि मार्च तक केरल में किसी भी मुलाजिम को तनख्वाह नहीं दी जाएगी, 31 मार्च तक तनख्वाह नहीं दी जाएगी और उसके बाद ही तनख्वाह देंगे ताकि योजना पूरी हो सके। अध्यक्ष महोदय, यह

हालत इनकी कांग्रेस की सरकार की है न कि हरियाणा सरकार की है। (गोर एवं व्यवधान) हमारे हरियाणा में कर्मचारियों को एक-एक पैसा दिया जाता है। इसी प्रकार 11वें वित्त आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उनको हम मानेंगे। वर्ष 2005 तक घाटे को पूरा करने के बारे में इस आयोग ने कहा है। 2005 तक सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 परसेंट कट किया गया है। हमने तो हालांकि केन्द्र को 30 परसेंट या 27 परसेंट कहा है लेकिन उन्होंने 2.5 परसेंट का मापदण्ड रखा है। इसी प्रकार 2005 तक ब्याज अदायगी की वृद्धि दर 18-20 प्रति शत तक सीमित रखी गई है। इसी प्रकार वेतन पर खर्च वृद्धि दर प्रति वर्ष 5 प्रति शत कम की गई है। इस बारे में मैंने बताया है और भायद आपने सुना नहीं होगा कि इस पर हमने 2 प्रति शत खर्च म किया है, जबकि उन्होंने 5 प्रति शत रखा है। अध्यक्ष महोदय, मांगेराम जी पढ़े लिखे और सूझबूझ वरले व्यक्ति हैं, वाणिज्य परिवार से हैं और 5 बजट पे पेंटा कर चुके हैं। ये कह रहे हैं कि एस.वाई.एल. नहर के लिए मुख्य मंत्री जी के ब्यान आ रहे हैं कि उसकी मुरम्मत कराएंगे और बजट में इसका प्रोवीजन ही नहीं है। मांगेराम जी, वर्ष 2002-2003 के बजट का वोल्यूम 3 और पेज 487 पढ़कर देखें उसमें पता चल जाएगा कि एस.वाई.एल. नहर के लिए कितना बजट रखा गया है।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मांगेराम जी ने यह तो मान लिया था कि इन्होंने किताब पढ़ी ही नहीं।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल नहर के लिए 10 करोड़ यपये का प्रावधान रखा गया है और जरूरत पड़ने पर की और से कट लगाना पड़ा तो कट लगाएंगे और एस.वाई.एल नहर पर जितने खर्च की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए वित्त विभाग इस काम में कोई कमी नहीं आने देगा।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांचट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष : मांगे राम गुप्ता की कोई बात रिकॉर्ड न की जाए। आपने अपनी बात कह ली अब आप इनकी बात सुनें। (तोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मांगे राम गुप्ता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एस.वाई.एल नहर की मुरम्मत के लिए 10 करोड़ निर्धारित किए गए हैं और इस बात से पूरा सदन सहमत होगा कि वह पैसा चौधरी बंसी लाल जी से वसूल करेंगे क्योंकि उन्होंने चीफ इंजीनियर के कहने के बावजूद भी उस नहर का गलत काम किया और वह टूट गई।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

(1) **चौ. बंसी लाल, एम.एल.ए.द्वारा—**

चौ. बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है कि मैंने कोई भी काम इंजीनियर की मर्जी के

खिलाफ नहीं किया । यदि वसूली करनी है तो मुख्य मंत्री जी से बादल के लड़के को जो जमीन दी गई उसकी की जाये ।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, इस जमीन के बारे में हाई कोर्ट का फैसला चौधरी बंसी लाल जी के समय में उनकी तरफ हुआ था इसलिए इसकी वसूली भी चौधरी बंसी लाल जी से की जानी चाहिए। चौधरी बंसी लाल जी लॉ ग्रेजुएट हैं, ये बोरी लेकर बैठते थे और 10-10 रूपये में दूसरों की वकालत करते थे लेकिन अपनी बात भूल गये हैं कि फैसला किसके समय में हुआ था ।

चौ. बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन पूरी नहीं हुई है। यह ठीक है कि इस बारे में हाई कोर्ट का फैसला मेरे वक्त में आया लेकिन मैं उस फैसले से संतुष्ट नहीं था। (Noise and interruption) I went to the Supreme Court. But what Supreme Court says in this case.... (Noise and interruption).

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी, अब बाप बैठिये आपकी पर्सनल एक्सप्लेनेशन पूरी हो गई है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी की बात जब सदन में नहीं मानी गई तो ये प्रैस में अपना मुद्दा छेड़ आये। जबकि इनको चीफ इंजीनियर ने कहा था कि नहर का काम मुड से भुरु किया जाये लेकिन इन्होंने काम

टेल से भुरु करवाया, बंसी लाल जी इसका स्पष्टीकरण दें। अध्यक्ष महोदय, एक सिस्टम बना हुआ है कि ड्रेन की खुदाई का काम टेल से होता है और नहर की खुदाई का काम मुड से भुरु किया जाता है। इन्होंने टेल से नहर का काम करवा कर वहां करोड़ों रुपये बरबाद कर दिये और अब ये यहां अपनी फजीहत करवा रहे हैं। वह पैसा इनसे वसूल होना चाहिए।

चौधरी बंसी लाल जी : अध्यक्ष महोदय, मैंने थू आउट एक साथ नहर पर काम भुरु करवाया था। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी प्लीज आप बैठें। चौधरी बंसी लाल जीकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाये। बंसी लाल जी इस बारे में आपका प्रोटैस्ट पहले दर्ज हो चुका है, प्लीज आप बैठें। (विधन) अगर आपने बजट पर बोलना है तो आप बोलें या एस.वाई.एल के बारे में कुछ उूसरी बात कहनी हैं तो कहें। टेल और मुड के बारे में कुछ कहना है तो कहें।(गोर एवं व्यवधान) गुप्ता जी प्लीज आप बैठें।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि एस.वाई.एल के बारे में कुछ कहना है तो कहें। मै एस.वाई.एल के बारेमें कुछ कहना चाहता हूँ। (गोर एवं व्यवधान)

वर्ष 2002–2003 के बजट पर सामान्य चर्चा(पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा। प्लीज आप बैठें।(गोर एवं व्यवधान) गुप्ता जी प्लीज आप

बैठे। सदन का समय बर्बाद न करें। प्लीज आप सभी बैठें मैंने हाउस को सूचित करना है।

सदन के सभी सम्मकनित सदस्यों की एफीं एंसी बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने सभी विधायकों को एक-एक लैपटॉप और प्रिंटर देने का निर्णय लिया था और सै उन के तुरंत बाद आप सभी स्पीकर के आफिस से उन्हें ले जा सकते हैं ताकि आप सभी की एफीं एंसी बढ़े। यह आपको गिफ्ट में दिए जा रहे हैं। आप उसमें लोगों की रिंकायतें दर्ज करें और आप सरकार को अच्छे सुझाव दें।(विधन) चौधरी भजन लाल जी लैपटॉप छोटे कम्प्यूटर को कहते हैं जो अटैची में आ जाता है। उसे जहां भी आप जायें वहां ले जा सकते है। 12 बजकर 15 मिनट पर सभी पार्टी लीडर्ज को ये कम्प्यूटर स्पीकर आफिस में दिए जायेंगे। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि यह बहुत की सराहनीय कार्य सरकार ने किया है।

वित्त मंत्री(प्रो. सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, आपके दिना निर्दे के हिसाब से ताकि सभी मैंबर्ज की एफीं एंसी बढ़े और सवाल मुफ्त का नहीं है,सवाल एफीं एंसी का है। इनसे मैंबर्ज की एफीं एंसी बढ़ेगी और आज के दिन एफीं एंसी बढ़ाने के लिए लैपटोप बहुत जरूरी है। स्पीकर सर, आपने सरकार को जो डायरेक्शन दी उसको सरकार ने जरूरी समझा और उसी हिसाब से सभी विधायको को लैपटॉप दिए जा रहे है। (गोर एवं व्यवधान)

चौ. जय प्रकाश : स्पीकर सर, सम्पत सिंह जी कह रहे हैं कि एफ़ी।।एंसि बढ़ेगी और आप कह रहे हैं कि मुफ्त दिए जायेंगे। यदि बाप अपने पैसे से खरीदकर देते तब हम मानते कि मुफ्त दिए जा रहे हैं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी आप जय प्रकाश जी को समझाओ, इनको कुछ सद्बुद्धि दो। (गोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, कम्प्यूटर के कार्य करने से एफ़ी।।एंसि बढ़ती है। मैम्बर्ज की एफ़ी।।एंसि बढ़ाने के लिए ही आपको दिना-निर्देश पर ये कम्प्यूटर दिए गए हैं। ये कम्प्यूटर स्पीकर सर की जेब से नहीं जा रहे, भजन लाल जीकी जेब से नहीं जा रहे हैं और न ही मेरी जेब से जा रहे हैं। इनके लिए सरकारी खजाने से पैसा जा रहा है। (गोर एवं विधन)क्या इसमें भी डिस्प्यूट आ गया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, मैम्बर्ज को जो लैपटॉप कम्प्यूटर दिए जा रहे हैं उनके बारे में मैं थोड़ी सी फ़दर जानकारी चाहता हूँ। अभी कई सदस्यों को कम्प्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है। हम चाहते हैं कि यदि मैम्बर्ज इन लैपटॉप कम्प्यूटर के बारे में और जानकारी जानना चाहेंगे या समझना चाहेंगे तो क्या उनकी मदद के लिए भी सरकार की तरफ से कोई अधिकारी कहीं पर बैठेगा जो विधायकों को पूरी जानकारी दे सके।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं थोड़ा-सा क्लीयर कर देता हूँ कि कोई सदस्य अगर इसके लिए अपने आपको एजुकेट करना चाहता है या अपनी जानकारी बढ़ाना चाहता है तो अच्छी बात है। हमारे यहां पर सचिवालय में 9वीं मंजिल पर आई.टी. सैक्टर का आफिस है। वहां पर हमारे हारट्रान की तरफ से ऐसपर्टस आते हैं। उनको जब आप कहेंगे आपको वे बताएंगे। स्पीकर साहब की तरफ से एम.एल.एज. को कम्प्यूटर की ट्रेनिंग के बारे में जितनी बार भी आदे ा हुआ है हमने वहां पर क्लासिज लगवायी हैं और यदि स्पीकर साहब या बाप लोग और क्लॉसिज लगवाने में लिए कहेंगे तो और क्लॉसिज लगवा देंगे। (विधन)

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, अप जो 9वीं मंजिल की बात कर रहे हैं इस बारे में मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप की सहमति हो तो हमको ट्रेनिंग देने का प्रबन्ध सचिवालय की 9वीं मंजिल की बजाये यहां पर विधान सभा में ही करवा दिया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहां पर मैम्बर्ज मीटिंग्स में भी आते हैं इसलिए उनको इस बारे में जानकारी लेने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आयेगी। 9वीं मंजिल पर चढ़ने में दिक्कत आती है। यदि यह सुविधा मैम्बर्ज को दे दी जाये तो सबको सहूलियत हो जायेगी। हमारे विपक्ष के साथियों को सचिवालय में जाना अच्छा नहीं लगता। (विधन)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब जो अनपार्लियामेंटरी भाब्द बोल रहे हैं वे रिकॉर्ड न किये जायें।

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, इस बारे में पहले से ही सचिवालय में अलग से एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्प किया हुआ है अगर फिर इतना सारा खर्चा करने के बाद उस सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर को उठाकर यहां वापस लेकर आयें यह संभव नहीं है। वहां जाने में क्या लम्बी चौड़ी बात है। अध्यक्ष महोदय, हम भी कोई कम्प्युटर एजुके इन जमाने के नहीं है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जब भी कोई सदस्य वहां पर जाकर सीखना चाहेगा, उसके लिए आपका बजट डिपैण्ड करता है। जो साथी इन्टरनेट कनेक्ट इन लेना नहीं चाहेगा तो उसके लिए उनको सी.डी.भी विधान सभा स्पीकर साहब के माध्यम से पहुंचा दी जायेगी ताकि उसका सभी सदस्य इस्तेमाल कर सके। स्पीकर साहब, यहां पर श्री मांगे राम गुप्ता जी ने गेहूं की खरीद के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने विशेषकर कैथल का जिक्र किया था कि गेहूं बाहर खराब हो रही है। (विधन)

श्री मांगे राम गुप्ता : मैंने तो यह कहा था कि पिछली फसल के कैथल और चीका मण्डियों के आढ़तियों के पैसे अभी तक नहीं दिये गये हैं।

प्रो. सम्पत सिंह : मैं इस बारे में भी बता दूंगा। साथ ही साथ मैं अपने याथियों का कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो

अच्छे काम किये हैं उनकी सराहना करनी चाहिए। पिछले सीजन में सरकार ने 64.07 लाख टन गेहूं की खरीद की थी। स्पीकर सर, आप जानते हैं कि अगर सरकार गेहूं न खरीदती तो क्या हालत होती।(विधन एवं भाोर) स्पीकर सर, इन्हें इस बात पर ऐतराज है।

चौ. जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय,

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, कैप्टन साहब आप बैठे।(विधन एवं भाोर) जय प्रकाश जी, आप बिना प्रश्नान के बोल रहे हैं इसलिए आप बैठें।(विधन एवं भाोर) इनकी कोई बात रिकॉर्ड न करें।(विधन) आप बता कुछ रहें हैं और ये कुछ और बोल रहे हैं। आप बैठ जाए।(विधन एवं भाोर)

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय नेता से निवेदन करूंगा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा आपके मैम्बरज बोलते रहे अच्छी तरह से उन्होंने सुझाव भी दिए मैंने उनको देखा है। (विधन एवं भाोर) बाकायदा उनको नोट किया है और जो बातें उन्होंने उठाई हैं उन्होंने जो प्वायंट्स उठाये हैं उनका जवाब तो आएगा ही। जो कुछ आप लोगों ने कहना था वे सारी बातें आपकी आ गयी है। स्पीकर साहब ने तो यहां तक कहा था कि अगर कोई और मैम्बर बोलना चाहे तो बोल लें। पूरा टाइम होने के बाद मैं जवाब दे रहा हूँ।(विधन एवं भाोर)

श्री राम किशन फोजी : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : फोजी साहब, आप बैठें (विधन),नो-नो, आपको इस बारे में कुछ पता नहीं है इसलिए आप बैठें।(विधन) इनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाए।

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इस बात को किसान अच्छी तरह से जानता है कि अगर सरकार गेहूं नहीं खरीदती तो गेहूं 610रूपये फी क्विंटल की बजाए 400 रूपए फी क्विंटल भी किसी ने नहीं पूछना था। स्पीकर सर, किसान का एक-एक दाना जो हरियाणा की मण्डी में आया हरियाणा सरकार ने बकायदा उसको खरीदा है यही कारण है कि 64 लाख 5 टन गेहूं की खरीद हुई है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक ये कह रहे हैं कि दूसरी स्टेट्स से गेहूं आया,स्पीकर सर,किसान का एक भी दाना ऐसा नहीं रहा जो वह बेचना चाहता हो और न खरीदा गया हो। यहां तक कि घर खर्च के लिए भी इस बार किसान ने अनाज नहीं रखा क्योंकि अनाज का दाम बहुत अच्छा मिल रहा था। अगर दूसरी स्टेट्स से भी गेहूं आया है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। किसी भी प्रदेश से अनाज कहीं भी बेचा जा सकता है आज स्टेट फ्री ट्रेड है और इस बार तो उल्टे बांस बरेली वाली बात हुई है। पहले हरियाणा का गेहूं नरेला की मण्डी में जा कर बिकता था लेकिन इस बार दिल्ली से भी गेहूं हरियाणा प्रदेश के अन्दर आया है। यह अच्छी खरीद का ही नतीजा है। स्पीकर सर, यहीं हालत गन्ने के अन्दर भी हुई है और 110/-रूपए फी-क्विंटल सरकार गन्ना खरीद रही है वरना गन्ने की तो बुरी हालत हुआ

करती थी और गन्ना सड़ा करता था। स्पीकर सर, यहीं चावल की खरीद की पोजिशन भी रही थी। 60 प्रतिशत से ज्यादा चावल हरियाणा सरकार ने खरीदा है। हरियाणा सरकार किसान हितैशी सरकार है। (विधन)अध्यक्ष महोदय, इनको अब क्या तकलीफ हो रही है।

चौ. जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आपका किस बात का प्वायंट ऑफ ऑर्डर है, आप बैठें (विधन) जय प्रकाश जी, आप अपनी सीट पर बैठें। इनकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं की जाए।

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैंने यही कहा है कि यह किसान की बैहबूदी की बात थी। इस खरीद की वजह से एक तरफ तो किसान के घर में आमदनी आई दूसरी तरफ मण्डी बोर्ड को फीस भी फालतू आई, एच.आर.जी.एफ. भी इस वजह से फालतू आया और आढ़तियों को आढ़त भी ज्यादा मिली। किसान को फायदा हुआ, दुकानदार को फायदा हुआ, सरकार को फायदा हुआ, मण्डी बोर्ड को फायदा हुआ और इस पैसे से प्रदेश का विकास हो सकेगा। स्पीकर सर, सब लोगों को हर वर्ग को इस खरीद की खरीद की वजह से आज फायदा हुआ है। स्पीकर सर, ये लोग कहते हैं कि 10 लाख टन गेहूं खराब हो गई। मैं इन को बताना चाहता हूँ कि 10 लाख टन ये लोग कहते हैं जब कि जबकि केवल

214 टन हरियाणा वेयरहाउसिंग निगम की गेहूं करे छोड़ कर और कोई गेहूं कहीं पर खराब नहीं हुआ। करीब 64 लाख टन में से सिर्फ 214 टन गेहूं खराब हुई है। स्पीकर सर, जो गेहूं खराब हुई है वह भी घाटा हम सहेंगे लेकिन किसान को नहीं मरने देंगे और किसान को जिन्दा रखेंगे। (विधन) (इस समय मेजें थपथपाई गई)। दूसरे स्पीकर सर, कैथल में व्यापारियों के बारे में मांगे राम गुप्ताजी ने जिक्र किया था। कैथल में व्यापारियों की जहां तक बात करते हैं, खरीद के बारे में सरकार के सामने जिक्र आया था स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने इसकी इन्क्वायरी की। इन्क्वायरी कम्पलीट होने से पहले उनकी अदायगी कैसे की जा सकती है। अब विजिलेंस विभाग ने अपनी जांच इसके आधार पर 18 व्यापारी दोशी पाए गए हैं। हो सकता है मंगे राम जी को पीड़ा हो रही है वैसे इन 18 में से उनका अपना तो कोई नहीं होना चाहिए। विभाग द्वारा इसकी एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जा चुकी है और सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो दोशी पाए गए हैं उनके खिलाफ तो कार्यवाही होगीबौर भोश अदायगी बकायदा कर दी जाएगी। कोई पेमेंट उनकी नहीं रोकी जाएगी। स्पीकर सर, उनकी पेमेंट हो भी गई है। अगर किसी की पेमेंट रह गई है तो ये बता दें उनकी भी पेमेंट कर दी जाएगी। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि जिनकी इन्क्वायरी हो चुकी है उन सब की पेमेंट कर दी गई है।लेकिन जो इस इन्क्वायरी में दोशी पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और उनसे वसूली भी की जाएगी। स्पीकर सर, इसके अलावा यहां पर फूड

लाइसेंस के बारे में जिक्र किया गया है। यह बात ठीक है कि भारत सरकार की तरफ से फूड लाइसेंस रद्द करने के बारे में आदे प्राप्त हो चुका है। इन आदे गों को एग्जामिन किया जा रहा है और उसके बाद की ही इस बारे में कार्यवाही की जाएगी। (भागेर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं यहां पर कृष्ण पाल गुर्जर जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि भुक्र है कि ये यहां पर बैठे हुए हैं वरना क्या होता था कि ये सदन में बोलकर चले जाते थे, दोबारा आते थे और बोलते थें और फिर से सदन से चले जाते थे। इन्होंने सदन में खानों का जिक्र किया। मैं खानों का ज्यादा यहां पर जिक्र नहीं करना चाहूंगा। कल किसी साथी के द्वारा सदन में इस बारे में सारी बात बता दी थी कि किसी पार्टी के राज में, किसी पार्टी के मैम्बरज ने, किस पार्टी के किस सदस्य ने किसी मंत्री ने कितनी खानें लीं और कितनी खानें किस-किस को दी, क्या दिया, क्या लिया मैं इस बारे में कोई जिक्र नहीं करूंगा। मैं यहां पर किसी व्यक्ति पर कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहूंगा। स्पीकर सर, भायद श्री रामबीर सिंह (पटौदी) ने इस बारे में सारा जिक्र कर दिया था कि किस सरकार के वक्त में कौन-कौन मंत्री था और किस-किस केस में किस मंत्री की पार्टनरिप थी। स्पीकर सर, बहुत से मंत्रियों ने इस बारे में यहां पर मान भी लिया हैं। (भागेर एवं व्यवधान) मैं किसी का पर्सनली जिक्र नहीं कर रहा हूँ। स्पीकर सर, रामबीर सिंह जी ने जो जिक्र किया था मैं उस बारे में यहां पर रिपीट नहीं करूंगा। स्पीकर सर, कृष्ण पाल गुर्जर जी उस समय यहां पर नहीं थे अगर ये होते तो इनको सन्तुष्टि

हो जाती कि कौन-कौन आदमी उसमें शामिल थे। इसके बाद इन्होंने यहां पर खानों की टेंडरों की पॉलिसी का भी जिक्र कर दिया। स्पीकर सर, इस सरकार की टेंडरों की पॉलिसी बहुत ही सराहनीय है उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है। स्पीकर सर, पहले क्या होता था कि जो खान के मालिक थे वे सरकार के रहमोकर्म पर थे उस समय क्या होता था एप्लीकेशन देने के बाद जो व्यक्ति सरकार के अधिकारियों को यह राजनीतिज्ञों को मोटा पैसा दे देता था केवल उनको ही खानें दी जाती थी। (भाोर एवं व्यवधान) मैरिट की उस वक्त कोई बात ही नहीं थी। अगर ये मैरिट की बात करेगे तो मेरे परस यहां पर कोर्ट का केस पड़ा हुआ है जिस बारे में कोर्ट ने फैसला भी दे दिया है अगर मैं उस बारे में यहां पर सुना दूंगा तो यहां पर किसी मैम्बर को पीड़ा हो जाएगी। मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि उस वक्त कोई मैरिट नहीं होती थी। पैसे का लेन-देन होता था और उससे सरकारी खजाने का नुकसान होता था और केवल मात्र 17 करोड़ रुपये की ही खानों से आमदनी होती थी। स्पीकर सर, मौजूदा सरकार ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अध्यक्षता में एक फैसला लिया है उस फैसले की वजह से आज 65 करोड़ रुपये की सरकार को आमदनी हुई है। इसके अलावा जो रायल्टी निर्दिष्ट की गई है। (भाोर एवं व्यवधान) आप मेरी बात सुन तो लें। रायल्टी के लिए जो अमाउन्ट फिक्स की गई है और जितनी मात्रा माल की निमालने के लिए फिक्स की गई है अगर कोई उससे ज्यादा मैटीरियल कोई निकालेगा तो उस पर उसको उतना पैसा देना पड़ेगा। इसके

अलावा उसके ऊपर सेल्ज टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। स्पीकर सर, कितने ही करोड़ों का फायदा इससे होगा और इस पैसे से कितना हरियाणा का विकास होगा। स्पीकर सर, 17 करोड़ और 65 करोड़ के बीच का जो पैसा है मुझे हिसाब नहीं आता है इस बारे में मांगे राम जी बता देंगे भायद यह 48 करोड़ के करीब बनता है और ये 70-80 करोड़ रूपए और सेल्ज टैक्स मिला करके करीबन-करीबन 70-80 करोड़ रूपए बनते हैं और ये 70-80 करोड़ रूपए कहां जाते थे। उस वक्त जो सरकारी पदों पर लोग थे और जो उस वक्त के राजनीतिक लोग थे उन लोगों के यारे-प्यारे और रि तेदार थे उनकी जेबों में जाते थे। (भाोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, आज इनको इस बात से तकलीफ हो रही है कि इस पैसे को लोगों के हितों के लिए क्यों खर्च किया जा रहा है। इनके समय में यह पैसा व्यक्ति वि ेश के लिए खर्च हो रहा था और इन लोगों से जुड़े हुए लोगों के लिए खर्च हो रहा था इसलिए आज इनको इस बात से तकलीफ हो रही है। (भाोर एवं व्यवधान)

चौ. बंसी लाल :

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए।

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, चौधरी बंसी लाल जी ने जो खानक के बारे में कहा है तो मैं इनको यह बताना चाहूंगा कि चौधरी बंसी लाल जी आपके समय में आपने आमदनी बढ़ाने के

लिए 30 लाख को 50 लाख करने की कोशिश की थी। जोकि आप बढ़ा नहीं पाए थे। उसके ऊपर भी आपको पता है कि प्रोटैस्ट हुए थे और वह प्रोटैस्ट आपने खुद ही करवाया था। वहां पर जो निर्दाश लोग थे उन लोगों के साथ मारपीट की गई थी, उनको अन्दर करवाया गया था, ट्रैक्टर जला दिए गए थे, फूंक दिए गए थे। उनके खेतों को जला दिया गया था और घरों को भी फूंक दिया गया था। स्पीकर सर, इतना जबरदस्त वहां पर हंगामा हुआ था। (भाोर एवं व्यवधान) मैं आपको एफ.आई. आर. का नम्बर भी ला दूंगा और आपको उसकी नकल भी ला कर दे सकता हूँ। (भाोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी मुनकर हो रहे हैं। तीन महीने तक लॉ एंड ऑर्डर मफलूज हो गया था। लेकिन जब बाद में उनसे इनकी सौदेबाजी हो गयी तो सौदेबाजी पटने के बाद फिर उन्हीं लोगों को खानें दं दी गयी। स्वयं बंसीलाल जी ने तसलीम किया है कि इनके बाद भाई रघुबीर सिंह वल्द मोहरसिंह की उसमें पार्टनरशिप रहीं हैं। कहा पहले साल में उस खान से चालीस हजार रुपये आते थे और कहां अब सात करोड़ वसूल किए जा रहे हैं। इनको इस बात के लिए लेना मात्र भी भार्म नहीं आ रही है।

चौ. बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय मैंने एक बात कही है। ठीक है कि दांग

के उस पहाड़ में मेरा भाई पार्टनर था लेकिन उसमें कोई बेईमानी नहीं हुई, किसी किस्म का कोई दो नम्बर का पैसा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, फिर यह रैवेन्यू क्यों कम लिया था ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये चालीस हजार रूपये में हर साल ठेका उसको देते थे और अब फिर भी ये कह रहे हैं कि इसमें बेईमानी नहीं हुई। यह तो रिकॉर्ड कह रहा है कि चालीस रूपये में ठेका हर साल में ये उसको दे देते थे।

चौ. बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात को कहने दो। मैं प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा हूँ।

श्री अध्यक्ष : इसमें क्या प्वायंट ऑफ ऑर्डर है ?

चौ. बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, पहली बात यह है कि जो रोड़ी पहले चार सौ या पांच सौ रूपये में मिलती थी एक गरीब आदमी का एक कमरा डालने के लिए वहीं अब वह ढाई हजार या तीन हजार रूपये में मिलती है। इसमें गरीब मरा है।

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, आपको प्रदे 1 के एक्सचेंजर की क्या कोई चिन्ता नहीं है अगर प्रदे 1 की आमदनी बढ़े तो क्या यह अच्छा नहीं है ? अब आप बैठें।

चौ. बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि खानक की जो खानें हैं इन खानों के 15 लाख रूपये रोज

का साढ़े चार करोड़ रूपये महीने का किसकी जेब में जा रहा है, कहां जा रहा है। एक-एक माल का दो-दो जगहों पर सेल्ज टैक्स लिया जाता है और यह टैक्स भी टोल टैक्स के तौर पर लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी, अब आप बैठें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी कह रहे हैं कि चार सौ रूपये को ट्राली रूपये प्रति टन के हिसाब से सरकार रायल्टी लेती है। फिर उसमें से उस पर बीस परसेंट सेल्ज टैक्स मिलता है और फिर क्रै 11 जो रोड़ी बनाकर बेचते हैं उस पर भी 12 परसेंट सेल्ज टैक्स वे देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन दोनों लोगों के समय में तो यह बीस परसेंट टैक्स लोगों की जेबों में जाता था अब यह सरकार के खजाने में आ रहा है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, िकायत मिलने के बाद जो पुराना ठग्गी टोरी का पैसा था उसमें से भी सरकार ने 80 लाख रूपया वसूल किया है। मैंने पहले भी सदन में कहा था और अब फिर कह रहा हूँ कि दस साल तक जिन लोगों ने वह बीस परसेंट टैक्स लूटा है उनसे भी वह वसूल किया जाएगा।

श्री चौ. बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है।

श्री अध्यक्ष : आप किस आत की पर्सनल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं आपसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुख्य मंत्री जी ने

आपसे निजी तौर पर कुछ नहीं कहा वे तो प्रदेश की पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं।

चौ. बंसी लाल : आप मेरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष : नहीं—नहीं अब आप बैठें। अब बंसी लाल जी जो बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न करें।

चौ. बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, (भाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी आप बैठिए। दलाल साहब आप भी बैठें।(भाोर एवं व्यवधान)

श्री धर्मवीर सिंह : जो वहां पर हजारों रूपये का गबन हुआ है उसके बारे में भी इनको बताना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : धर्मवीर जी की कोई बात रिकॉर्ड न करें।(भाोर एवं व्यवधान)

श्री राम किान फोजी : स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनें। वह मेरे हल्के का पहाड़ है।(भाोर एवं व्यवधान) मेरे हल्के के लोगों की तसल्ली जोनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जब इंकवायरी होगी तो आपके हल्के के लोगों की तसल्ली हो जाएगी। पुराने हिसाब—किताब की सारी इंकवायरी हो जाएगी। आप बैठें।

श्री धर्मवीर सिंह : स्पीकर साहब, हम चाहते हैं कि इस बारे में मैम्बर्ज की एक कमेटी बनाकर वहां भेज दी जाए वह जाकर इस बारेमें इंक्वायरी कर लें।

श्री अध्यक्ष : धर्मवीर जी, अब आप बैठें।

चौ. बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, जब से हरियाणा बना तब से लेकर अब तक की दी हुई सभी खानों की इंक्वायरी सी.बी. आई.को दे दे सबका फैसला हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : अब बंसी लाल जी की कोई बात रिकॉर्ड न करें।

चौ. बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय,

Prof. Sampat Singh : Speaker Sir, our Vigilance Department is competent enough to enquire in this matter
और इस मामले की इंक्वायरी के लिए मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दे ही दिया है कि विजिले।स से उसकी इंक्वायरी करवायी जा रही है। यह किसी व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है जो भी इसमें दोषी होगा उससे बाकायदा रिकवरी तो होनी ही चाहिए।(भाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्टेट पुलिस पर भी भरोसा करें।

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर,अब ये खानों का जिक्र आ गया, इसमें अपनी बात कहते हुए कृष्ण पाल जी धौज और

नाथूपुर का जिक्र कर गए कि ऑक्शन कॉलिसी लागू होने के बाद इनको लीज पर दिया गया। स्पीकर सर, तथ्यों को जानने से पहले कोई आदमी यह बात करजा है वि शेरकर कृष्ण पाल जी ऐसी बात करें जो कि मंत्री रह चुके है और एक नै नल लैवल की पार्टी के लीडर हैं तो इनको सदन में ऐसी बात कहना भाभा नहीं देता है। मैं आपको तथ्य बताना चाहता हूँ कि ऑक्शन पॉलिसी 28-9-2001 को एनाउंस हुई थी। The State Government announced his new Auction Policy on 28-9-2001. आप तारीख नोट कर लें, नाथूपुर और धौज का जहां तक सवाल है इन लोगों ने ऐप्लाइड इससे हपले किया, इनके इन्टरव्यू का बता देता हूँ। अक्टूबर 2000 में इनके इन्टरव्यू हुए। ऑलमोस्ट ए साल पहले इन्टरव्यू हो चुके थे। यह पॉलिसी से 9 महीने पहले लैटर ऑफ इंडेंट दिया जा चुका था। ये डेट्स मैंने आपको दी हैं उसने बाद कहते हैं कि सरकार ने ऑक्शन पॉलिसी के बादमें उनको लीज पर दे दी। बेबुनियाद बात करना आपको भाभा नहीं देता।(भाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृष्ण पाल जी आप बैठ जाएं।(भाोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बताने का काम वित्त मंत्री जी का है आप बैठ जाएं। आए अपनी बात कह चुके हैं आप बैठ जाएं।(भाोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पाल : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : कृष्ण पाल की कोई बात रिकॉर्ड न की जाए। कृष्ण पाल जी, आपका नाम नहीं लिया।(भाोर एवं व्यवधान)

चौ.भजन लाल : अध्यक्ष महोदय,

श्री ओम प्रका । चौटाला : चौधरी भजन लाल जी, आप तो जिम्मेदार आदमी हैं जो कोई सम्मानित सदस्य इस सदन में बोलेगा जवाब देते समय उसका उल्लेख तो किया ही जाएगा। जिस आदमी ने बाकायदगियों से तथ्यों पर आधारित बात कही हो और अनर्गल और बेबुनियाद बातें इस सदन में कह कर चला जाए। हुड्डा के बारे में इन्होंने बात कह दी और जब उस बारे में धीर पाल जी स्पष्टीकरण दे रहे थे तब ये सदन में नहीं थे। आज तो ये संयोग से फंस गए इसलिए इनको पीड़ा होती है। भजन लाल जी, आपको तो पता होना चाहिए कि जिस बात का सदन में उल्लेख किया जाता है उस बात का जवाब रिप्लाय में दिया जाता है।

श्री कृष्ण पाल : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : कृष्ण पाल जी की कोई बात रिकॉर्ड न की जाए। आप बैठ जाएं। (भाोर एवं व्यवधान) आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। इररैलेवैंट बात करना भाोभा नहीं देता है। आप बैठ जाएं।(भाोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अब मैंने स्पष्ट तारीख विद फैक्ट्स बता दी है किसी भी जिम्मेदार सदस्य को ऐसी अनर्गल बातें जो सत्य न हों, हाउस में नहीं कहनी चाहिए।(भाोर एवं व्यवधान)इसी तरह से कादयान साहब ने और कर्ण सिंह दलाल ने एक जो राय दी थी साथ में समस्या बताई थी उसे मैं ऐप्रीि एट करता हूँ उन्होंने डब्ल्यू.टी.ओ. और क्रॉप के डाइवर्सिफिके ान का जिक्र किया था। आज इस चीज की जरूरत है कि इस की तरफ ध्यान दिया जाए और क्रॉप के डाइवर्सिफिके ान किया जाए उसके लिए सरकार ने प्रयास किए हैं लेकिन वह प्रयास अभी अपर्याप्त हैं और सरकार को उससे ज्यादा प्रयास करने चाहिए और उन प्रयासों को करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और करेगी भी जैसा कि पहल कादयान साहब और दलाल साहब ने कहा था। स्पीकर सर, साठी की फसल पहले 85 हजार हैक्टेयर में होती थी। बाद में किसानों को समझाया गया कि इसमें आमदनी नहीं होती आप दूसी फसलों की तरफ जायें उसके बारे में किसानों को समझाने के बाद वह फसल 25 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में रह गई हैं। पैडी क्रॉप 10.45 लाख हैक्टेयर से 10.24 लाख हैक्टेयर रह गई है इसकी डाइवर्सिफिके ान की गई

है। उसमें काटन, भुगरकेन, मंज की क्रॉप, पलिसज, गुड, हाई वैल्यू बेसड क्रॉप्स जैसे बासमती राइस, वैजीटेबल, फ्रूट इन सब का एरिया इनक्रीज किया है ताकि इनकी अच्छी प्राइस मिल सके। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का प्रोग्राम अण्डर प्रोसेसिंग चल रहा है। भाहा, डगवाली, राई, नरवाला और झज्जर में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जायेंगे क्योंकि फूड प्रोसेसिंग प्लांट अगर नहीं लगाए जाएं तो चाहु किसान कितना अच्छा बीज भी लेता है और उसे फसल का मूल्य भी न मिले तो किसान को क्या फायदा होगा। इसके बारे में सरकार बाकायदा चिन्तित है और सरकार पूरा ध्यान दे रही है इसी तरह से टि यू कल्चर की तीन लैब काम कर रही हैं हरियाणा राज्य में गन्ना के उत्पादन को बढ़ाने के लिए टि यू कल्चर पांच वर्शों से अपलाई जा रही हैं वर्तमान में तीन कल्चर लैबज है। दो तो हिसार में और एक करनाल में चलाई जा रही हैं। बाकायदा सरकार का इस तरफ पूरा ध्यान है। स्पीकर सर, बाकी जो प्वायंट्स कवर नहीं है वह बताना चाहूंगा इन्होंने जो यमुनानगरके उप चुनाव का जिक्र किया। स्पीकर सर, हर आदमी मानता है कि यह उपचुनाव तो सरकार के कार्यों के प्रति मेनडेट था। उसके बारे में फालतू चर्चा नहीं करना चाहता (गोर)। उसी की वजह से इन्होंने उपचुनाव का अपने आप जिक्र किया क्योंकि उसकी वजह से यं हता हो चुके हैं और हता हो के कारण बौखला गये हैं। बजट एड्रेस पर बोलते समय वाक आउट करने का इनका कोई मतलब नहीं बनता है। वह मार जो यमुनानगर के लोगों ने इनको मारी है वह मार इनको रात को

सपने में दिखाई देती है। कोई नम्बर एक पर आने के लिए और कोई नम्बर दो पर आने की बात कहते थे।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : जो बंसी लाल जी कह रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाये।

प्रो. सम्पत सिंह : इन्होंने यहां पर यह भी मं ता जाहिर की कि जिस राज के अन्दर बाइ इलैक् ान होते है उस राज की पार्टी ही जीतती है। स्पीकर सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनको याद कराऊं कि 1974 में ठीक अमरजैंसी लगने से पहले जब चौधरी बंसी लाल जी आपका राज था और रोड़ी का उप चुनाव हुआ था उस समय चौधरी देवीलाल जी आजाद उम्मीदवार के रूप में आपकी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़कर 29 हजार वोटों से जीत कर आये थे और आपके रि तेदार उस चुनाव में लड़ रहे थे।

श्री बंसी लाल : मैंने गवर्नमेंट की म िनरी का मिसयुज नहीं किया था जैसे यमुनानगर में इस सरकार ने किया है। मैंने फेयर इलैक् ान करवाया था और यमुनानगरमें फेयर नाम की कोई चीज नहीं थी।

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, उस चुनाव के बारे मे मैं आपको बताऊं उस चुनाव में जिस प्रकार चौधरी बंसी लाल ने प्रचार किया था चौधरी देवी लाल जी ने यह चुनाव लोगों को यह

कहकर लड़ा था कि मैं एम.एल.ए. बनने के लिए चुनाव लहीं लड़ रहा मैं तो जो लोगोंने मुँह पर तालाबन्दी लगा रखी है उसको खोलने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। उन्होंने यह भी कहा था कि कोई गाड़ी न ले कर जाये कोई कहीं न जाये, मैं घर-घर अकेला जाऊंगा,कोई झण्डा नहीं लगाये यह कहकर चौधरी देवी लाल जी वह चुनाव जीतकर आये थे और लोगों की तालाबन्दी को खोला था।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मंत्री का दुरुपयोग नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष : चौधरी बंसी लाल जी, आप बैठिये। यह गलत बात है कि आप बीच में खड़े हो जाते हैं।

प्रो. सम्पत सिंह : दूसरे चुनाव भी आपको याद करवा दूँ। चौधरी भजन लाल जी 1993 में जब मुख्य मंत्री थे तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नरवाना से चुनाव जीता था और आपकी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त करवाई थी (भाोर एवं व्यवधान)

चौ. जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत है। नरवाना में ऐसा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने तो उन्हीं चुनावों का जिक्र किया है जो सरकार के खिलाफ लड़कर जीते हैं। चौधरी बंसी लाल जी आप को भायद ध्यान नहीं आप तो बतौर मुख्य मंत्री होते हुए हारे हैं।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, वह भी इनका ही राज था आप बेइमानी करके जीते थे लेकिन इलैक्ट्रान पैटी इन में आप केस हार गये हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, धर्मवीर जी बता देंगे कि क्या कोई बेइमानी हुई थी।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप तो चीफ मिनिस्टर थे तब भी हार गये। धर्मवीर जी आप खड़े होकर बताओ कि बेइमानी हुई थी या नहीं।

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, उस उप चुनाव में कोई बेइमानी नहीं हुई थी।

श्री बंसी लाल :

श्री अध्यक्ष : बंसी लाल जी की कोई बात रिकॉर्ड न की जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : बंसी लाल जी, अगर बंकायदगी का जिक्र करते हो तो आज जनाब ने मुख्य मंत्री के तौर पर चुनाव लड़ा और 90 परसेंट पोल हुए।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो गया भी नहीं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : बंसी लाल जी, आप तो नहीं गए लेकिन 98 परसेंट पोल हुए हैं या नहीं ये बता दो यह हिन्दुस्तान के इतिहास में रिकॉर्ड है कि कहीं 98 परसेंट पोल हुए हैं। किस बात पर तो टिकोगे, किसी बात पर तो आओगे, कहीं तो कुछ मानोगे।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह 1985-86 में महम के बाइ इलैक्शन में इनके राज में हम जीते। 1998 में फतेहाबाद में बाइ इलैक्शन हुए उस समय में छोटा-सा कार्यकर्ता था और मैं भी सरकार के सामने जीता था। अध्यक्ष महोदय, सवाल सरकार या बेसरकार का नहीं है। सरकार का पॉपुलर होना तो सरकार की नीतियों पर होता है। ये बोखला गए हैं, ये गवर्नर एंड्रैस और बजट पर जो कुछ कहना चाहते थे, वह नहीं कह रहे हैं, इस हार से प्रभावित होकर इनके मुंह से कुछ और ही निकल रहा है। अध्यक्ष महोदय, बंसी लाल जी ने जिक्र किया कि हुडको की ब्याज की दर ज्यादा है, वर्ल्ड बैंक से कर्जा क्यों नहीं लिया। चौधरी साहब, आपको मालूम है कि सैंक्शन लग गई थी और सैंक्शन लगने के बाद भी वर्ल्ड बैंक का कर्जा आपको नहीं मिला, वर्ल्ड बैंक से कर्जा न मिलने के कारण क्या वे सड़के जिनमें 6-6 फूट के गढ़े हो गए थे उनको ऐसे ही छोड़ देते, हमने इसलिए हुडको से कर्जा लिया और स्पीकर सर, ब्याज पर पैसा भी उसी को मिलता है जिसके बारे में पता होता है कि इससे पैसा

वापिस आएगा। अध्यक्ष महोदय, सड़कें अच्छी बनेंगी तो बसें उस पर ज्यादा चलेंगी, ट्रैफिक उन पर ज्यादा चलेगा, उससे स्टेट को पैसा आएगा, स्टेट का विकास होगा और इससे कर्ज के पैसे को भी हम वापिस कर सकेंगे।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूँगा कि क्या उन सड़कों पर कोई मैटीरियल भी डलवाया गया है।

प्रो. सम्पत सिंह : बंसी लाल जी, आप लिखकर भेज दें कहीं मैटीरियल डलवाना होगा तो हम वहां पर मैटीरियल डलवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बिजली का जिक्र करते हुए कहा कि नलकूपों की संख्या पहले से कम हुई है और आपकी सरकार कर रही है कि 10 हजार नलकूप बढ़ गए हैं। इसके साथ ही इन्होंने यह कहा कि बिजली महंगी कर दी। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जहां खारा पानी हो जाता है या नहरी पानी पूरा मिल जाता है वहां के लोग नलकूपों के कनेक्ट इन डिस कनेक्ट करवा लेते हैं। ये एक दिन के आंकड़े नहीं चल रहे, ये हर साल के आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा जो आता है वह हर साल आता है। कई बार जो बिल की अदायगी नहीं करता है उनके भी कनेक्ट इन काटे जाते हैं। बात यह है कि मौजूदा वर्ष में कितनी अचीवमेंट्स की गई हैं तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि 10 हजार ट्यूबवैल्ज के कनेक्ट इन पिछले साल बौर 10 हजार कनेक्ट इन इस साल सरकार ने दिए हैं जबकि इनकी सरकार ने 10 सालों में भी इतने

कनैव उन नहीं दिए होंगे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के रेटों पर आता हूँ। मैं सारे हिन्दुस्तान में बिजली के टैरिफ के बारे में बता देता हूँ। पंजाब में कृषि के लिए बिजली फ्री है, आंध्र प्रदेश में ऑलमोस्ट फ्री है।

चौ. जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में भी फ्री है, वह भी बता दें। (भाोर एवं व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि हिन्दुस्तान में बाकी स्टेट्स में मुकाबले हरियाणा में कृषि का टैरिफ कम है। ये आंकड़े मैं बता रहा हूँ। आसाम में कांग्रेस की सरकार है वहां पर कृषि पर बिजली का रेट 2 रूपये 70 पैसे प्रति यूनिट, वैस्ट बंगाल में 1 रूपया 83 पैसे, उड़ीसा में 1 रूपया 10 पैसे, मध्य प्रदेश में ये कह रहे थे कि फ्री है तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि पहले 1 रूपया 20 पैसे था लेकिन अब 50 पैसे घटाकर 70 पैसे कर दिया गया है, राजस्थान में भायद कांग्रेस की सरकार है वहां 90 पैसे प्रति यूनिट, कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है वहां 80 पैसे प्रति यूनिट, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार है वहां पर 75 पैसे प्रति यूनिट, उत्तर प्रदेश में 70 पैसे, केरला में 95 पैसे, तमिलनाडु में 50 पैसे, हिमाचल प्रदेश में 50 पैसे और गुजरात में बी.जे.पी. की सरकार है वहां 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली का रेट है। जबकि हरियाणा में किसानों को 45 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सिंचाई के लिए बिजली दी जाती है जो दे

में सबसे सस्ती है, पंजाब को छोड़कर क्योंकि पंजाब में तो किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाती है। (भाोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, हमारी किसान को 8 घंटे हर रोज बिजली देती है और जहां दूसरे राज्यों में कांग्रेस की सरकार हैं वहां किसानों को 2 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज बैठिये—बैठिये

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह सारा झूठ का पुलिंदा है। (भाोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राम भगत जी प्लीज आप बैठें। (भाोर एवं व्यवधान)

राव इन्द्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो ये 45 पैसे बता रहे हैं ये प्रति हार्सपावर वसूल किए जाते हैं या पर यूनिट। यह तो क्लीयर करें। (भाोर एवं व्यवधान)

Prof. Sampat Singh : Speaker Sir, this is not a question hour but i repeat again

कि हरियाणा में किसान से 45 पैसे प्रति युनिट के हिसाब से बिजली का बिल वसूल किया जाता है। इसके अतिनिवत चौधरी बंसी लाल जी ने जिक्र किया था कि साईबर सिटी का काम प्राइवेट सैक्टर में क्यों दिया गया है। यदि यह काम हुड्डा या एच.एस.आई.डी.सी. से सरकार करवाती तो 300 करोड़ रुपये

सरकार के बच जाते। इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी से प्राइवेट सैक्टर को साईबर सिटी का काम दिया है और हमारी सरकार राईट ऑफ वे की नीति भी लाई है इसमें एक दो कंपनीज आई है। (भाोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, इन्होंने न तो कुछ किया और न हमें करने देना चाहते। जिस समय हमारी सरकार आई उस समय हरियाणा प्रदे 1 कि आई.टी. सैक्टर मे बहुत बुरी हालत थी और इनकी गलत नीतियों की वजह से आंध्र प्रदे 1 तथा कर्नाटक आई.टी. क्षेत्र में हमारे से आगे निकल गए। हम चाहते है कि हमारे पुराने संस्कार रहे लेकिन हम यह नहीं चाहते कि हम आधुनिकी करण की तरफ न बढे। हम चाहते है कि अपने पुराने संस्कारों के साथ आधुनिकी करण की तरफ बढे और यहीं हमारी सरकार ने किया है। Private participation that is must स्पीकर सर, आई.टी. क्षेत्र में यदि आंध्र प्रदे 1 और कर्नाटक हमारे से आगे है तो वे सिर्फ प्राइवेट पार्टीसिपे 1 न करके आगे आए है। स्पीकर सर, हमारी आई.टी. नीति में पूरी ट्रांसप्रेेंसी है और यदि विपक्ष का कोई भाई साईबर सिटी का लाईसैंस लेना चाहता है तो वह अपलाई कर दें। यदि नॉर्मर्ज पूरा करता होगा तो हम उसे जरूर लाईसैंस देंगे। स्पीकर सर, प्राइवेट पाटीसिपे 1 न से सरकार को नुकसान नहीं हुआ है इससे सरकार को फायदा होगा।

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, इससे सरकार को तीन सौ करोड़ का नुकसान होगा।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, बंसी लाल जी भी अपलाई कर दें यदि ये नामर्ज पूरे करते होंगे तो इन्हे भी साईबर सिटी का लाईसैंस दे दिया जाएगा।

श्री धर्मवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : धर्मवीर जी, जो कुछ कह रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाए।

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, हमने साईबर सिटी का लाईसैंस देने के लिए बकायदा रूलज बनाए हैं, रैगुले ांज बनाए हैं तथा लाईसैंस मंजूर करने के लिए नामर्ज फिक्स किए गए हैं। यह एक खुली नीति है यदि इस में दस पार्टी आना चाहेगी और वे नामर्ज पूरा करती होंगी तो हम दस की दस पार्टियों को लाईसैंस दे देंगे इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। स्पीकर सर, हम साईबर सिटी ही नहीं बल्कि मैडी सिटी भी बनाने जा रहे हैं। फिर ये कहेंगे कि मैडी सिटी क्यों बनाई जा रही है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।) डिप्टी स्पीकर सर, आज के दिन मैडीकेयर की बहुत आव यकता है। आप तो जानते हैं कि हमारे हरियाणा में कितने अच्छे मैडीकल हॉस्पिटल हैं और कितने पांच सितारा होटल हैं। जब तक ये चीजें हरियाणा में नहीं आएंगी तब तक रोजगार नहीं बढ़ेगा, व्यापार नहीं बढ़ेगा, विकास नहीं होगा इस लिए इनका आना जरूरी है। डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने ऑन लाईन लाटरी का भी जिक्र किया है। (भाोर एवं विधन) डिप्टी

स्पीकर साहब, जो ऑन लाईन लाटरी का सवाल यहां पर उठाया गया है उस बारे में मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी मैजोरिटी स्टेट्स में लाटरी चल रही है। यह एक ह्यूमन नेचर है। (भाोर एवं विधन) चौधरी बंसी लाल जी ने भाराब को रोकने के लिए ट्राई किया था। हम सब मानते हैं कि भाराब पीना बुरी बात है। इसमें कोई दो राय नहीं की हर आदमी मानता है कि भाराब की लत बहुत बुरी लत है। लोगों का भाराब पीना कानून द्वारा बन्द नहीं कराया जा सकता। चौधरी साहब, आपने कानून द्वारा इसे बंद करने के लिए प्रयास करके देख लिया। उसके क्या नतीजे हुए वे भी आपने देख लिए। (भाोर एवं विधन) अमेरिका में फिंकागो में भी भाराब बंद की गई थी। आज भी फिंकागो भाहर में क्राईम रेट कम नहीं आया है। कानून बनाकर जहां भी भाराब बंद की गई, उसके ठीक परिणाम नहीं निकले। जैसे हालात फिंकागो में हुए थे, वहीं हालात हरियाणा प्रदेश में भी हुए हैं। ये लोग तो उन हालातों को छोड़ कर चले गए लेकिन हम उनको भुगत रहे हैं। भाराब को बंद करने की वजह के नतीजे यह निकले कि हमारे न जाने कितने नौजवान भटक गए। (भाोर एवं विधन) उस समय भी लोगों ने भाराब पी और बहुत ज्यादा पीं जिससे स्टेट को करोड़ों रूपए का नुकसान हुआ। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इनसे पुछना चाहता हूँ कि क्या गरीब आदमी दारू नहीं पीता। चौधरी बंसी लाल जी ने जो भाराब बंद की थी उससे स्टेट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ऐसी चीजों को हम कानून से नहीं हटा सकते बल्कि उनको भाराब न पीने के बारे में समझाया जा सकता

है। इसके लिए लोगों के सामने गोश्लथयां करे, सम्मेलन करे और लोगो को बताया जाए कि यह चीज अच्छी नहीं है, भाराब पीना बुरी लत है। जुआ खेलना भी बुरी लत है और लाटरी खेलना भी बुरी लत है। इनके बारे में आप लोगों को समझाए।डिप्टी स्पीकर साहब, लोगो में इस तरह की जो आदते है उनको समझा कर ही हटाया जा सकता है। इन्होंने खुद ही भाराब बंद की थी और फिर इन्होंने खुद ही उन ऑर्डर को वापिस लै लिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप भाराब बंद करके उसे दोबारा चला सकते है तो क्या लाटरी को ठीक ढग से नहीं चलाया जा सकता।(भाोर एवं विध्न)डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक लाटरी को चलाने का सवाल है,इसका मतलबहै कि आप अवैद लाटरी न रखें।अगर प्रदे ा में कही अवैद लाटरी यानि कही झटके,कहीं मटके,कही सट्टे जैसी चीजें चले तो क्या वह अच्छा है। इससे जब अपराध बढ़ेंगे तब क्या अच्छा रहेगा।

श्री बंसी लाल : ऑन ए प्वाइंट ऑफ ऑर्डर सर।(भाोर एवं विध्न) आप मेरी बात सुने।

श्री उपाध्यक्ष : चौ.बंसी लाल जी,आप तो बड़े वरिष्ठ सदस्य है। आप तो नियम के हिसाब से चलते है। आपको नियमो का पता होगा।

श्री बंसी लाल : मुझे नियमो का पता है। (भाोर एवं विध्न)

श्री उपाध्यक्ष : बंसी लाल जी, आपने बोलने से पहले मेरे से पूछा नहीं है। ऐसे हाउस नहीं चलेगा। मैं मानता हूँ कि आप तो कम से कम नियमों से बंद करके चलते हैं। आप मेरे से पूछ कर बोल सकते हैं। (भाोर एवं विधन) सम्पत सिंह जी आप अपनी बात कहिए। (भाोर एवं विधन)

प्रो. सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की इस बारे में अन्दर की कोई बात नहीं है। सरकार का बिल्कुल ओपन माईन्ड है। सरकार को अपना काम चलाने के लिए नॉन कनवैन्शनल रिसोर्सिज जुटाने पड़ेंगे। अकेले कनवैन्शनल रिसोर्सिज से आप कितने दिन जीवित रहेंगे। जब टैक्स लगाने की बात आती है तो फिर यह कहते हैं कि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए। फिर ये भाोर मचाते हैं कि फलां-फलां चीजों के दाम बढ़ा दिए गए। (भाोर एवं विधन) स्पीकर साहब, नॉन कनवैन्शनल रिसोर्सिज जुटाने पड़ेंगे और नॉन कनवैन्शनल रिसोर्सिज जुटाने के लिए ऑन लाइन लाटरी न केवल हरियाणा सरकार लें कर आई है बल्कि अब सिक्किम में भी किसी प्राइवेट पार्टी ने सरकार के साथ कोलैबोरेट करके उसको चलाया है। (भाोर एवं विधन) डिप्टी स्पीकर साहब, जो लाटरी सरकारों द्वारा चलायी जा रही हैं उन लाटरियों पर हम पाबन्दी नहीं लगा सकते। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हम ऑन लाइन लाटरी को बिना टैक्स चलने दें। ऑन लाइन लाटरी के बारे में एक दो स्टेट्स कोर्ट के अन्दर भी गई और वहां जा कर वे स्टै ले आयीं। कोर्ट ने कहा कि जब आप

अपनी लाटरी चला रहे हैं तो दूसरी लाटरी को हम बन्द नहीं कर सकते। डिप्टी स्पीकर साहब, इसी वजह से जब हरियाणा में ऑन लाइन लाटरी आयी तो आते ही हरियाणा सरकार ने मन बनाया कि इस पर 20 परसेंट टैक्स लगा दें। इसमें क्या बुराई है और कोई आदमी सट्टा खेलता है तो उसका कोई पैसा तो सरकार के पास नहीं आता। यदि कोई लाटरी वैध खेलेगा तो स्टेट को पैसा तो आयेगा। जहां तक ये जुआ घर की बात कर रहे हैं, कैसीनो की तरफ इतारा कर रहे थे, इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार बाकायदा कैसीनो भी भुर्खु करेगी। हमें अपने रवैन्यू को तो बढ़ाना ही पड़ेगा और नॉन कन्वैन्शनल रिसोर्सिज भी लेकर के आयेगें। गोवा के अन्दर भी यह हुआ है। दूसरी स्टेट्स के अन्दर भी यह हो रहा है। (भाओर एवं विधन) इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। जो लोग जुआ खेलते हैं। अवैध खेलते हैं। अवैध काम करने से कोई पैसा सरकार को नहीं आता। डिप्टी स्पीकर साहब, सरकार सोच विचार करके नीति बनायेगी, सरकार ट्रांसपेरेट तरीके से काम करेगी। यहां पर कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय घटी है। इस बारे में मैं यहां पर पहले ही बता चुका हूँ कि प्रति व्यक्ति आय घटी नहीं है बल्कि बाकायदा बढ़ी है। इसी प्रकार से यहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति का भी जिक्र किया गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति हरियाणा प्रदेश के अन्दर बाकी सभी प्रदेशों से बढ़िया है। पहले जहां इन्होंने नौजवानों को बिगाड़ने की कोशिश की थी वहां अब हम उन नौजवानों को रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों

को रास्ते पर लाने के लिए हमने स्पोर्ट्स नीति भी बनसशी है ताकि नौजवान अपराधों की तरफ न जायें बल्कि खेलों की तरफ आयें। डिप्टी स्पीकर साहब, इस बात के लिए हरियाणा प्रदे 1 को गर्व कना चाहिए। सारे अपोजी 1न को भी बधाई देनी चाहिए कि यूथ फेस्टिवल अगर पहली बार कहीं पर हुआ है तो वह कैपीटल हैड क्वार्टर पर न होकर हिसार में हुआ है। यह हरियाणा प्रदे 1 में डिस्ट्रिक्ट लैवल पर पहली बार हुआ है। उसमें सारे हिन्दुस्तान से आए हुए नौजवानों ने, लोगों ने, उसको सराहा है। इसका नतीजा यह भी निकला कि हमारी जो केन्द्रीय खेल और युवा मामलों की मंत्री उमा भारती है, उन्होंने वहां पर ही स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी खोलने के बारेमें अनाउंसमेंट की। हिन्दुस्तान में यह स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी पहली युनिवर्सिटी होगी। इसी तरह से सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में नार्थ जॉन का स्पोर्ट्स कम्पलैक्स भी सेंटर गवर्नमेंट ने मंजूर किया है। अब तक नॉर्थ जॉन में कोई स्पोर्ट्स सेंटर नहीं था। डिप्टी स्पीकर साहब, अम्बाला और गुडगांव में ऐस्ट्रोर्टफ लगाने जा रहे है, हिसार में भी स्पोर्ट्स की एनाउंसमेंट की है, ईनाम बढ़ाए गए हैं और रियायतें दी गई है, नर्सरियां खोली गई है और डिप्टी स्पीकर साहब, भायद आपका कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतता होगा जब किसी न किसी ने 1नल लैवल की चैम्पियनशिप में भाग न लेने जाना पड़े।(विधन)। 3 नौकरियों में रिजर्व 1न जवानोंके लिए स्पोर्ट्स पर्सनल के लिए रखी गई है। जितने भी बोर्डज तथा कॉरपोरे 1न्ज हैं वे भी अपनी टीमें बना रहे हैं ताकि उन बच्चों का खेल स्तर राष्ट्रीय स्तर तक ले

जाया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, नौजवानोंके प्रति सरकार कटिबद्ध है। इसी प्रकार से नये-नये कोर्सिज चालू किये जा रहे है जो कि व्यवसाय पैदा करते है। केवल मात्र सरकारी तौकरियां ही रोजगार नहीं देती आज आप कोई व्यवसाय करेगे तो आप रोजगार प्रििक्षण लेंगे, ट्रेनिंग लेंगे,आई.टी.आईज. तथा पोलिटैक्निक्स में जा कर आप स्वरोजगारी प्राप्त कर सकते हैं, यह काम भी सरकार ने चालू किया है। डिप्टी स्पीकर साहब,यहां पर एक एफ.डी. आई. का जिक्र किया था फॉरेन इन्वैस्टमेंट का भी चौधरी कर्ण सिंह दलाल जी ने जिक्र किया था इस बारे इन्होंने बड़े अच्छे सूझाव दिए हैं मैं इनकी ताईद करता हूँ। चौधरी भजन लाल जी के टाइम में 1991-96 की 5 साल की अवधि में 1457 करोड़ एफ.डी. आईज की थी, चौधरी बंसी लाल जी के टाइम में 1437 करोड़ की थी केवल मात्र आपकी सरकार में अढ़ाई साल में समय में असल में तो दो साल ही कहे क्योकि इसमे से 6 महीने तो चौधरी बंसी लाल जी वाला अड़ंगा ही था। इस दो साल में 1826 करोड़ रूपये की फॉरेन इन्वैस्टमेंट आई है (विधन) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कन्कल्यूड करने जा रहा हूँ और एक बात फिर यह कहना चाहूँगा कि एक बहुत बढ़िया बात कही थी बजट के 87 और 88 पैरा में,मांगे राम गुप्ता जी अगर ध्यान से पढ़ते तो इन बातों के लिए सरकार का धन्यवाद करते। सदन में जितने भी सदस्य बोले किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह कितना सीरियस मैटर था और कितनी चिन्ता का विशय था तथा सरकार ने भी इस पर चिन्ता जाहिर की है। डिप्टी

स्पीकर साहब, कन्या भ्रूण हत्या एक अन्य चिन्ताजनक विषय है (विधन) इसके बारे में अगर बजट पर बोलते हुए किसी ने कुछ बोला हो तो बताएं। (विधन) इसी प्रकार से राज्य प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो कि आज भी चलाया जा रहा है। ये दोनों चीजें एक रैवोल्यूशनरी स्टैप्स हैं और इन्होंने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, जो भी मांगें इनकी तरफ से आई हैं और सदस्यों ने भी अपनी मांगें रखी हैं, सरकार इन पर गौर करेगी। वैसे तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में स्वयं मुख्य मंत्री जी ने जितनी भी एनांसमेंट्स की हैं उनके बारे में मैंने बजट स्पीच में यह बताया था कि सारी एनांसमेंट्स पर काम हो चुका है या चल रहा है और हर हल्के के अन्दर सरकार ने काम रिया है। सरकार के लिए सारे हल्के बराबर हैं किसी एक हल्के का सवाल नहीं है। 90 के 90 हल्कों में मुख्य मंत्री जी जाते हैं चाहे वहां के विधायक उसमें आए या नहीं आए लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी की और से बाकायदा लोगों से यह कहा जाता है कि वे सरकार आपके द्वार में अपने हल्के की मांगें और समस्याएं रखें ताकि उनका निवारण हो। मुख्य मंत्री जी के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है कि यह हल्का सत्तापक्ष के विधायक का है या ओपोजीशन के विधायक का है मुख्य मंत्री जी के लिए और हरियाणा सरकार के लिए सारे के सारी हल्के बराबर हैं और हर हल्के के अन्दर पूरा काम किया जाता है। सदन में जा मांगें रखी गई हैं उन पर सरकार पूरा गौर करेगी, मैं डिप्टी स्पीकर साहब, के माध्यम से हाउस से यह निवेदन करूंगा कि इनता बढ़िया तो

बजट आया है और जो डिमाण्डज हैं उनको ध्वनि मत से पास करना चाहिए ओर पूरे उत्साह के साथ पास करपा चाहिए, पार्टी लाइन से पर उपर उठ कर चलना चाहिए। धन्यवाद सर।

**वर्ष 2002–2003 के बजट की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा
मतदान**

Mr. Deputy Speaker: Hon'bles members, Now discussion and voting on the Demands for Grants on Budget for the year 2002-2003 will take place. As per the past practice and to save the time of the House, all the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved. Hon'ble members can discuss any demands but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion.

That a sum not exceeding Rs.7,64,84,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No. 1-Vidhan Sabha.**

That a sum not exceeding Rs.2,50,14,17,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No. 2-General Administration.**

That a sum not exceeding Rs.5,54,12,97,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray

charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No. 3- Home.**

That a sum not exceeding Rs.1,60,07,07,000/- for revenue expenditure and Rs.5,00,00,000 for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No. 4-Revenue.**

That a sum not exceeding Rs.45,15,52,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No. 5- Excise & Taxation.**

That a sum not exceeding Rs.6,28,82,34,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No. 6-Finance.**

That a sum not exceeding Rs.5,42,40,57,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No. 7- Other Administration Services.**

That a sum not exceeding Rs.2,08,47,00,000/- for revenue and Rs.3,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No. 8- Buildings & Roads.**

That a sum not exceeding Rs.17,05,96,21,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No. 9- Education.**

That a sum not exceeding Rs.6,87,39,82,000/- for revenue expenditure and Rs.1,60,61,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No. 10-Medical & Public Health.**

That a sum not exceeding Rs.41,05,72,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No. 11- Urban Development.**

That a sum not exceeding Rs.56,87,25,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No.12 labour &Employment.**

That a sum not exceeding Rs.5,02,84,99,000/- for revenue expenditure and Rs.45,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No.13 Social Welfare & Rehabilitation.**

That a sum not exceeding Rs.24,09,35,000/- for revenue expenditure and Rs.14,61,47,93,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No.14 Food & Supplies.**

That a sum not exceeding Rs.14,09,93,00,000/- for revenue expenditure and Rs.3,25,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No.15-Irrigation.**

That a sum not exceeding Rs.35,72,58,000/- for revenue expenditure and Rs.1,68,10,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No.16- Industries.**

That a sum not exceeding Rs.2,95,51,00,000/- for revenue expenditure and Rs.1,40,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No.17-Agriculture.**

That a sum not exceeding Rs.1,35,65,79,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No.18 Animal Husbandry.**

That a sum not exceeding Rs.12,34,60,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year

2002-2003 in respect of charges under **Demand No.19 Fisheries.**

That a sum not exceeding Rs.75,10,75,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No.20 Forest.**

That a sum not exceeding Rs.1,26,64,53,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No.21 Community Development.**

That a sum not exceeding Rs.21,81,00,000/- for revenue expenditure and Rs.15,76,29,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No.22-Cooperation.**

That a sum not exceeding Rs.5,03,84,84,000/- for revenue expenditure and Rs.50,66,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No.23-Transport.**

That a sum not exceeding Rs.92,51,000/- for revenue expenditure and Rs.2,50,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No.24-Tourism.**

That a sum not exceeding Rs.2,21,12,71,000/- for revenue expenditure and Rs.3,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of Payment for the year 2002-2003 in respect of charges under **Demand No. .25 Loan & Advances by State Govt.**

Mr.Dputy Speaker: I have also received notices of cut motions on the various demands from some M.L.As. These will also be deemed to have been read and moved. However, I shall put the various cut motions to the House when the respective demands are put to the House. Such members may, however, participate in the discussion.

Demand No.3

- 1.Cap.AjaySingh;
- 2.Shri Jai Parkash and
- 3.Shri Karan Singh Dalal,M.L.As

That Demand No. 3 of Rs.5,54,12,97,000/- for revenue expenditure and Rs.27,00,00,000/- for capital expenditure on account of Home be reduced by Rs.1,00,000/-.

Demand No.5

1. Cap.AjaySingh;
2. Shri Shadi Lal Batra and
3. Smt.AnitaYadav,M.L.As

That demand No. 5 of Rs.45,15,52,000/- on account of Excise and Taxation be reduced by Rs.1/-.

Demand No.9

1. Cap.AjaySingh;
2. Shri Shadi Lal Batra and M.L.As

That demand No.9 of Rs. 17,05,96,21,000/- on account of Education be reduced by Rs.1000/-.

Demand No.10

1. Cap.AjaySingh;
2. Shri Shadi Lal Batra and
3. Shri Dan Singh, M.L.As

That demand No.10 of Rs. 6,87,39,82,000/- for revenue expenditure and Rs.1,60,61,00,000/- for capital expenditure on account of Medical and Health be reduced by Rs. 1/-.

Demand No.11

1. Smt. Anita Yadav,
2. Cap.AjaySingh; and
3. Shri Shadi Lal Batra and M.L.As

That demand No.11 of Rs.41,05,72,000/- on account of Urban Development be reduced by Rs.2/-.

Demand No.15

1. Cap.AjaySingh;
2. Shri Dharambir;
3. Shri Karan Singh Dalal, and
4. Shri Narender Singh, M.L.As

(i) That demand No. 15 of Rs.14,09,93,00,000/- for revenue expenditure and Rs. 3,25,00,00,000/- for capital expenditure on account of Irrigation and be reduced by Rs.2/-.

1. Shri Karan Singh Dalal, and
2. Shri Jagjit Singh, M.L.As

(ii) That demand No. 15 of Rs. 35,72,58,000/- for revenue expenditure and Rs. 3,25,00,00,000/- for capital expenditure on account of Irrigation be reduced by Rs. 1/-.

Demand No.16

1. Cap.AjaySingh;
2. Shri Dharambir, M.L.As

That demand No.16 of Rs. 35,72,58,000/- for revenue expenditure and Rs. 1,68,10,000/- for capital expenditure on account of industries be reduced by Rs.1/-.

Demand No.17

1. Cap.AjaySingh;
2. Shri Karan Singh Dalal, and
3. Shri Dharambir, M.L.As

That demand No. 17 of Rs.2,95,51,00,000/- for revenue expenditure and Rs.1,40,00,000/- for capital expenditure on account of Agriculture be reduced by Rs.1/-.

Now, discussion will take place. Shri Karan Singh Dalal may speak.

श्री कर्ण सिंह दलाल(पलबल) : अध्यक्ष महोदय, यह जो होम डिपार्टमेंट के बारे में डिमाण्ड है मैंने इसके बारे में कट-मोान दी हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि जो यह गृह विभाग है यह प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है प्रदेश के अन्दर कार्य ठीक ढंग से चले इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी गृह विभाग की है और जिस तरीके से आज गृह विभाग को यह सरकार चला रही है, वह बहुत ही निन्दनीय बात है। उपाध्यक्ष महोदय, अब में पुलिस की भर्ती के बारे में कहना चाहूँगा कि प्रदेश में पुलिस की भर्ती कह जरूरत न होते हुए भी पिछले दिनों पुलिस की भर्ती की गई थी। कायदे और कानूनो का उल्लंघन किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय मुझे पता चला है कि जो ए.एस.आई. की भर्ती हुआ करती थी अब यह सरकार उस ए.एस.आई.की भर्ती को खत्म करने जा रही है और सीधे तौर पर सब-इन्सपैक्टर्ज की भर्ती करना चाहती है। अगर इस सरकार ने सीधे ही सब-इन्सपैक्टर्ज की भर्ती करनी भुरु कर दी तो यह सरकार बहुत बड़ा गुनाह करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, नीचे से जो सिपाही, हवलदार ओर ए.एस.आई.की

परमो इन होती है वह परमो इन होनी बंद हो जायेगी। इसके अलावा सब—इन्सपैक्टर्ज उन बातों को नहीं सीख पाएगा जो ए.एस. आई. अपनी पोस्ट पर रहकर सीखता हैं। इसके अलावा पुलिस विभाग में हमने देखा कि पुलिस विभाग में मैडल बांटे गए।

वित्त मंत्री(प्रो.सम्पत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो मैडलज दिए गए हैं ये राष्ट्रपति जी ने दिए हैं और भारत सरकार के कहने पर दिए हैं। इस तरह से सदन में असत्य बातें करना कम से कम कर्ण सिंह दलाल जी आपको भाभा नहीं देता है। डिप्टी स्पीकर साहब, इन्होंने जो मैडलज वाली बात कही है वह कार्यवाही से निकलवा दी जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : जो रिकमेंडे इन होती है वह स्टेट गवर्नमेंट की होती है। मेरा कहना है कि जो अच्छे पुलिस अधिकारी है, जो योग्य अधिकारी हैं और जिनकी इन्टेग्रेटी जनता की भलाई का काम करने की है उन आफिसर्ज को इस सरकार ने खुड़े लाइन लगा रखा है। जो पुलिस अधिकारी सरकार के इ तारे पर राजनीतिक विरोधियों पर झूठे मुकदमे बनाना चाहते हैं और झूठे मुकदमे बनाने में लगे हुए हैं, उन पुलिस अधिकारियों को यह सरकार प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति प्रदरन कर सही है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में पुलिस उपायुक्तों की, पुलिसकी जो एस.पी. और एस.एच.ओ. साहेबान हैं जिनकी पोस्टिंग अच्छी जगहों पर हैं उनके बारे में अगर उनकी कान्फीडेंसियल रिपोर्ट्स मंगवा कर देखी जाए तो वह लाल पैन से भरी हुई होगी। मेरा आपके

माध्यम से सरकार को सुझाव है कि कम से कम हमारे गुड़गांव में, फरीदाबाद में, पानीपत और हरियाणा के दूसरे बड़े-बड़े भाहर हैं उनमें क्राईम को राकने के लिए अच्छे पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए और डी.सी.पी. का जो सिस्टम दिल्ली में या दूसरे महानगरों में मुम्बई और कोलकता में हैं वही सिस्टम हरियाणा में होना चाहिए। यही मेरा आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से अनुरोध है।

प्रो.सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी सैल्फ कंट्राडिक्ट्री स्टेटमेंट आ गई है। अभी ये दिल्ली के बारे में कह गए कि हरियाणा में दिल्ली का जो सिस्टम है उसको लागू किया जाए। दिल्ली के बारे में इनको पता होना चाहिए कि वहां पर सब-इन्सपैक्टर की भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होती है। ये सैल्फ कंट्राडिक्ट्री स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सब-इन्सपैक्टरज की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होनी चाहिए और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि दिल्ली के पैटर्न पर यहां पर डी.सी.पी. नियुक्त होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अब हम इनकी कौन सी बात मानें। (गोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष महोदय : कैप्टन अजय सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (गोर एवं व्यवधान)

श्री देवराज दीवान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सम्मानित साथी श्री कर्ण सिंह दलाल जी को बताना

चाहूँगा कि दिल्ली के लोग यह चाहते हैं कि वहां पर आई.जी. सिस्टम होना चाहिए। डी.सी.पी. का जो सिस्टम है उसको वे नहीं चाहते।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, दलाल साहब ने राष्ट्रपति द्वारा दिए गए मैडलज के प्रति जैसी भाशा का इस्तेमाल किया है मैं चाहूँगा कि उसे इस हाउस की कार्यवाही से निकलवा दिया जाए। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये मैडलज लगभग 6 वर्ष पहले दिए गए थे उस समय ये स्वयं मंत्री होते थे। ये उसी वक्त कि बात है इसलिए इस टिप्पणी को हाउस की कार्यवाही से निकलवा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा दिए गए मैडलज के बारे में दलाल साहब द्वारा जो टिप्पणी की गई है उन भावों के हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। अब कैप्टन साहब बालेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमान्ड न. 3 जो होम के बारे में है, बोलना चाहूँगा। सरकार ने अपने जवाब में दिया है कि टोटल जो एबस्कोर्डज थे वह पहली मई, 1998 को 60742 थे जिनकी संख्या अब बढ़कर 11263 हो गई है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि किडनैपिंग के 253 केसिज हैं जिनमें से केवल 139 केसिज में आरैस्ट हुई है। यह पोजिशन तो लॉ एंड ऑर्डर कि है। दक्षिण हरियाणा के टोटल

207 केसिज थे जिसमें से केवल 153 केसिज में आरैस्ट हुई है। इसी तरह से दूसरी बात में यह भी कहना चाहूंगा कि बजट में जिस हाई-वे पैट्रोलिंग को भुरु करने के बारे में कहा गया है वह एक अच्छी प्रथा है लेकिन ये हाई-वे पैट्रोलिंग वाले फट्टी का काम करने लग गए हैं। मैंने खुद देखा था कि गाड़ी के अन्दर पीछे काकड़े की बोरी रखी हुई थी और गाड़ी हाई-वे पर जा रही थी अब हाई-वे पर हरासमेंन्ट भुरु हो गई है। कहीं पर भी वे यात्रीयों को रोकते हैं और उनको टार्चर करते हैं। इसी तरह से ट्रकों को रोक कर भी ऐसा किया जाता है। जबकि इनका काम यह है कि अगर हाई-वे पर कोई ऐक्सीडैड हो जाए तो वे उसके देखने का काम करें। लेकिन वे इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं जो कि ठीक बात नहीं। इसी तरह से मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि जो प्राईवेट कम्पनीज है या कोर्पोरेटस है जिनको सरकार ने अपने गार्डस दे रखे हैं उनकी तरफ करीब तीन या साढ़े तीन करोड़ रूपए ऐसे हैं जो पैडिंग है इस बारे में सी.ए. जी. की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि 2.9 करोड़ रूपया इस तरह का है जो पर्सनल्ज और कामि रियल कम्पनीज है उनके पास जो गार्डस सरकार ने डिप्लाए कर रखे हैं, उनके एवज में सरकार ने आज तक उनसे पैसा वसूल नहीं किया है। जबकि यह पैसा उनसे एडवांस में लेना चाहिए था। मैं सरकार से ये जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों नहीं किया गया? इसी तरह से एक बात और कहना चाहूंगा कि 51 परसेंट भोयर रेलवे की तरफ हरियाणा सरकार का है वह भी आज तक नहीं लिया गया जबकि यह रेलवे

से ले लेना चाहिए था। इसी प्रकार से जेलों के अन्दर यह हालत हो गई है कि जिसके बारे में कहना मुश्किल है। इस बारे में कई केसिज है जिनमें मुंबाइल्ज फोन का जेलों के अन्दर इस्तेमाल हो रहा है खासकर गुड़गांव की जेल में आज भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, एक मिस्टर रिन्कू थे जिन्होंने एगजाम देना था लेकिन वहां के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने उससे पैसा मांगा और उसको एगजाम में नहीं बैठने दिया। जब जस्टिस वी.एम. जैन ने इस बारे में डायरेक्टिवान दी तब उसको उसने एगजाम में बैठने दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह किस्सा आपके गुड़गांव का है इसी तरह से पंचकूला के सी.आई.डी. इंस्पैक्टर भगवान सिंह के घर से ही मारुति को कोई उठाकर ले गया। इसी प्रकार से मुख्य मंत्री जी के खुद के रिलेटिव कैप्टन जसवन्त सिंह के साथ हांसी के भंडारी गांव में लोगों ने उनके घर में जाकर लूटमार की। इसका मतलब कोई सुरक्षित नहीं है। इसी तरह से कैथल में सतबीर सिंह एक जब्बल गैंग है वह बाकायदा एक्सटोरान कर रहा है। लोगों ने इस बात के लिए प्रोटेस्ट भी किया था। इसी प्रकार से जैसा मैंने पहले भी बताया कि भास्त्री कालोनी के अंदर मिसेज सुदे अबराल पत्नी डॉ.एम.सी. अबराल को मार दिया गया था और उसकी लाश एक बक्से में मिली थी।

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, अब आप बाईउड आप करें।

कैप्टन अजय सिंह यादव : जो, मैं वाईड अप कर रहा हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पानीपत के कोर्ट प्रिमिसेज में जोगिन्द्र कौर बाकायदा आपने वकील से सलाह लेने गयी थी लेकिन उसको वही पर ही गोली मार दी गयी। वह तो केवल अपने वकील से बातें करने गयी थी। इस केस में सुई एक ऐसे व्यक्ति पर जाती है जो यहां पर एक उच्च पद पर बैठा हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह की बातें ठीक नहीं हैं। कोर्ट में वह आने वकील से सलाह करती है लेकिन वहां भी उसकी जान सुरक्षित नहीं है। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि सी.बी.आई. से इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए कि किस हालात में जोगिन्द्र कौर को मारा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जस्टिस सिंघवी जी ने भी इस बारे में डायरेक्टिवान दी हैं। वहां के बार-चीफ को भी इस बारे में थ्रेट्स मिल रही हैं। इसी तरह से गांव रोजावास में पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति मारा गया है और इसी तरह से बल्लवगढ़ में भी दो लड़कियों के साथ ज्यादाती हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप कोई लयी बात कहें क्योंकि ये सारी बातें तो आप बजट पर बोलते हुए भी कह चुके हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मुख्य मंत्री जी के रि तैदार का फतेहाबाद में भारूम है यह पुलिस चौकी से 200 गज की दूरी पर है और कुछ लोगों ने उसमें घुस कर लूट मार की। इस तरह से

आज किसी की जान महफूज नहीं है। रोजाना लूट मार की वारदातें हो रही हैं।

परिवहन मंत्री (श्री अ गोक कुमार अरोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय सदस्य ने हाइ-वे पैट्रोलिंग के बारे में जिक्र किया। हरियाणा प्रदेश की सरकार बनते ही मुख्य मंत्री जी ने रोड़ सेफ्टी के लिए हाइ-वे पैट्रोलिंग का गठन किया उससे हरियाणा प्रदेश में एक साल के अंदर ऐक्सीडेंट्स में 20 प्रतिशत की कमी आई। इसको न केवल हरियाणा प्रदेश ने बल्कि भारत सरकारने भी सराहा है और उन्होंने दूसरी स्टेट्स को डायरेक्ट संज दी हैं कि हरियाणा के पैटर्न पर इसीप्रकार की हाइवे पैट्रोलिंग टीम बनाएं। जो माननीय सदस्य ने भांका जाहिर की कि पुलिस वाले लोगों को नाजायज लूटते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकारकी तहफसे स्पष्ट डायरेक्ट संज हैं और जिन व्हीकल्ज से ऐक्सीडेंट का खतरा है सिर्फ उन्हीं को रोका जाता है जैसे सरिया बंधा हुआ है या तूड़ी भरी हुई है इसके सिवाय किसी को नहीं रोका जाता है। माननीय सदस्य के ध्यान में यदि कोई ऐसा वाक्या है तो वे बता दें उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : जब श्री भादी लाल बत्रा बोलेंगे। (विधन) जय प्रकाश जी, आप बैठ जाएं। मैं आपकी ही पार्टी के सम्मानित सदस्य को बोलते का मौका दे रहा हूँ। बत्रा जी, आप बोलें। जय प्रकाश जी, आप खड़े होकर टाइम नहीं मांग सकते हैं। जिसको

मैंने टाइम देना है उसकी मैंने लिस्ट बना ली है। आम बैठ जाइए।
(गोर एवं व्यवधान)

चौ. जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नंबर 3 पर बोलने के लिए समय मांग रहा हूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप हमारे गार्जियन हैं आपसे ही हम बालने के लिए समय देने की उम्मीद कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो नाम मेरे पास आए हैं मैं उनको ही समय दे रहा हूँ। आप मुझे डिक्टेट न करें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डिमांड नंबर 3 पर बोलने के लिए इजाजत नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सबको बानलने कि लिए समय दूंगा। जिका नाम कट मो इन में है उन सबको मैं बोलने का मौका दे रहा हूँ।

राव इन्द्रजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो भांका है वह यह है कि डिमांड 3 पर चर्चा हो रही है और डिमांड नंबर 5 वाले सदस्य को आप बुला रहे हैं। डिमांड नं. 3 पर बोलने वाले को मौका नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कहते हैं कि सभी तीन नंबर डिमांड पर ही बोले हैं। तीन नंबर डिमांड के अलावा भी डिस्क इन हुई है और मैंने किसी को नहीं रोका। तीन नंबर

डिमांड के अलावा भी दूसरी डिमांडज को टच किया हैं। आप बैठिए प्लीज। एक चीज आप सुन लें। कट मो इन जितनी है उनको सबको इकट्ठा मुव किया है। जो सदस्य जिस पर बोलना चाहें वे बोल सकते है। अब श्री भादी लाल बत्रा बोलेंगे।

श्री भादी लाल बत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पास हुआ है और उसमें कुछ चीजें ऐसी आई। मटके पर जब नंबर लगाते थे तो उसे गैर कानूनी माना जाता था और उन्हें पकड़ा जाता था आज इसमें 20 परसेंट टैक्स लगाकर उस नंबर देने को मान्यता दे दी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज हम क्या करने जा रहे है। हम विकास की तरफ जा रहे हैं या विना टा की तरफ जा रहे ळ। इस लाटरी से किसी वर्ग वि ोश पर नहीं बल्कि भाहर में भी, गांव में भी सभी वर्ग, बल्कि गरीब वर्ग इससे ज्यादा प्रभावित होगा। एक रिक् टा मुलर सारे दिन की कमाई से भाम को लाटरी का नम्बर लगायेगा और सारे दिन की कमाई उसमें लगा देगा लाटरी का नम्बर तो किसी एक आदमी का लगेगा बाकी तो बर्बाद हो जायेंगे। यह जो जुआखाना सरकार खोलने जा रही है मैं तो यह कहूंगा कि यह ठीक नहीं हैं। जैसा कि माननीय वित्त मुत्री महोदय ने कहा कि नॉन कंवै इनल सोर्सिज हाने चाहियें। वहां से रेवैन्यू आना चाहिये, वहां से कर आना चाहियें तभी विकास होगा वहां तक तो ठीक है क्योंकि नाम्न कंवै इनल हमारी संस्कृति के खिलाफ है यह विकास की भावना है उसके खिलाफ है उससे हमें कुछ फायदा

नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। इसके अलावा बजट में यह भी दर्शाया गया है कि नयी चीज आ रही है उससे इतना अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कितना रेवेन्यू आयेगा। इस लयी चीज की जो भुरुआत हो रही है वह ठीक नहीं है। अगर यह ठीक प्रकार से नहीं करेंगे तो इससे नुकसान होगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि नहीं करो लेकिन अगर 20 प्रतिशत टैक्स ही लगाना है तो सरकार अपनी लाटरी भुरु करे तो कैसा रहेगा उससे अच्छा रेवेन्यू आयेगा। सिविकम की लाटरी से वहां की सरकार ही कमायेगी। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि वह सारी इन्कम हरियाणा सरकार को आनी चाहिए। हरियाणा सरकार सिविकम की लाटरी को मान्यता देने की बजाये अपनी लाटरी को मान्यता दे। इसके इलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य के बारे में हकला चाहूंगा। बजट में जो स्वास्थ्य के बारे में दर्शाया गया है, मैं राहतक मैडिकल कॉलेज के कैंसर इंस्टिट्यूट के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वहां पर माफर्निन की गोलियां नहीं मिलती हैं क्यों नहीं मिलती क्योंकि उसके लिए नारकोटिक्स बोर्ड से लाइसेंस लेना होता है वह लाइसेंस नहीं लिया गया है, वहां पर मरीज कराहते रहते हैं। दो साल पहले डब्ल्यू.एच.ओ. से अस हजार गोलियां ली गई थी उनकी पेमेंट भी कर दी गई है लेकिन लाइसेंस न होने के कारण वे गोलियां अभी तक नहीं आ रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बजट में बहुत कुछ दर्शाया गया है लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वे पूरी नहीं होती। वहां पर आप्रेशन के लिए ब्लेड नहीं होते हैं, आप्रेशन के लिए भार्मसार बात है। फिर किस

प्रकार की स्वास्थ्य की रक्षा यह सरकार कर रही है, किस प्रकार की सुविधा ये दे रहे हैं इसलिए स्वास्थ्य के लिए जो बजट द ार्या गया है उसको और बढ़ाया जाये। तीसरी बात.....(विधन)

श्री उपाध्यक्ष : बतरा जी वाईड अप कीजिये।

श्री भादी लाल बत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, जो ि ाक्षा नीति मे यह सैल्फ फायनैसिंग स्कीम है इसकी बजाये गुणों के आधार पर एडमि ान करने का प्रोविजन किया जायें। धन्यवाद।

चौ.जय प्रका ा(बरवाला) : उपाध्यक्ष महोदय, अपना धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। उपाध्यक्ष महोदय, गृह विीग सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। लेकिन मैं बड़े खेद के साथ सदन को सूचित करना चाहूँगा कि इस विभाग के पुलिस प्र ासन को आज सरकार के कुछ लोगों द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए और बदला लेने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। जैसा हक हर थाने मे पुलिस की जिप्सियां और गाड़ियां है उनको एक ही परिवार के लोगों की सिक्कियों रिटी, एस्कार्ट, पायलट के लिए प्रयोग किया जा रहा है जिस पर करोड़ों रूपये का खर्चा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का एक सदस्य जो आज एम.एल.ए. है और कल वह एम.एल.ए नहीं रहेगा तो क्या उसको फिर भी एस्कार्ट मिलेगी। ये एस्कोर्टस अपराध को राकने के लिए है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एक बार कलायत में एक बदमा ा दुकान को लूटकर ले गया,

थाने में गाड़ी नहीं थी और पुलिस वाला मोटर साइकिल पर गया। इसलिए जो एस्कोर्टस दिए जाएं, इस बारे में सरकार सदन को बताएं कि जिप्सीयां कौन से थाने को दी गई हैं और कौन से इलाके को दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में री रेलू राम पूनिया जो किस इस सदन के सदस्य रहे हैं उनके पहरवार के 8 लोगों को मारा गया, अगर सरकार चुस्त और दुरुस्त होती तो वहां कोई एक्लान लेती, जो वहां पर कांड हुआ उसका मुख्य कारण यह है कि प्रशासन ने ठीक तरह से अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। पुलिस के लोग मौके पर मौजूद नहीं थे उसके बाद जब मैंने यह बात उठाई तो उलटा मेरे खिलाफ चार्ज दर्ज करने का काम किया गया। उससे बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने थ्या दे सकता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम गृह मंत्रालय जिसका काम प्रदेश के लोगों की जान की और उनके माल की सुरक्षा करना होता है उसका प्रयोग अपने निजी हितों के लिए न किया जाए बल्कि उनका प्रयोग उनके खिलाफ किया जाए जो जनता के साथ अपराध करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, झज्जर अदालत में सरेआम गोलियां चली लेकिन आज तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस समय पर नहीं पहुंचती उसका एक कारण यह है कि थाने में रख रखाव ठीक तरह से नहीं किया जा रहा। नई जिप्सीयां पुलिस के उच्च अधिकारियों को दी जाती है। कई बार थानेका इन्चार्ज दूर होता है और कोई क्राइम होता है तो उस तक मैसेज नहीं जा पाता। इसलिए हर थाना इन्चार्ज के एक-एक

मोबाइल फोन देना चाहिए। ताकि जो थानों के और बीट के इन्चार्ज हैं अगर कोई क्राइम हो जाए तो उनको जल्दी से जल्दी बताया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि रेलू राम पुलिया हत्याकांड की सी.बी.आई. से जांच कराई जाए।

श्रीमती अनीता यादव(साल्हावास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पे किया था उसमें में आबकारी और कराधान विभाग के बारेमें कुछ जिक्र करना चाहती हूँ। सिरसा जिले में जो भाराब के ठेके खोले गये हैं और जो ठेके दिए गए हैं, जितनी सब ब्रांचिज खोली गई हैं इनका रेवैन्यू मुझे ठीक नहीं लगता। कैथल का ठेका दे दिया गया एण्ड कम्पनी की तरफ 50 लाख का ब्याज बकाया था उसके बावजूद भी उसको वर्ष 2001-2002 का ठेका दे दिया गया और आज जो साढ़े 3 करोड़ रुपये बजट में दिखाया गया है। मुझे यह रेवैन्यू ठीक नहीं लगता। इसी प्रकार भाहरों की बात मैं करना चाहूँगी। भाहरों के विकास के लिए 41 करोड़ 5 लाख 72 हजार रुपये की राशि जो दिखाई गई है मुझे लगता है कि इसमें कोई त्रुटि रह गई है। जिस भी भाहर से हम निकलते हैं वहां सड़कों की हालत बहुत खराब है। वाटर सप्लाई और सीवरेज का परली दोनों मिक्स होकर आता है इससे डायरिया होने की भी शिकायत मिली है। मेरा आपसे अनुरोध है कि रेवैन्यू डिपार्टमेंट के बारे में मुझे भाक है इसलिए इसकी जांच कराई जाए।

राव दान सिंह(महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट की डिमांडस पर बोलने के लिए अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जन स्वास्थ्य विभाग के ऊपर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा। प्रदेश के नागरिक प्रदेश की धरोहर होते हैं अगर उनका स्वास्थ्य ठीक हो तो यह प्रदेश के लिए दवाइयों का प्रावधान किया गया है वह इन-सफी एंट है। पहली बात तो यह है कि दवाइयां उन अस्पतालों में मिलती नहीं और अगर मिलती भी हैं तो नाम मात्र। दूसरी बात जिसकी तरफ में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि महेन्द्रगढ़ क्षेत्र के साथ पिछड़ा नाम जुड़ा हुआ है। पहले भी मैंने बताया था कि जिस जिनले का नाम महेन्द्रगढ़ है और उसका हैडक्वार्टर नारनौल में है। महेन्द्रगढ़के सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, एक महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो महिला का उस समय दूसरा जनम होता है। ऐसे समय में यदि किसी अस्पताल में महिला चिकित्सक न हो तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं को कितनी दिक्कत होती होगी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि महेन्द्रगढ़ जिले में नारनौल को छोड़कर पांचों ब्लॉकों में कहीं भी महिला चिकित्सक नहीं है, सब-डिवीजन में भी महिला चिकित्सक नहीं है वहां महिला चिकित्सक का प्रबन्ध सरकार करवाये।(विधन) उपाध्यक्ष महोदय, महेन्द्रगढ़ के अंदर अस्पतालों की हालत इतनी खराब हैकि वहां के अस्पताल अब एम.एल.आर. सेंटर बनकर रह गये है। इसलिए वहां के अस्पतालों की तरफ सरकार

ध्यान दे और जहाँ महिला डाक्टरों की जरूरत है वहाँ महिला डाक्टरों का प्रबन्ध करवाया जाये ताकि जनता का जो वि वास सरकारी अस्पतालों से उठ गया है वह दोबारा से बन जाये। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं। एक दो बरते जनस्वास्थ्य विभाग के बारे में और कहना चाहूँगा कि जन स्वास्थ्य की हालत आज यह है कि बहुत सी जगहों पर वाटर सप्लाई के पाइप्स टूटे हुए हैं। जब उनमें परली की सप्लाई की जाती है जतब वाटर सप्लाई बंद की जाती है तो गंदा पानी भी वाटर सप्लाई होता है। इससे बीमारी फेलने की आ ंका होती है। इस प्रकार के सैम्पलज कई बार भरकर हमने उनमण्डल अधिकारी को दिए हैं। इसलिए जहां भी पाइप्स टूटे हुए हैं। उन्हें बदला जाये और वाटर प्लाई टेंकों में दवाई डाली जाये ताकि जनता का स्वास्थ्य ठीक रह सके। इसके अतिरिक्त मैं मेरे ल्के से संबंधित एक और समस्या की तरफ जन स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि मेरे हल्के के गांव जाट की जो वाटर सप्लाई है उसके पानी को वाटर टैस्टिंग लैबोरेट्री ने चैक किया था और कहा था कि इसका पानी पीने लायक नहीं है क्योंकि पानी में फ्लोराईड की मात्रा अधिक है जो दातों और हड्डियों के लिए हानिकारक है। लेकिन उसकी सप्लाई को आज तक भी नहीं रोका गया है। इस तरह के पानी की सप्लाई को बंद किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मवीर सिंह (तो नाम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डिमांड नम्बर 16 व 17 पर अपनी बात रखना चाहता हूँ।(विधन)

श्री उपाध्यक्ष : जय प्रकाश जी आप बैठे-बैठे न बोलें। आपको बोलने का मौका मिल चुका है।

श्री धर्मवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिए बजट में जितने पैसे का प्रावधान किया गया है वह कम है।

प्रो.सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कट मोटाई दी है क्या उस पैसे को और कम करवाना चाहते हैं।

श्री धर्मवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हम कम नहीं करवाना चाहते। मैं सम्पत सिंह जी को बताना चाहूँगा कि सिंचाई के लिए बजट में बहुत कम पैसा रखा गया है तथा मेरे क्षेत्र के साथ भेदभाव भी बरता गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे दक्षिणी हरियाणा में पीने के पानी की बहुतकमी है इस कमी को पूरा किया जाये। हरियाणा प्रदेश को लीन सीजन में 13 हजार क्यूबिक पानी भाखड़ा और यमुना सिस्टम से मिलता है तथा इससे टोटल 95 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। 32 लाख एकड़ भूमि को ये 8 हजार क्यूबिक पानी देते हैं और 63 लाख एकड़ भूमि को ये 5 हजार क्यूबिक पानी देते हैं। जब हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो जवाब मिलता है कि दक्षिण हरियाणा में लिफ्ट कनाल सिस्टम से सिंचाई होती है और ये खराब है। इसलिए मेरी वित्तमंत्री जी

सम्पत सिंह जी से प्रार्थना है कि वहां जे.एल.एन. कैनल,सिवाणी,दादरी,जूई आदि फीडरों की मोटरें 6 महीने के अंदर बदली जायें या रिपेयर की जायें तथा इनके लिए बजट में पैसे का प्रावधान भी किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कृषि से संबंधित मांग पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। वहां पर 100 सिंप्रकलर सैट्स नहरो पर लगे हुए थे सरकार को चाहिए कि डीप सिस्टम के माध्यम से या ट्यूबवैलज के माध्यम से इन सिंप्रकलर सैट्स का यूज करे। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि तारीबन 100 सिंप्रकलर सैट्स आज भी गोदाम में पड़े हुए है, उनके ठीक करके दोबारा चलाया जाएं। यदि इनको ठीक करके दोबारा नहीं चलाया जाएगा तो इससे करोड़ों रूपए का जो माल है, वह खराब हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली से संबंधित डिमांड पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। इस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे यहां पर किसानों से बिजली का बिल लेने के लिए बिजली बोर्ड द्वारा चौथा स्लैब सिस्टम लागू किया जाये। भिवानी, महेन्द्रगढ़ और रिवाड़ी जिलों का इलाका ऐसा है जहां पर 200 फुट से ज्यादा गहरा पानी पहुंच चुका है। इन एरियाज में 20 हॉर्ज पावर की मोटर से भी पानी नहीं उठाया जा सकता। यदि पानी उठाया भी जाता है तो केवल 2 इंच ही पानी निकलता है। मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने लोगों को यह आश्वासन दिया था और चुनाव से पहले इन्होंने घोशणा

की थी कि यदि मेरी सरकार आयेगी तो वहां पर चौथा स्लैब सिस्टम लागू किया जायेगा। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि हमारे एरिया में यानी दक्षिणी हरियाणा में चौथा स्लैब सिस्टम लागू किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं। हैल्थ से संबंधित जो मांग है उस पर अपनी बात कहला चाहता हूँ। बड़े दुःख की बात है कि इस मद में 2 करोड़ 10 लाख की आबादी के लिए बजट के अन्दर केवल 16 करोड़ रुपये अवाइयों के लिए रखे गए हैं। बजट के हिसाब से देखें तो साल में एक आदमी पर केवल 7 रुपये खर्च आयेगा। आज 7 रुपये में तो कोई रिक्शा वाला बस स्टैंड से हॉस्पिटल तक भी लेकर नहीं जा सकता। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इस मद में भी पैसे को बढ़ाया जाये ताकि आम आदमी को कुछ राहत मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना सीगन लेता हूँ।

राव नरेन्द्र सिंह (अटेली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे डिमांडज पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे पहले डिमांड नं.15 जो सिंचाई से संबंधित है उसके विषय में कुछ बरतें कहना चाहूँगा। इस बजट के अन्दर और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर उन इलाकों के बारे में जो हरियाणा के अन्तिम छोर पर लगते हैं जैसे नांगल चौधरी का इलाका है, गोद बलावा का इलाका है, रातामोलड़ा का इलाका है, अटेली के गनियार बजाड इलाके है

उनके लिए कोई नीति नहीं बनायी गयी है। सरकार को चाहिए कि टेल एण्ड के इलाको की तरफ विशेष नीति बनायी जाये क्योंकि आज तक वहां पर नहर का पानी नहीं पहुँच पाया है। इसका मुख्य कारण मैं समझता हूँ कि या तो नहरों की गाद की सफाई नहीं करते या ऐसी व्यवस्था है कि जितना हमें पानी मिलना चाहिए वह पानी नहीं मिल पाता जिस कारण पानी का प्रैार पूरा नहीं हो पाता और पानी बीच में ही रह जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि आजकल बहुत से गांवों के अन्दर कैनल बेस्ड वाटर स्कीम है। लोगों को पीने का पानी पूरा मिले इसलिए नहरों में पानी जाना बहुत जरूरी है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि आप अन्तिम छोर वाले इलाको के लिए पानी की अधिक से अधिक व्यवस्था करें ताकि उन इलाकों के लोगों को पीने का पानी और खेती के लिए पानी मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं काडा विभाग के बारे में जिकर करना चाहता हूँ। हमारे जिले में इससमय काडा का कोई दफतर नहीं है। पहले जो दफतर कांग्रेस के समय में वहां पर था 1997 से रिफट कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में लाना चाहूँगा कि वहां पर अब भी काडा का काफी काम बचा हुआ है। मैं समझता हूँ कि जब एस.वाई.एल. का पानी आयेगा और यदि उस समय काडा की तरफ से खालें नहीं होंगी तो वह पानी हमें कैसे मिल पायेगा। जब नहरों में पानी ही नहीं आ पायेगा तो फिर किसान आने खेतों में कैसे प्रोपर पानी दे सकेगा। अतः मेरा

आपके ताध्यम से अनुरोध है कि वहां पर काडा का आफिस अव य खुलवाया जाये ताकि वहां पर पानी की उचित व्यवस्था हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई से संबंधित मांग पर अपली बात कहना चाहूंगा । हमारे वहां पर पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है । हमारे यहां पर पानी का स्तर 700 फुट से 1000 फुट तक चला गया है । जैसा कि आप जानते हैं कि नांगल चौधरी, नारनौंद ब्लाक के अन्दर सरकार की तरफ से कुएं खोदने पर भी बैन है जिसके कारण आज वहां पर स्थित यह बनी हुई है कि खेती के लिए तो कया पीने के पानी के लिए भी लोग तरस रहे है इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि उन इलाकों में जहां वाटर लैवल नीचे चला गया है उसको री-चार्ज करने के लिए सरकार कोई सुविधा उपलब्ध कराए । सरकार चाहे नहर के माध्यम से वहां पर कोई पानी की व्यवस्था करें, या फ्लड के टाइम में या दूसरे समय के अन्दर उन नदियों पानी रोकने की व्यवस्था करें ताकि वहां का जल स्तर ऊपर आ सकें । इसी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए । अंत में उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना सीगिन लेता हूँ ।

कैप्टन अजय सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई से संबंधित मांग पर कुछ कहना चाहूंगा । (गोर एवं विधन)

श्री उपाध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठिए। आप पहले ही बोल चुके हैं।(गोर एवं विधन)

चौधरी भजन लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब ने सभी डिमांडज पर कट मो तान दे रखे हैं। वे पहले समझ नहीं पाए थे कि सभी कट मो तान पर एक साथ बोलना है या अलग-अलग उनको बोलने का समय मिलेगा इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इनको दो मिनट का समय बोलने के लिए दें तो ये अपनी बात कह लेंगे।(गोर एवं विधन)

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, मेरे पास जो-जो नाम आए हैं, मैंने उन सभी को बोलने का मौका दिया है।(गोर एवं विधन)

चौधरी भजन लाल : ठीक है, आपने मौका दिया है, अच्छी बात है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कैप्टन साहब को दो मिनट और बोलने का समय दे, इससे क्या फर्क पड़ेगा। (गोर एवं विधन)

श्री उपाध्यक्ष : हमें टाइम का भी तो ध्यान रखना है। यह भी देखना है कि कौन मैम्बर नहीं बोला है। अब इनको समय दिया तो फिर सारे कौ सारे बोलेंगे। ऐसे बात नहीं बनती। (गोर एवं विधन) मैंने सबको बोलने का मौका देने की कोशिश की है। यदि अब एक सदस्य को बोलने का मौका न दिया जाए और दूसरे को बोलने का मौका न दिया जाए तो यह अच्छी बात नहीं लगती।

(गोर एवं विधन) समय सबके लिए एक सार है। (गोर एवं विधन)आप सभी बैठिए। अब प्रो.सम्पत सिंह जी जवाब देंगे। (गोर एवं विधन)

प्रो.सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, पहले भी यह ट्रेडी इन रही है कि चाहे कट मो इन हो चाहे डिमांडस हो सबको इकट्टी ही लिया करते है और आपने इस बारे में ठीक ही कहा है। बहुत से मैम्बर ने डिमांड के माध्यम से और कट मो इन के माध्यम से कुछ बातें सदन में कहीं। हालांकि काफी बातें सैल्फ कण्ट्राडिक्टरी बातें थी जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया श्री मान कर्ण सिंह दलाल ने भी पुलिस के बारे में जिक्र किया कि पुलिस के फला पद को समाप्त करके फला को देना है। जैसे सब-इन्सपैक्टर का जिक्र किया था और उसके बाद देहली पैट्रन का जिक्र किया था कि यह देहली पैट्रन पर हो। उपाध्यक्ष महोदय, देहली के बारे में आपको बेहतर ज्ञान है क्योंकि आप देहली के नजदीक गुड़गांव में रहते हैं। देहली में सब-इन्सपैक्टर की रिक्रूटमेंट, ए.एस.आई. और इन्सपैक्टर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है और इसके लिए इन्होंने यह कहा कि यह पैट्रन लागू किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आता कि वे क्या कहना चाहते थे ? जहां तक हरियाणा प्रदेश का सवाल है, पुलिस प्रशासन को या पुलिस की नियुक्तियों का जहां तक सवाल है (विधन) हरियाणा प्रदेश के हर वार्डिन्डे ने रिक्रूटमेंट को सराहा है, ईवन आपोजि इन के मैम्बर्ज ने भी इसे सराहा है। उपाध्यक्ष

महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमें यह ऐलान किया है कि कोई भी आदमी चाहे तो इस बारे में विभागत करें। मुख्य मंत्री जी जहां कहीं भी जाते हैं, जनसभाओं में भी पूछते हैं और मीटिंगों में भी यह पूछते हैं कि किसी भी रिक्रूटमेंट के अन्दर अगर किसी ने पैसा लिया हो (विधन) किसी भी जगह अगर एक भी पैसे का लेन-देन हुआ हो तो कोई भी व्यक्ति इस बारे में दरखास्त दे सकता है। (विधन)

श्री कर्ण सिंह दलाल : डिप्टी स्पीकार साहब,

श्री उपाध्यक्ष : देखिये कर्ण सिंह जी, इस हाउस के 90 सम्मानित सदस्य हैं और सभी सदस्य बराबर हैं। (विधन) आपको विभागत रहेगी, जब मैं आपको बोलने से रोकूंगा तो आपको विभागत रहेगी। यहां पर अकेले आदमी का जिक्र नहीं है और यह भी जरूरी नहीं है कि आप हर बात पर बोलें। (विधन) आपने जो कुछ भी कहा, आपका कोई भी भाव कार्यवाही से नहीं निकलवाया, बार-बार बीच में टोकना अच्छा नहीं लगता इसलिए आप प्लीज बैठें। (विधन) आप जस्टिफाई नहीं करेंगे जब भी कोई मौका आएगा तो आपको बोलने का मौका देंगे। (विधन) देखिये हाउस का टाइम पहले ही खत्म होने जा रहा है दलाल साहब जो बोल रहे हैं वह रिकॉर्डन किया जाए। (विधन)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

**वर्ष 2002–2003 के बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा
मतदान(पुनरारम्भ)**

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था और अब फिर दोहरा रहा हूँ कि जिस किसी सदस्य की तरफ से उल्लेख किया जाता है तो रिप्लाय में उसकी चर्चा जरूर आएगी (विधन) ये बार-बार बीच में खड़े होकर सदन का समय खराब करते हैं तथा कुर्सी की गरीमा को बिगाड़ते हैं। अध्यक्ष की कुर्सी की तरफ पीठ करके सौ काल्ड स्पीकर बनाकर हाउस का समय बर्बाद करते हैं। यह कतई ठीक नहीं है। यहां पर कायदे कानून का तो ध्यान रखा जाए। ये अपनी बात तरीके से हाउस के सामने रखें। (विधन) उपाध्यक्ष महोदय, ये अपने आप को पढ़ा-लिखा कहते हैं अगर ये अनपढ़ होते तो इनका क्या हाल होना था।

श्री कर्ण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : कर्ण सिंह जी, अब आप नहीं बोलेगें। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पूरे हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। चेयर की प्रमिान के बिना आप कुछ नहीं बोले और चेयर की प्रमिान के बिना जो बोला जाता है उसको रिकॉर्ड न करे। (विधन)

वित्त मंत्री (प्रो.सम्पत सिंह) : डिप्टी स्पीकर सर, जहां तक हमारे पुलिस प्रशासन संबन्ध है, इस पर इन्होंने टिप्पणी की है। सर बकायदा, अपराध को नियंत्रित रखने में, अपराध रोकने में और अपराधों को हल करने में हमारा पुलिस प्रशासन एकदम सक्षम है। योग्य अधिकारियों को उनकी योग्यता के अनुसार उचित प्लैसिज पर रखा गया है। यह जो टिप्पणी की गई है वह बिल्कुल असत्य है। राष्ट्रपति वाली बात तो मुख्य मंत्री जी ने कह ही दी है। उन्होंने जो प्रशासनीय कार्य किया था, कई जगहों पर उन्होंने उग्रवादियों को पकड़ा, उनका सामना करते हुए उन्होंने गोलियां भी खाईं। डिप्टी स्पीकर सर, इनमें ऐसे ऑफिसर भी हैं जिन्होंने उग्रवादियों से लड़ते हुए गोलियां भी खाईं और एक-एक महीना अस्पतालों में भी रहे हैं चौधरी भजन लाल जी खुद भी अस्पताल में उनसे मिल कर आए थे, क्या फिर भी दूसरे सदस्य उनकी बातों को उठाते रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मरणोपरान्त भी अवॉर्ड दिए गए हैं।

प्रो.सम्पत सिंह : अब उनमें से कइयों को मरनोउपरान्त मैडलज दिए गए है। अब इनको इस बात पर भी ऐतराज हो रहा है और उनका नाम लेने में भार्म आ रही है उनको तो इस बात के लिए सरकार की सरहाना करनी चाहिए कि जिनको 6 साल तक सम्मानित नहीं किया गया था उनको अब इस सरकार के प्रयासो से राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित किया गया है। जो मैडल स्टेट गवर्नमेंट देती है वे मैडल उनके 6 साल तक गवर्नर हाउस में पड़े रहे उनको वे मैडल मिले है इनको तो इस बात के लिए सरकार की सराहना करनी चाहिए कि इस सरकार ने उनको ऑर्न किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस कारण से दूसरे जो प्र गसिनक कर्मचारी और अधिकारी है उनका भी होसला बढ़ता है और उनको उत्साह मिलता है । उपाध्यक्ष महोदय, अब इन्होंने यहां पर अपराधों का जिक्र कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय,जहां तक अपराधों की बात है। हम यह नहीं कह रहे है कि हमारी सरकार ने अपराधों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जब हमने यह सरकार सम्भाली थी, उस समय जो परिस्थितियां थी और जिन परिस्थितियों में यह सरकार सम्भाली थी उस वक्त पिछली सरकार ने प्रदे 1 के क्या हालात बना दिए थे। उस वक्त 17,18 और 20 साल के एक लाख से ऊपर बच्चों पर क्रीमिनल केस दर्ज थे। जिस प्रदे 1 में इतने बच्चों पर क्रीमिनल केस दर्ज हो तो उस प्रदे 1 के भविश्य का आप अन्दाजा लगा सकते हैकि उस प्रदे 1 का भविश्य क्या होगा ? उन बच्चों पर कैसे काबू पाया जाएगा यह बहुत ही मु किल काम था लेकिन

फिर भी इस सरकार ने उन पर काबू पाया है। हम ने उनको प्रोत्साहित करके उन पर छोटे-मोटे दो-चार मुकदमे थे, उनको विदग्ध कर लिया ताकि वे सही रास्ते पर आ जाएं। हमने यह सोचा कि उनसे गलतियां हो गईं और अगर उनको इन्सैंटिव दिए जाए तो वे रास्ते पर आ सकते हैं। कुछ के खिलाफ कार्यवाही करके इन्सैंटिव या डिस-इन्सैंटिव देकर दोनों तरीकों से रास्ते पर लाने की कोशिश की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, आज यहीं कारण है कि अपराधों में कमी आई है। मैं आपके माध्यम से सदन में इस वर्ष के बारे में बता देता हूँ। इस वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले में आई.पी.सी. के तहत 330 मुकदमे कम हुए हैं, हत्या के तीन मुकदमों में, मार-पीट के 170 मुकदमों में, बलात्कार के 33 मामलों, डकैतों के 32 मामलों में, लूट-मार के 58 मुकदमों में, संधमारी के 359 मुकदमों में और चोरी के 357 मुकदमों में कमी आई है। इसी तरह से डिप्टी स्पीकर सर, जहां तक मुकदमों को हल करने की बात है, खास करके इन्होंने जो अपहरण का जिक्र किया है तो मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि 1997 में 65.1 प्रति सफलता मिली थी और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 86.5 प्रति सफलता प्राप्त की है। अपराधी तो अपराध करके चला जाता है लेकिन उसको कैसे रोका जाए और आईन्दा के लिए उसके निरूत्साहित किया जाए ताकि दूसरे लोग उस रास्ते पर न आए। इसलिए अगर जो केस बनता है और उसको हल कर लिया जाए और उसको हल करने में आपको सफलता मिल जाती है तो अपराधों की संख्या कम होगी। अगर

उस केस को हल करने में आपको सफलता नहीं मिलती है तो अपराध बढ़ेंगे। हम उन अपराधों को जो कि हो रहे हैं उनको जस्टिफाई नहीं करते हैं लेकिन सरकार की तरफ से उन अपराधों को रोकने का पूरा प्रयास है और दूसरी तरफ जहां तक उपाध्यक्ष महोदय, प्रोत्साहित करने की बात है तो इन्होंने यहां पर सिपाही का और दूसरे महकमों के लोगों का जिक्र किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और जन-जाति के जो लोग हैं इनके खिलाफ जो अपराध होते हैं वह बहुत बड़ा धिनौना अपराध माना जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, उनमें भी सन् 2001 में 44 मुकदमों की कमी आई है। यह 27.67 प्रतिशत की कमी बनती है। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर रेनुका, सुटाला वगैरह का जिक्र नहीं करूंगा, पुरानी बातों को यहां पर जिक्र नहीं करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर पुलिस वालों को प्रोत्साहन देने के लिए और आधुनिकीकरण करने के लिए हमने नई गाड़ीयां खरीदी हैं, नए वायरलैस सैट्स खरीदे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमने पुलिस लाइन भी बनाई है ताकि पुलिस के लोग वहां पर अच्छी तरह से रह सकें। उपाध्यक्ष महोदय, 1987 से 1991 तक जब चौधरी देवी लाल जी की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी उस बात के लिए आज हिसार में पुलिस लाइन इस बात के लिए गवाह है। हिसार में पुरानी पुलिस लाइन जरजर हालत में पड़ी हुई थी और वहां पर 15-20 सिपाही ही रह सकते थे। उस पुलिस लाइन को वहां से हटाकर करने का, हुड्डा को इसको डिवैल्प करने का और उसके बदले में दूसरी

पुलिस लाइन बनाने का फैसला चौधरी ओम प्रकाश जी की सरकार ने लिया। आज वहां पर 700 रहने के क्वार्टर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज ऐतिहासिक में ऐसी पुलिस लाइन नहीं है इसके इलावा वहां पर पुलिस वालों के बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल भी खोला है। ऐसा स्कूल आपको ऐतिहासिक में पुलिस लाइन के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि जो सिपाही पहल सिपाही की पोस्ट पर ही रिटायर हो जाते थे उनके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी को दाद देना चाहता हूँ क्योंकि मुख्य मंत्री जी के पास गृह विभाग भी है तो इन्होंने उन सिपाहियों का मनोबल बढ़ाने के लिए यह किया है कि जो सिपाही, सिपाही के पद पर 16 साल तक की सर्विस पूरी कर लेगा उसको हवलदार बना दिया जायेगा। यह निर्णय मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में इस सरकार ने लिया है ताकि एक सराहनीय कार्य है और कइयों को तो हवलदार बना भी दिया है। इसी तरह से पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए मुठभेड़ में भागीदारी करने वाले पुलिस वालों के लिए पांच लाख रुपये आकर घायल होने वालों के लिए तीन लाख रुपये देने का प्रावधान सरकार ने किया है ताकि वे हिम्मत से लड़ सकें। इसी तरह से पुलिस कर्मचारियों की सलारान मनी को दूगने से तिगुना कर दिया गया है। इसी प्रकार से कमांडो की ड्राईट भी इस रुपये से बढ़ाकर बीस रुपये की गयी है। वर्दी भते को भी दुगुना दिया गया है। पुलिस कर्मचारियों को अच्छा प्रोत्साहन देने के लिए भोंडसी में 320 एकड़ जमीन पर एक प्रोत्साहन केन्द्र खोला जा रहा है। इसी

तरह से आधुनिकीकरण के लिए 2001-2002 में 51 करोड़ और 37 लाख रुपये का प्रावधान योजनागत खर्च में रखा गया है। डिप्टी स्पीकर सर, इसके अलावा भायद जय प्रकाश जी ने सदन में झज्जर कोर्ट में गोली चलने का भी जिक्र कर दिया। झज्जर कोर्ट का जहां तक सवाल है वहां पर गोली चलाने वाले तीन बदमाश पथे। बहादूरगढ़ में इलैक्ट्रान के दौरान जो रमेश दलाल कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनका भाई इसमें शामिल था। (विधन) उनको भायद हुड्डा साहब ने टिकट दी होगी या भजन लाल जी ने टिकट दील होगी। डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें तीन नाम आये थे ये नाम हैं मीनू, राजेश, एवं धर्मेन्द्र। इनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है और धर्मेन्द्र अभी फरार है। यह अनुपगढ़, जींद के सरपंच का कातिल है और मीनू एवं राजेश ग्रामीण महिला के साथ बलात्कार करने के दोषी के रूप में धारा 376 में भी मुलजिम है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, यह रमेश दलाल का सगा भाई है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उनका भाई नहीं है बल्कि उनके चाचा का लड़का है। आप किस-किस के भाई का जिक्र करेंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हुड्डा साहब, इस बारे में नफे सिंह राठी से ज्यादा न तो मेरे को पता है और न आपको पता है। लेकिन वह रमेश दलाल का सगा भाई है। (विधन)

चौधरी नफे सिंह राठी : उपाध्यक्ष महोदय, वह मेरा हल्का है और मेरे खिलाफ उसने चुनाव लड़ा है इसलिए मैं उनके सारे परिवार को जानता हूँ। मीनू रमे । दलाल का सगा भाई है और धारा 376 का मुलजिम है जबकि राजे । और धर्मेन्द्र उसके चाचा के लड़के है। यह बात आप नोट कर लें। हुड्डा साहब ने तो इस मामले को लेकर वकीलों से हड़ताल भी करवाई थी लेकिन जब इनको पता लगा कि इसमें कांग्रेस के लोग भाामिल है तब इन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : रमे । दलाल का उससे कोई वासता नहीं है।

प्रो.सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब नफे सिंह जी ने इस बारे में बता दिया है। इन्होंने मीनू का नाम तो ले ही लिया लेकिन मैं यहां पर नैना साहनी का जिक्र नहीं करना चाहता कि कांग्रेस ने क्या किया था। इसी तरह से जहा तक रेलू राम मडर की बात है यह केस कोर्ट के अन्दर चल रहा है इसलिए अगर इस बारे में यहां पर कोई टिप्पणी न ही की जाए तो ठीक होगा। इसी तरह से इन्होंने सिक्योरिटी का जिक्र कर दिया । पता नहीं क्यों इनको एक ही परिवार का फोबिया हो रहा है। कम से कम उनको तो इस बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहिए जिन्होंने उस थाली में खाया है उनको तो उसमे छेद नहीं करना चाहिए, उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। (विधन) जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है चौधरी भजन लाल जी भी मुख्य मंत्री रहे है और चौधरी

बंसीलाल जी भी जो इस समय नहीं है, मुख्य मंत्री रहे है, को सिक्योरिटी मिलती है। इसके लिए नॉर्म्ज बने हुए है। कोई एक्स कैटेगरी में आता है, कोई वाई कैटेगरी में आता है और कोई जैड कैटेगरी में आता है। विजिलेंस की इस बारे में रिपोर्ट आती है और उसी हिसाब से सिक्योरिटी दी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी को भी जैड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है। कल हम इ आए थे इसलिए मुझे इस बारे में पता है। इसी तरह से मेरा एक पड़ोसी कोईबिड्डा है वह भी जब कही जाता है तो पूरा लावल कर ले कर ही जाता है।

प्रो.सम्पत सिंह : जैड सिक्योरिटी के हिसाब से ही भजन लाल जी के पास 72 आदमी पोस्टेड है। इस पर हमें ऐतराज भी नहीं हैं अगर ये जैड कैटेगरी में आते है। तो इनको नॉर्म्ज के हिसाब से सिक्योरिटी मिलेगी ही। इसी तरह से चौधरी बंसीलाल जी के साथ भी 38 आदमी पोस्टेड है। (विधन)

श्री उपाध्यक्ष : भजन लाल जी, मुझे तो खतरा तब भी नहीं था जब पिछली सरकार के समय में बैंक लूटने पर मैंने आंदोलन किया था तो मेरे घर पर गोली चलायी गयी थी लेकिन मैंने तो तब भी परवाह नहीं की थी।

प्रो.सम्पत सिंह : चौधरी बंसी लाल जी के साथ 38 आदमी सिक्योरिटी में है। सिक्योरिटी नॉर्म्ज के हिसाब से मिलती

है, इंटैलीजेंस की रिपोर्ट पर मिलती है। सभी एम.एल.एज. को दो-दो गनमैन मिले हुए हैं। बरना ऐसा वक्त भी होता था कि कोई गनमैन होता ही नहीं था। डिप्टी स्पीकर सर, सिक्कोरिटी एंगल से जो सिक्कोरिटी रिस्क होती है उसके हिसाब से सिक्कोरिटी दी जाती है कल को किसी पर कोई हमला हो जाए और किसी की जान चली जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। सरकार की जिम्मेदारी आएगी।(विधन).

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आपका बस चले तो पंजाब की तरह हर विधायक को एक-एक टाटा सूमो दिलवा दें।

प्रो.सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से सिरसा जिले का जिक्र किया गया उसमें सारे के सारे ठेके व उपठेके नियम के अनुसार दिए गए। कैथल जिले के ठेकेदारों से वसूली की बात आई इस पर कार्यवाही चल रही है। इसी तरह से अभी भादी लाल बत्रा जी ने जिक्र किया था। (विधन)

कैप्टन अजय सिंह : जोगिन्दर कौर के बारे में भी बताएं।

प्रो.सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वह भी कार्यवाही कोर्ट में चल रही है अगर मैं एक-एक केस के बारे में बताऊंगा तो सदन का काफी समय जाया होगा। अगर लीडर ऑफ दि अपोजी उन इजाजत दें तो पुराना सरार बता दूं।

श्री उपाध्यक्ष : सम्पत सिंह जी, प्लीज आप कंक्लूड करें।

प्रो.सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, सदन में हैल्थ के बारे में अभी जिक्र किया गया था, दवाइयों के बारे में जिक्र किया गया था। सरकार इस बारे में पूरी तरह से केयरफुल है। धर्मवीर जी ने पानी के बारे में कह दिया। हम बाकायदा पानी बराबर देते हैं यहां ड्रेनें बाढ़ का पानी निकाला करती थीं लेकिन हमने इन ड्रेनों में लोगों को पीने का पानी और सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध करवाया है। हुड्डा साहब ने पहले भी जिक्र किया था और धर्मवीर जी पानी के बारे में कह गए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2002–2003 के बजट के अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान(पुनरारम्भ)

वित्त मंत्री (प्रो.सम्पत सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, एन.बी.के. लिंक के थ्रू भाखड़ा का पानी यमुना एरिया में दिया जाता है।

इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सारे प्रदेश में काम चल रहे हैं। इनको तो बजट का समर्थन करना चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं कि इरीगेशन के लिए बजट बढ़ाया जो दूसरी कटमोशन लाते हैं। साइन करने से पहले मेरे से पूछ तो लिया करे।

Mr. Deputy Speaker : Hon'bles members, Now voting on the Demands on the Budget for the year 2002-2003 will take place.

First, I will put the cut motions on the demands to the vote of the House and then I will put the demands to the vote of the House.

Demand Nos.1 & 2

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 7,64,84,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No. 1-Vidhan Sabha.

That a sum not exceeding Rs. 2,50,14,17,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for the year 2002-2003 in respect of charges under Demand no. 2 –General Administration.

The motion was carried.

Demand No. 3

Mr.Deputy Speaker: Now, I put cut motion No. 1 on demand No. 3 given by Cap.AjaySingh,Shri Jai Parkash and Shri Karan Singh Dalal to the vote of House.

Question is –

That Demand No 3 of Rs. 5,54,12,97,000/- for revenue expenditure and Rs. 27,00,00,000/- for capital expenditure on account of Home be reduced by Rs. 1,10,000/-.

The motion was lost.

That a sum not exceeding Rs. 5,54,12,97,000/- for revenue expenditure and Rs.27,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No. 3 – Home.

The motion was carried.

Demand No.4

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 1,60,07,07,000/- for revenue expenditure and Rs.5,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No. 4 - Recenue.

The motion was carried.

Demand No.5

Mr. Deputy Speaker: Now, I put cut motion No.2 on demand No. 5 given by Cap. Ajay Singh, Shri Shadi Lal Batra and Smt. Anita Yadav to the vote of the House.

Question is –

That Demand No. 5 of Rs. 45,15,52,000/- on account of Excise and Taxation be reduced by Rs. 1/-.

The motion was lost.

That a sum not exceeding Rs. 45,15,52,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No. 5 – Excise and Taxation.

The motion was carried.

Demand Nos.6 to 8

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 6,28,82,34,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No. 5- Finance.

That a sum not exceeding Rs.5,42,40,57,000 /- for revenue expenditure and Rs. 3,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003

in respect of charges under Demand No. 7- Other Administrative Services.

That a sum not exceeding Rs. 2,08,47,00,000/- for revenue expenditure and Rs. 3,82,68,40,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No. 8- Buildings and Roads.

The motion was carried.

Demand No.9

Mr.Deputy Speaker: Now, I put cut motion No.3 on demand No. 9 given by Cap.AjaySingh, and Shri Shadi Lal Batra to the vote of the House.

Question is -

That Demand No. 9 of Rs. 17,05,96,21,000/- on account of Education be reduced by Rs. 1000/-.

The motion was lost.

Mr.Deputy Speaker: Question is -

That a sum not exceeding Rs. 17,05,96,21,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No. 9- Education.

The motion was carried.

Demand No.10

Mr.Deputy Speaker: Now, I put cut motion No.4 on demand No. 10 given by Cap.AjaySingh, Shri Shadi Lal Batra and Shri Dan Singh to the vote of the House.

Question is -

That Demand No. 10 of Rs. 6,87,39,82,000/- for revenue expenditure and Rs. 1,60,61,00,000/- for capital expenditure on account of Medical and Public Health be reduced by Rs.1/-.

The motion was lost.

Mr.Deputy Speaker: Question is -

That a sum not exceeding Rs. 6,87,39,82,000/- for revenue expenditure and Rs.1,60,61,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No. 10 - Medical and Public Health.

The motion was carried.

Demand No.11

Mr.Deputy Speaker: Now, I put cut motion No.5 on demand No. 11 given by Cap.AjaySingh, and Shri Shadi Lal Batra to the vote of the House.

Question is -

That Demand No. 11 of Rs. 41,05,72,000/- on account of Urban Development be reduced by Rs. 2/-.

The motion was lost.

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 41,05,72,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No.11- Urban Development.

The motion was carried.

Demand No.12 to 14

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 56,87,25,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No.12 Labour and Employment.

That a sum not exceeding Rs. 5,02,84,99,000/- for revenue expenditure and Rs.45,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No.13- Social and Rehabilitation.

That a sum not exceeding Rs. 24,09,35,000/- for revenue expenditure and Rs.14,61,47,93,000/- for capital

expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No.14- Food and Supplies.

The motion was carried.

Demand No.15

Mr.Deputy Speaker: Now, I put cut motion No.6 on demand No. 15 given by Cap.AjaySingh, Shri Dharamvir, Shri Karan Singh Dalal and Narender Singh to the vote of the House.

Question is –

(i)That Demand No. 15 of Rs. 14,09,93,00,000/- for revenue expenditure and Rs. 3,25,00,00,000/- for capital expenditure on account of Irrigation be reduced by Rs. 2/-.

The motion was lost.

Mr.Deputy Speaker: Now, I put another cut motion No.7 on demand No. 15 given by Shri Karan Singh Dalal and Shri Jagjit Singh to the vote of the House.

Question is –

(ii) That Demand No. 15 of Rs.14,09,93,00,000/- for revenue expenditure and Rs. 3,25,00,00,000/- for capital expenditure on account of Irrigation be reduced by Rs.1/-.

The motion was lost.

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 14,09,93,00,000/- for revenue expenditure and Rs.3,25,00,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No.15 –Irrigation.

The motion was carried.

Demand No.16

Mr.Deputy Speaker: Now, I put cut motion No.8 on demand No. 16 given by Cap.AjaySingh and Shri Dharambir to the vote of the House.

Question is –

That Demand No. 16 of Rs.35,72,58,000/- for revenue expenditure and Rs. 1,68,10,000/- for capital expenditure on account of Industries be reduced by Rs.1/-.

The motion was lost.

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 35,72,58,000/- for revenue expenditure and Rs.1,68,10,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No.16 – Industries.

The motion was carried.

Demand No.17

Mr.Deputy Speaker: Now, I put cut motion No.9 on demand No. 17 given by Cap.AjaySingh, Shri Karan Singh Dalal , and Shri Dharambir to the vote of the House.

Question is –

That Demand No. 17 of Rs. 2,95,51,00,000/-for revenue expenditure and Rs. 1,40,00,000/- for capital expenditure on account of Agriculture be reduced by Rs.1/-.

The motion was lost.

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 2,95,51,00,000/- for revenue expenditure and Rs.1,40,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No.17—Agriculture.

The motion was carried.

Demand No.18 to 25

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That a sum not exceeding Rs. 1,35,65,79,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No.18—Animal Husbandry.

That a sum not exceeding Rs. 12,34,60,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year

2002-2003 in respect of charges under Demand No.19—Fisheries.

That a sum not exceeding Rs. 75,10,75,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No.20—Forest.

That a sum not exceeding Rs. 1,26,64,53,000/- for revenue expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No.21—Community Development.

That a sum not exceeding Rs. 21,81,00,000/- for revenue expenditure and Rs.15,76,29,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No.22—Cooperation.

That a sum not exceeding Rs. 5,03,84,84,000/- for revenue expenditure and Rs.50,66,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No.23—Transport.

That a sum not exceeding Rs. 92,51,000/- for revenue expenditure and Rs.2,50,00,000/- for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No.24—Tourism.

That a sum not exceeding Rs. 2,21,12,71,000/-for capital expenditure be granted to the Governor to defray charges that will come in the course of payment for of the year 2002-2003 in respect of charges under Demand No.25—Loans and Advances by State Government.

The motion was carried.

विधान कार्य

1. दि.हरियाणा म्यूनिसिपल(अमेंडमेंट) बिल, 2002

Mr.Deputy Speaker: Now, the Minister of State for Urban Development will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 2002 and also move the motion for its consideration.

भाहरी विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाश गोयल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर पालिका सं गोधन विधेयक 2002 प्रस्तुत करता हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ --

कि विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr.Deputy Speaker: motion moved—

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

कैप्टन अजय सिंह(रिवाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो अमेंडमेंट ले कर आ रहे है, मैं समझता हूँकि सरकार ने ठीक काम

किया है कि स्वामियों द्वारा भवनों तथा भूमि पर भुगतान योग्य कर की प्रतिशतता साढ़े सात प्रसैंट से ढाई प्रसैंट कर दी गई है परन्तु अपर लिमिट तो अभी भी 15 प्रसैंट है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पर विचार करें और दूसरा आपने इसमें चौथी क्लॉज में लिख दिया है कि—

No land and building with in the controlled area shall, except with the permission of the Director and on payment of such conversion charges.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो क्लॉज डाली गई है यह क्लॉज कम्यूनिटी के लिए बड़ी घातक है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इसी कम्यूनिटी से बिलोंग करते हैं। इस लिए किसानों की जमीनों पर या तो सरकार कम्पनसे इन दे या कोई रिलीफ दे वरना किसान उसको बेच नहीं सकेगा और न ही उस पर कुछ बना सकेगा। यह सरकार अपने आप को किसानों की सरकार कहती है इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यह क्लॉज ठीक नहीं है। दूसरा जो हरियाणा अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमेंट बोर्ड बनाया गया है इस तरीके से सरकार आपने हाथों में म्यूनिसिपल बोडिज की पार्वस सैन्ट्रालाइज कर रही है। इससे म्यूनिसिपल बोडिज को नुकसान होगा और इससे फण्डस डायवर्ट होंगे इसलिए मेरा सुझाव है कि ये फण्डस डायवर्ट नहीं होने चाहिए। लाइसेंस फीस म्यूनिसिपल बोडिज में ही रहनी चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा(किलोई) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कप्तान साहब ने कहा कि किसान उस जमीन को बेंच नहीं सकता और न लड़की की भाादी कर सकता है। इसलिए सरकार को वह जमीन मार्किट वैल्यू पर ले लेनी चाहिए। इतनी आपन तो किसान पर छोड़ देनी चाहिए।

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr.Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That Clause-2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That Clause-3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That Clause-4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-5

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That Clause-5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-6

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That Clause-6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of
the Bill.

The motion was carried.

Speaker: Question is—

Title

Mr.Deputy Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr.Deputy Speaker: Now, the Minister of State for Urban development will move that the Bill be passed.

भाहरी विकास राज्य मंत्री(श्री सुभाश गोयल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि —

विधेयक पारित किया जाए।

Mr.Deputy Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr.Deputy Speaker: Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

2.दि पंजाब पेसेंजर एंड गुड्ज टैक्से अन(हरियाणा अमेंडमेंट)बिल,2002

Mr.Deputy Speaker: Now,Chief Minister will introduce the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) Bill,2002 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, on behalf of Hon'ble Chief minister, I beg to introduce the Punjab Passengers and goods Taxation (Haryana Amendment) Bill,2002.

Sir,I also beg to move—

That the Punjab Passengers and goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr.Deputy Speaker: Motion moved—

That the Punjab Passengers and goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That the Punjab Passengers and goods Taxation (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr.Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause-2

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That Clause-2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That Clause-3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

That Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस का समय 15 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

विधान कार्य

2.दि पंजाब पेसेंजर्ज एंड गुड्ज टैक्से ान(हरियाणा अमेंडमेंट)बिल 2002

Mr.Deputy Speaker (Prof. Sampat Singh) : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr.Deputy Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr.Deputy Speaker: Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

3. दि ईस्ट पंजाब वार अवार्डज(हरियाणा अमेंडमेंट)बिल 2002

Mr.Deputy Speaker: Now, the Revenue Minister will introduce the East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill,2002.

Mr.Deputy Speaker: Motion moved—

That the East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That the East Punjab War Awards (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr.Deputy Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That Clause-2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That Clause-1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr.Deputy Speaker: Question is –

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker: Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Now the revenue Minister will move that the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Deputy Speaker: Question is –

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

***14.03 hrs.**

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Wednesday, the 20th March, 2002)